हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 फरवरी, 2009

खण्ड – 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 17 फरवरी, 2009

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)1
वर्ष 2009–10 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)24
मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा–	(7)28

वर्ष 2009–10 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)27
बैठक का समय बढ़ाना	(7)77
वर्ष 2010 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्म)	(7)78
विधान कार्य–	(7)85
(1) दि पंजाव शिडयूल्ड रोड्स एण्ड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रक्शन आफ अनरेगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2009	
बैठक का समय बढ़ाना	(7)87
विधान कार्य–(पुनरारम्भ)	(7)87
(2) दि हरियाणा लैजिस्तेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड अलाउसिज (अमैंडमैंट) बिल, 2008	
(3) दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी शराइन (अमैंडमैंट) बिल, 2009	
सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन	(7)90

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 17 फरवरी, 2009

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ में प्रातः 8.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now question hour.

Electricity Connections in the name of Women

***1093. Dr. Sushil Indora:** Will the Power Minister be pleased to state whether the Government has formulated any special scheme for releasing the electricity connections in the name of women in doemstic, agricultural and industrial sector ; if so, the name of such scheme together with number of beneficiaries ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): No, Sir.

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महिला वर्गा को प्रोत्साहन देने के लिए और विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार ने कोई ऐसी घोषणा की थी कि हम उनको बिजली के रेट में या कोई और कन्सैशन देंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त ने वाजिब फरमाया। 18.12.2005 को हमने निर्णय लिया था कि जो भी महिला हरियाण में बिजली का डोमैस्टिक कनैक्शन लेगी उसको 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसका अच्छा परिणाम भी आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि 2005 में जब हमने यह स्कीम अनाउंस की थी उस समय कुल महिला उपभोक्ता 29316 थी जो कि अब बढ़कर दुगनी हो गई है यानि अब यह संख्या 55871 है। उनको इस स्कीम का कुल फायदा जो आज तक पहुंचा है वह है 75 लाख छत हजार रुपये। अध्यक्ष महोदय, बिजली के अलावा भी भिन्न–भिन्न विभागों में अनेकों स्कीमें हरियाणा सरकार ने लागू की हैं जिनकी व्याख्या मुखतलिफ मंत्रीगण इस सदन को बता चुके हैं।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जबाव में बताया हे कि 'नो सर' और अभी यह मान रहे हैं कि हमने घोषणा की और उसको लागू किया यानि कि योजना तो हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने स्पष्ट लिखा है कि 'नो सर'। अध्यक्ष महोदय, ये गुमराह करने वाला जो जबाव दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा जवाब क्यों दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): आपने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जबाब ठीक है।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मैंने योजना के बारे में पूछा है। घोषणा के बाद योजना बनाई जाती है।

श्री अध्यक्षः इन्दौरा जी, आपने जो सवाल पूछा था उसका जबाब है 'नो सर'। फिर आपने कहा कि कोई घोषणा की है तो उसके बारे में मंत्री जी ने बताया है। A Minister can amend his reply on the floor of the House at any time.

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I have not amended my reply. My learned friend, Dr. Sushil Indora ji, has been in Parliament. He has been a learned Member of the Assembly and he is also deputy leader of his party. He should understand what question has to frame. I have answered the question that he has asked and since he asks me a supplementary, I will also give the answer. If he does not know how to frame the question properly what can I do ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडाः इन्दौरा साहब, आपका सवाल बिल्कुल सीधा सा था कि releasing of electricity connections उसका जवाब 'नो सर' ही आएगा। आपने सप्लीमैंट्री पूछनी हो तो पूछ लो।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब दिया है 'नो सर। मैं कहना चाहूंगा कि घुमा फिराकार जवाब देना इनकी आदत सी है।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, आप गलत बात न करें। आपसे पूछा गया कि डॉ० साहब आप बाम्बे जा रहे हैं तो आपने कहा कि

मैं बाम्बे जा रहा हूं। आपसे फिर पूछा गया कि आप उधर जा रहे है तौ आपने कहा कि मैं उधर जा रहा हू तो यह तो कोई बात नहीं हुई कि आप इधर भी जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं। पहले आप कुछ पूछते हैं फिर कुछ पूछते हैं। आपके पास स्पैसीफिक क्यैश्चन हो तो आप being a educated man बताएं।

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि सरकार ने योजना बनाई कि 10 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति महिला को डोमैस्टिक कनैक्शन में लाभ दे रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये यह भी बता दें कि लाभार्थी कितने हैं।

श्री अध्यक्षः इन्दौरा जी, आप बैठें।

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमैंट्री है कि गांव में खासकर विद्युतीकरण कम होता है क्योंकि उनके पास आमदनी के सोर्सिज कम होते हैं। क्या सरकार गांवों में विद्युतीकरण स्कीम को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं के नाम से कोई ऐसी योजना बनाएगी ताकि गांवों में विद्युतीकरण हो सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे काबिल दोस्त की भावना को समझ गया हूं चाहे वे सही तरीके से प्रश्न न बना पाये हों। कई बार इनके प्रश्न कोई और लिखकर दे देता है ये तो केवल दस्तखत करके दे देते हैं, ऐसा कई बार होता है। लेकिन मैं इनकी भावना को समझता हूं। इनकी भावना सही है जिसकी मैं और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों तारीफ करते

हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यदि ये जवाब सुनना चाहते हें तो मैं जवाब दे देता हूं। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों स्कीम्ज बनाई हैं। जहां तक विद्युतीकरण की बात मेरे माननीय साथी ने की है तो इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 16.12.2005 को एक पत्र ईशू किया था जिसमें अनाउसमैंट की गई थी कि बिजली का डोमैस्टिक कनैक्शन महिला के नाम होने पर 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। इसके पीछे सरकार का लक्ष्य था कि खासतौर पर जो महिला उत्पीड़न ग्रामीण क्षेत्रों में होता है उसे रोका जाये और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं घर और बिजली के कनैक्शन की मालकिन बनें ताकि उनका घर में बेहतर हिस्सा हो। इस स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को फायदा हुआ है उसके आकड़े मैंने पहले बता दिये हैं, अब दोबारा बताता हूं कि कुल 55871 महिला उपभोक्ता इस समय प्रदेश में डोमैस्टिक कनैक्शन की हैं जिनको 75,65,000 रुपये का लाभ मिला है। इसके साथ–साथ डॉक्टर साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गऊशालाओं को 90 कनैक्शन दिए हुए हैं जिनको भी स्पेशल रेट का फायदा दिया गया है। इसके अतिरिक्त होर्टिकल्चर यूनिट्स और फिशरीज के कंज्यूमर्स को भी स्पेशल रेट का फायदा दिया गया है ताकि सामूहिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्र प्रगति करें। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र प्रगति करें इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार कटिबद्ध है। यही कारण है कि हरियाणा बनने के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने

इस प्रकार के कारगर कदम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उठाये

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर के कनैक्शन ट्यूबवैल्ज के दिए जाते हैं इनमें एक प्रोसीजर है कि पैसा पहले जमा करवा लिया जाता है लेकिन एक–एक साल और दो–दो साल बाद भी किसानों को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन नहीं मिलते।

श्री अध्यक्षः आप यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि पैसे जमा करवाने के कितने दिन बाद किसानों को टयूबवैल का कनैक्शन मिल जाता है।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, पैसे जमा करवाने के बाद भी सालों तक कनैक्शन नहीं मिलता। जबकि पैसे जमा करवाने के तुरंत बाद कनैक्शन मिल जाना चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी की चिंता वाजिब है और पहली बार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने कोशिश की कि एक सीमित समय के अंदर किसानों को टयूबवैल के कनैक्शन दिए जायें। मेरे साथी और सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 51 दिसम्बर, 2007 तक के ट्यूबवैल कनैक्शन क्लीयर कर दिए गए हैं और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण

निगम ने जिसमें आपका क्षेत्र भी आता है 2008 के मध्य तक के टयूबवैल के कनैक्शन क्लीयर कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की कटिबद्धता केवल एक आकड़े से साबित होती है कि इनकी सरकार के 6 साल के कार्यकाल के दौरान 52900 ट्यूबवैल कनैक्शन दिए गए इससे पता चलता है कि ये किसानों के हक को लेकर कितने लालायित थे और हमारी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान 62399 ट्यूबवैल कनैक्शन दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त और भी ट्यूबवैल कनैक्शन दिए जा रहे हैं ताकि आखरी छोर तक किसानों को बिजली मिल सके और वे अच्छी सिंचाई करके अच्छी फसल पैदा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह पृथक प्रश्न था फिर भी मैंने इसका जवाब दे दिया है लेकिन मेरे साथी कुछ और जानकारी चाहते हैं तो ये मुझे लिखकर दे दें तो मैं पूरी जानकारी इनको दे दूंगा।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। जो रुटीन में ट्यूबवैल कनैक्शन मिलते हैं वे तो चलते रहते हैं लेकिन तुरंत पैसे जमा करवाकर जो कनैक्शन दिए जाते हैं उनमें भी काफी समय लग जाता है ऐसा क्यों है?

श्री अध्यक्षः आपके सवाल का जवाब मंत्री जी ने दे दिया है इसलिए आप बैठें। श्री बलवंत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में एक ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए कितना सरचार्ज लिया जाता था और मौजूदा सरकार के समय में कितना सरचार्ज लिया जाता है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह पृथक प्रश्न है इस बारे में मेरे साथी लिखकर भिजवा दें मैं जबाब दे दूंगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केहर वाली और मातूवाली की ढाणियों में बिजली की बहुत समस्या है।

Mr. Speaker: It is not relevant.

Construction of building of Government Rajiv Gandhi College for Women, Bhiwani

***1070 Dr. Shiv Shankar Bhardwaj:** Will the Education Minister be pleased to state 'whether it is a fact that construction of building for Government Rajiv Gandhi College for Women, Bhiwani is delayed ; if so, the reason thereof ?

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, the construction is being done by PWD (B&R) Department, Haryana. The work is delayed due to site conditions. The main building is likely to be completed by 31.3.09.

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज: स्पीकर सर, मैं अपनी सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: भारद्वाज जी, आपके प्रश्न का जबाव आ चुका है।

डा० शिव शंकर भारद्वाजः स्पीकर सर, वह दूसरे कालेज का जबाव था।

श्री अध्यक्षः भारद्वाज जी, चाहे किसी भी कालेज के बारे में जबाव आया हो On the floor of the House the reply of this College has already been given. Now, next question please.

Development of Nangal Chaudhary as Model Village

***1045. Shri Radhey Shyam Sharma Amar:** Will the Chief Minister be pleased to state, 'Whether there is any proposal under consideration of the Government to develope the Nangal Chaudhary as Model Village?'

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): No sir,

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि नांगल चौधरी 100 गांवों का मुख्यालय है, नया विधान सभा हल्का बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपये उसके विकास के लिए दिये हैं। क्या माननीय मंत्री जी अपने जवाब के०पर पुनर्विचार करेंगे कि इतने बड़े मुख्यालय को आदर्श गांव बनाया जाये जैसे कि 'और सैकड़ों गांव हरियाणा प्रदेश में आदर्श गांव बना दिये हैं। यह मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार ने वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक नांगल चौधरी में तरक्की के विभिन्न कार्यों के लिए 77 ,26,800 रुपये दिये हैं। इसकी डिटेल्ड सूची मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय. इसके अलावा नांगल चौधरी ब्लॉक हैडक्वार्टर भी है, यहां पर कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर पहले से मौजूद है, यहां पर पुलिस स्टेशन है, सरकार का कालेज है, सब–तहसील है, सब–ट्रेजरी है, पोस्ट–ऑफिस है। माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से दक्षिणी हरियाणा के इस क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं इसलिए 77 ,26,800 रुपये की राशि हमने वहां पर दी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार प्रदेश के सभी इलाकों को एक नजर से देखती है और इसीलिए दक्षिणी हरियाणा के अन्दर खास तौर से नांगल चौधरी, नारनौल, महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी के ये इलाके जो वर्षों से पिछड़े हुए थे इनमें करोड़ों रुपये की राशि हमने वहां विकास कार्यों के लिए दी है। हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि आपके क्षेत्र के विकास में कोई कमी न आने दी जाये।

Suitable office premises for M.C., Gurgaon

***1114. Shri Dharambir Gauba:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to State whether there is any proposal to provide suitable office premises to the newly created Municipal Corporation, Gurgaon to accommodate the staff ?

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Yes Sir. proposal to provide suitable office premises to the newly created Municipal Corporation, Gurgaon is under consideration with HUDA.

श्री धर्मवीर गाबा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह हो सकता है कि जब तक म्यूनिसिपल कारपोरेशन के लिए कोई अन्य बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक कोई बैंगलो रैंट पर लेकर फिलहाल उसकी अकोमोडेट किया जाये। क्या माननीय मंत्री जी इसकी सैंक्शन करेंगे।

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर सर, यह म्युनिसिपल कारपोरेशन के लिए बिल्डिंग की बात चल रही है। मैं इसके लिए माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम मी इस बात के लिए वरिड हैं और हमने इसके लिए हुड्डा से सैक्टर उम्र और 57 में 2 बिल्डिंग ले ली हैं। हम उनकी रैनोवेशन करा रहे हैं। इन बिल्डिंग्स में हम काफी स्टाफ अकोमोडेट कर लेंगे। स्पीकर सर, मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि इतना सब होने के बावजूद भी हम समझते हें कि हमारी रिक्यायरमैंट पूरी नहीं होगी। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि कल ही इन्होंने हुडा को निर्देशित किया कि वह हमें ढाई किल्ला जमीन और दे दे ताकि हम उस पर जल्द से जल्द बिल्डिंग बना दें। इस वक्त जो सैक्टर 39 और 57 में बिल्डिंग्ज हैं इनके बावजूद भी पुरानी म्युनिसिपल बिल्डिंग में भी कुछ स्टाफ है। इसके अलावा कुछ

स्टाफ एस०ई० पब्लिक हेल्थ डिपार्टमैंट में शिफ्ट किया हुआ है। हमारा स्टाफ एक जगह तब इकट्ठा बैठ सकेगा जब हम नई जमीन लेकर उस पर बिल्डिंग बना देंगे और उसमें पूरा स्टाफ शिफ्ट कर देंगे।

श्री धर्मबीर गाबा: अध्यक्ष महोदय, आज कारपोरेशन को बने छ महीने हो गये हैं। 2 जून को कारपोरेशन बनी थी। जिस प्रकार से मंत्री जी बता रहे हैं कि कारपोरेशन का कुछ तो स्टाफ पब्लिक हैल्थ के दफ्तर में है और कुछ कहीं है। कारपोरेशन के ऑफिस से मतलब है सारे का सारा आफिस एक ही बिल्डिंग में होना चाहिए। सारे डिपटिमैंट्स चाहे वह इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट हो चाहे इनफोर्समैंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको एक बिल्डिंग में एकोमोडेट किया जाये। यह नहीं होना चाहिए कि कोई 59 सैक्टर में है कोई 42 सैक्टर में है। म्पूनिसिपल कारपोरेशन का कमिश्नर आज पब्लिक हैल्थ के रैस्ट हाउस में बैठा हे। क्या यह साख है हमारी?

श्री अध्यक्ष: वह बता तो दिया है जी। अगर स्पेस ही नहीं है तो कहीं न कहीं तो बैठना ही पड़ेगा।

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता समझ सकता हूँ लेकिन नई कारपोरेशन सीविक बाडी इतने बड़े पैमाने की बनी हे तो स्वाभाविक है उसकी जरूरत के मुताबिक हमारे पास पहले से तैयार कोई भी मैटीरियल बिल्डिंग

उपलब्ध नहीं थी। लेकिन उनको एकोमोडेशन दिलवाने के लिए एस०ई० पब्लिक हैल्थ के इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट की बिल्डिंग में हमने कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्वर–।।, डिप्टी कमिश्नर, म्यूनिसिपल काऊंसलर और चीफ इंजीनियरिंग और इन सबका स्टाफ एक जगह बैठाया है। बाकी का स्टाफ हमने पुरानी म्यूनिसिपल कमेटी की बिल्डिंग में ही रखा हुआ है। मैं पहले भी मान चुका हूँ कि हम भी चिंतित हैं कि सैग्रीगेट डिपार्टमैंट चल नहीं सकते लेकिन जल तक नई बिल्डिंग का इंतजाम नहीं हो रहा जाता तब तक हमारी मजबूरी है और कम से कम लोगों को जगह तो तय है कि यहां–यहां ये–ये आफिसर्ज बैठते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की बात में मैं केवल एक बात और जोड़ना चाहूंगा वैसे भी गाबा साहब शायद हमारे सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं। वहां पब्लिक हैल्थ का जो गैस्ट हाऊस है उसकी बिल्डिंग शायद सबसे अच्छी बिल्डिंग है जो मुख्य मंत्री जी की अनुमति से हमने बनाई थी। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का निर्देश आया कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के लिए वह बिल्डिंग चाहिए तो हमने फौरी तौर पर अपने दफ्तर पुरानी बिल्डिंग में रख कर उस बिल्डिंग का आधे से ज्यादा हिस्सा म्यूनिसिपल कारपोरेशन के लिए खाली कर दिया क्योंकि म्यूनिसिपल कारपोरेशन की हमारे से भी पहले प्राथमिकता है। मैं एक बार फिर माननीय सदस्य को सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा

कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे तो बाकी का दफ्तर भी हम म्यूनिसिपल कारपोरेशन के लिए देने के लिए तैयार हैं लेकिन म्यूनिसिपल कारपोरेशन के ऑप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्षः अब तो सैटिस्फाई हो गाबा साहब?

श्री धर्मवीर गाबाः ही सर, मैं सेटिस्फाई हूँ।

Proper Dranages system in Dadri City

***1105. Maj. Nirpender Singh Sangwan:** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that the floods during the last year monsoon has damaged/destroyed public as well as private property in Dadri city; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide proper drainage system in Dadri City?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Yes Sir. Though no Public property was damaged, 902 residential houses were partially damaged due to heavy rains during the last year monsoon. Out of the said houses, 21 houses were more than 25% damaged.

An estimate of Rs. 111.65 Lacs was approved by Flood Control Board during 2008-09 against which Rs. 20.00 lacs have been allocated for the construction of open drains in Dadri City.

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मंत्री

महोदय जी ने कहा कि पब्लिक प्रोपर्टी डैमेज नहीं हुई है। The Girls School in Dadri had more than 3 feet water and due to that a lot of class rooms have been damaged and these rooms have not been repaired yet. There is no drainage system in the city so far. The estimate of about Rs. 101.65 lacs was made before the monsoon and before this flood like situation came to Dadri and out of which only Rs. 20 lacs were allocated. I submit that there is no arrangement so far for the storm water.

Mr. Speaker: Sangwan ji, what is your specific question?

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवानः Sir, my specific question is that वे कहते हैं कि sewerage system cannot take place. मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि दादरी के लिए जब तक अलग से इसका स्टोर्म वाटर एण्ड ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तब तक दादरी का सुधार नहीं हो सकता है।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, Major Sahib has raised a pertinent question. Actually, as far as damage to properties is concerned, normally it is a matter that should have been addressed to Revenue Department but since Major Sahib has asked, we have taken the question and we have tried to collect information from all the departments. All the same, I want to bring one thing to the notice of the learned Member that this Government in four years for the first time in the history of Dadri has allocated so far Rs. 710.55 lacs for water supply and Rs. 780.10 lacs for sewerage system of Dadri. सर, समस्या दादरी में है और माननीय सदस्य की चिंता

वाजिब है। केवल हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में स्टोर्म वाटर ड्रेनेज और सीवरेज लाईन अक्सर इकट्ठे चलते हैं। स्पीकर सर, दादरी में पानी को बाहर ले जाकर उसके डिस्पोजल की भी समस्या है क्योंकि दादरी नैचुरल ग्रेडियेंट्स के०पर सिचुऐटिड नहीं है इस वजह से वहां पर पानी को निकाल कर कहां डालें यह भी एक कठिन समस्या है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं सिर्फ दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया था कि हरियाणा के 16 ऐसे छोटे शहर हैं जिनको आप सीवरेज, ड्रिकिंग वाटर, स्टोर्म वाटर और ड्रेनेज की पूरी सुविधा दें। 500 करोड़ रुपये की एक विशेष राशि हमें भारत सरकार देने वाली है, उस स्कीम के अन्दर दादरी भी शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषतौर पर दादरी को इसमें शामिल करवाया है और दूसरी बात यह है कि हमें यह उम्मीद है कि जब हमें यह पैसा मिल जाएगा तो हम 5० करोड़ रुपये के करीब की राशि तो अकेले दादरी शहर के लिए खर्चेंगे जिसमें से हमारी प्रपोजल के तहत हम एक सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट 28 करोड़ रुपये की लागत से लगाएंगे और जलापूर्ति के लिए 22.50 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। स्टोर्म वाटर ड्रेनेज का जहां तक सवाल है, इस बारे में मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें हमारी एक मदद करें। अब हम पानी को दादरी से बाहर ले जाते हैं और ओपन ड्रेनेज या साईड ड्रेन के अन्दर उस पानी को छोड़ दिया जाता है। अगर माननीय सदस्य एक–दो–तीन एकड़ जमीन दादरी के इमिजियेटली बाहर हमें

दिलवा दें तो हम कोशिश करेंगे कि जो स्टोर्म वाटर, ड्रेनेज का पानी है कम से कम जो पॉल्यूटिड पानी नहीं है उसको वहां हम इकट्ठा कर दें। वह पानी नैचुरल प्रोसैस से इवैपोरेट हो जाए या फिर अण्डर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के काम आ जाए या फिर पड़ौस के किसानों को सिंचाई के लिए दे दिया जाए, यह एक हल हो सकता है जिस पर हम गौर करेंगे। स्पीकर सर, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवानः स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने दादरी शहर पर हमेशा ही बहुत ध्यान दिया है जिसकी वजह से दादरी शहर का बहुत विकास हुआ है। इसके लिए जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा है मैं इस सारे आपरेशन में खुद मदद करके कोशिश करूंगा कि प्रशासन की चिन्ता दूर हो जाए।

श्रीमती अनीता यादवः स्पीकर सर, वैसे मंत्री जी ने जबाव दे ही दिया है लेकिन मुझे चिन्ता इस बात की हुई है कि दादरी शहर का स्पैसिफिक जिक्र किया गया है। हमारे कोडराली, मुण्ढाडा, नवादा, बिरहड तथा हमादल यह पांच गांव ऐसे हैं जहां बारिश के समय में पानी भर जाता है और फसल लगभग खराब हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या वे इन गांवों के लिए भी कोई उपाय करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग से जुडा हुआ नहीं है फिर भी माननीय सदस्या मुख्यमंत्री जी को लिख कर भिजवा दें तो हम इसका हल निकालने का अवश्य प्रयास करेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सत्र के दौरान मैंने क्यैश्चन भी किया था कि कलायत शहर काफी पुराना शहर है इसमें भी बाढ़ की वजह से और बरसात के पानी की वजह से शहर के चारों तरफ की बेशकीमती जमीन पर गंदा पानी भर जाता है। हमने काफी बार यह प्रयास किया है कि बाढ़ और बरसात का पानी जो वहां आता है और स्टोर्म वाटर को भी निकालने का कोई न कोई समाधान किया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की चिन्ता वाजिब है। माननीय सदस्या को हालांकि मालूम है फिर भी मैं आपकी अनुमति से इनको और सदन को बताना चाहूंगा कि अब जो 15 शहर हैं उनमें कलायत और सफीदों दोनों शहर हमने शामिल किये हैं जिसके लिए 500 करोड़ रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम केन्द्रीय सरकार से ले लेंगे। दूसरे अध्यक्ष महोदय, क्लायत में जैसे सीवरेज की व्यवस्था होगी हमने बजट में इसका प्रोवीजन भी किया हुआ है, जुलाना भी उसमें शामिल है क्योंकि आई०जी० साहब ने भी इस बारे में पूछा था। इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहूंगा कि कलायत में पहली बार पीने के पानी की

व्यवस्था करके 70 एल०पी०सी०डी० तक करने जा रहे हैं। तकरीबन 350 लाख रुपये का पहला और नया वाटर वर्क्स कलायत में चालू होगा। हम सभी गांवों में इस प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। इस बात को लेकर हम सजग हैं, चिन्तित हैं 'और इसका हल निकालेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1177

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री सोमवीर सिंह सदन में उपस्थित नही थे।)

Taking over of the Kapil Muni Mahila College at Kalayat

***1130. Smt. Geeta Bhukal:** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the "Kapil Muni Mahila College" of Kalayat?

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): No, Sir.

श्री अध्यक्षः गीता भुक्कल जी, आपके इस प्रश्न का जबाव आ चुका है। On the floor of the House, this question has already been replied.

श्रीमती गीता भुक्कलः स्पीकर सर, इस बारे में मैं सदन की जानकारी में कुछ बातें लाना चाहूंगी।

श्री अध्यक्षः आपने सवाल पूछा था और मंत्री जी ने उसका जबाव दे दिया है। अब आपने जो पूछना है उसको आप लिखकर दे देना।

तारांकित प्रश्न संख्या 1052

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Functioning of Incinerator at Government Hospital, Karnal

***1196. Smt. Sumita Singh:** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the incinerator for destroying the bio medical waste installed in year 1997 in the Government Hospital, Karnal has not been made functional; if so, the reasons thereof togetherwith the status of such incinerators installed in other Government Hospitals?

Power Minister (Shrl Randeep Singh Surjewala): No, Sir. The incinerator installed in the Government Hospital, Karnal in the year 1997 was functional till Dec., 2003. Operation was stopped due to change in Bio Medical Waste Rules, which warranted installation of double chambered incinerators. Same is the status in respect of other Govt. hospitals also.

श्रीमती सुमिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि यह सही है कि 1998 से 2003 तक इन्सीनेरेटर चला और उसके बाद

डी०जी०एच०एस० ने सिविल हॉस्पिटल करनाल को एक लैटर लिखा। पहले इस इन्सीनेरेटर को स्वयं सिविल हॉस्पिटल करनाल चला रहा था। सर, यह जो लैटर ईशू किया गया था, इसमें यह लिखा गया था कि यह इन्सीनेरेटर इंडिया वेस्ट एनर्जी लिमिटिड एक प्राईवेट कम्पनी को चलाने के लिए दिया गया और कुछ महीने के बाद उन्होंने बिजली के बिल जमा नहीं करवाए तथा फिर वह कम्पनी उसको बंद करके चली गई। उसके बाद पिछली सरकार ने काईनोक्स बैल्डिंग कैमिकल नामक भिवानी की कम्पनी को उस इन्सीनेरेटर को चलाने के लिए दे दिया और उस कम्पनी ने भी कुछ दिन इसको चलाया और बिजली का बिल नहीं दिया। फिर से यह इन्सीनेरेटर बंद हो गया। मैं यह पूछना चाहूंगी कि सिविल हॉस्पिटल करनाल के कर्मचारी जब अच्छे से इसको चला रहे थे और इस मशीनरी पर हमारा बहुत पैसा लगा हुआ था तो 2003–04 में ऐसा क्या हुआ कि इसको चलाने के लिए प्राईवेट कम्पनी को दे दिया गया। Who is responsible to give this machine to the private company and why it was given to the private company? What was the intention behind it? क्या आपने पता लगाया है कि किन कारणों से यह हुआ था? मंत्री जी ने अपने जबाव में यह कहा हे कि डबल चौम्बर के इन्सीनेरेटर होने चाहिएं। क्या ये जो इन्सीनेरेटर इतना खर्चा करने के बाद हमारे हॉस्पिटल में लगे हुए हैं. इनको सिंगल से डबल चौम्बर नहीं किया जा सकता।

10.00 बजे

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, यह जो बायो मैडिकल वेस्ट मैनेजमैंट और हैंडलिंग है, यह डिसाईड करते हैं कि किस प्रकार का इन्सीनेरेटर हम लगाएं। स्पीकर सर, रूल्ज की अमैंडमैंट के बाद हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो डायरैक्शन आई थी उसके अनुसार हमारे पास जो 14 इन्सीनेरेटर थे, वे सारे के सारे हमें बंद करने पड़े क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया था कि आप केवल डबल चौम्बर ही लगा सकते हैं। सर, यह बहुत ही लार्ज साईज का है। केवल एक हास्पिटल के लिए सिंगल चौम्बर काफी नहीं है, इसी वजह से सिंगल चौम्बर के सारे इन्सीनेरेटर बंद कर दिए गए थे। स्पीकर सर, सात विभिन्न प्राईवेट फर्म्ज हैं जिन्होंने ये इन्सीनेरेटर हरियाणा में लगाए हुए हैं अगर माननीय सदस्या चाहेंगी तो इनको मैं यह लिस्ट दे भी सकता हूं। स्पीकर सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि हाट सुप्रीम वेस्टेक इन्सीनेरेटर करनाल के भौडसी गाँव में लगा हुआ है। हम हर साल इसके लिए बाकायदा पैसा भी देते हैं। इस प्रकार से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सारे हरियाणा के अस्पताल जो ये 7 इन्सीनेरेटर हैं हमारे भी और सैक्टर्ज के भी तथा दूसरे जो इस प्रकार का बॉयो मैडिकल वेस्ट जहां से भी पैदा होता है, इन सबको देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन जहां निडल और सीरिज डिस्ट्राएड हैं वह हमने सी०एच०सी० के लैवल तक सब जगह लगा दिए हैं और उसके लिए हम तकरीबन हर साल 80 लाख रुपये की राशि भी देते हैं।

श्रीमती सुमिता सिंहः स्पीकर साहब, मैंने यह भी पूछा था कि जब सरकारी अस्पताल इन्सीनेरेटर को स्वयं चला रहे थे तो 2003 में भिवानी की एक प्राईवेट पार्टी को इसको क्यों चलाने के लिए दिया गया?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, जैसा जवाब में स्पष्ट तौर पर कहा गया हे कि बॉयो मैडिकल वेस्ट रूल्ज की अमैंडमैंट होने के बाद डबल चौम्बर्ड इन्सीनेरेटर लगाने जरूरी हो गए थे। डिपार्टमैंट का भी मानना था कि एक अस्पताल के लिए अकेला इन्सीनेरेटर काफी नहीं है। हमें उसके लिए ज्यादा बॉयो मैडिकल वेस्ट चाहिए इसलिए नीतिगत तौर पर एक प्राईवेट पार्टी को यह दिया गया और आज भी यह प्रक्रिया चल रही

श्रीमती सुमिता सिंहः सर, सरकारी अस्पताल वाले इन्सीनेरेटर को प्राईवेट कम्पनी क्यों चला रही थी ?

श्री अध्यक्षः ठीक है, आपके प्रश्न का जबाव आ गया है अब आप बैठें। अब अगला सवाल होगा।

डा० सीता रामः स्पीकर सर, इस प्रकार से जो प्राईवेट फर्म्ज को यह वेस्ट मैनेजमैंट का ठेका दिया गया है।

श्री अध्यक्षः डॉक्टर सीता राम जी, मैंने आपको अगला सवाल पूछने के लिए कहा है न कि सप्लीमैंट्री पूछने के लिए।

डा० सीता रामः सर, मैं सप्लीमैंट्री भी पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्षः नहीं नहीं, आप अपना अगला सवाल पूछिए।

डा० सीता रामः ठीक है सर।

Constructlon of Kisan Rest House

***1145. Dr. Sita Ram:** Will the Agriculture Minister be pleased to state the date on which the Kisan Rest House was constructed in NewAnaz Mandi, Dabwali togetherwith the amount spent thereon alongwith the time by which it will be opened for the use of farmers ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha): Sir, Kisan Rest House in New Anaz Mandi, Dabwali was completed on 12-2-2002 with an expenditure of "s. 26,32,520/-. The Rest House is occupied by the Commission constituted by the Government to assess the quantum of compensation to the victims of fire tragedy at Dabwali since January, 2003. It will be opened for the farmers as and when it is vacated by the said Commission.

डा० सीता रामः स्पीकर साहब, यह रैस्ट हाउस डबवाली अग्निकांड के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन करने हेतु ऑनरेबल कमीशन को दिया गया था। लेकिन इस रैस्ट हाउस को इस कमीशन को देने के कारण वहां अनाज मंडी में किसानों को बड़ी भारी दिक्कत होती है। वहां पर कोई दूसरा रैस्ट हाउस भी नहीं है। काफी लम्बे समय से यह रैस्ट हाउस उस कमीशन को दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि सरकार उनके लिए कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था करके दे ताकि किसानों को वहां पर

दिक्कत न हो। सर, अब तो उस कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसका काम भी खत्म हो चुका है। वहां पर वह कमीशन पांच–छः महीने में एक आध बार ही सुनने के लिए आता है इसलिए कितने महीनों तक वह रैस्ट हाउस बंद ही पड़ा रहता है। अगर सरकार उसको किसानों के पूज के लिए खुलवा दे तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर सर, जब तक कमीशन वाले उस रैस्ट हाउस को हमें हैंड ओवर नहीं करते तब तक वह रैस्ट हाउस उनके पास ही रहेगा। सर, उस वक्त कमीशन को वह बिल्डिंग इन्होंने ही दी थी। ये इस बारे में उस वक्त ही सोचते कि किसान को किस तरह से इसका आल्टरनेटिव देना है लेकिन इन्होंने उस वक्त कुछ नहीं सोचा। सर, कमीशन की रिपोर्ट अब पूरी होने वाली है and thereafter the building will be handed over to us.

डॉ० सीता रामः स्पीकर साहब, मेरा भी कहना यही है कि उस कमीशन की रिपोर्ट अब पूरी हो चुकी है इसलिए अब तो उस रैस्ट हाउस को किसानों को दे दिया जाए।

Mr. Speaker: As and when the report is completed, the building will be handed over to the Government.

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर साहब, पहले कमीशन हमें उस रैस्ट हाउस को हैंड ओवर तो करें। जब वह कमीशन हमें

उसका हैंड ओवर दे देगा तो उसको हम किसानों के लिए ओपन कर देंगे।

Release of Funds for C.H.C., Julana

***1135. Shri Sher Singh:** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the funds will be released to set up CHC at Juliana ?

Power Mlnister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, the matter is under active consideration of the Government.

आई०जी० शेर सिंहः स्पीकर साहब, 2006 में यह मामला इन प्रिंसिपल ऐग्री हो गया था और म्यूनिसिपल कमेटी ने चार एकड़ जमीन भी दे दी है लेकिन अभी तक यह केस कहां है, किधर है यह पता नहीं लग रहा है। क्या मंत्री महोदय इस साल उसकी सैंक्शन दे देंगे? अगर इस साल इसकी सैंक्शन देना संभव नहीं है तो अगले साल तो हर हालत में इसकी सैंक्शन मिलनी ही चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इनकी चिंता वाजिब है और यह सच है कि 2 अप्रैल, 2006 को मुख्यमंत्री जी वहां गए थे उन्होंने कहा कि 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दें तो हम वहां पर कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर बना देंगे। वैसे सी०एच०सी० वहां अभी भी चल रही है लेकिन जिस गवर्नमैंट बिल्डिंग में वह

चल रही है वह बिल्कुल टूटी हुई है और सफिशिएंट नहीं हे। वहां की नगरपालिका ने 10 जनवरी, 2007 को 11 महीने के बाद पहली बार जमीन देने के लिए प्रस्ताव दिया। नगरपालिका ने लगभग साढ़े दस महीने की देरी चार एकड़ जमीन देने में कर दी। नगरपालिका ने दिनांक 11.8.08 को हैल्थ डिपार्टमैंट को अंडर अर्बन लोकल बाडीज जमीन ट्रांसफर करने के लिए चिट्ठी लिखी और साथ में एक शर्त भी लगा दी। सर, अक्सर हैल्थ डिपार्टमैंट जमीन फी लेता है लेकिन नगरपालिका ने शर्त लगा दी और प्रस्ताव करके भेजा है कि हमें जमीन का मुआवजा भी दीजिए। हमें इस चार एकड़ जमीन के मुआवजे के रूप में 22 लाख रुपये चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दो तीन केसिज इस प्रकार के और हें, एक तो०चाना का है और एक सिमिलर केस जुलाना का भी है। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्णय लिया है कि हम इनको विशेष तौर पर मुआवजे की राशि भी देंगे और अगले 2–4 महीने के अंदर प्रयास करके यह काम चालू करवा देंगे।

मुख्यमंत्री (जी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): आई०जी० साहब, अब तो ठीक है।

आई०जी० शेर सिंहः मुख्यमंत्री जी, जी हां, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न संख्या 1162

(इस समय माननीय सदस्या श्रीमती राजरानी पूनम सदन में उपस्थित नहीं थी इसलिए यह प्रश्न पूल नहीं जा उस।)

Development of Residential Area

***1154. Shri Mahender Partap Singh:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the residential areas have developed beyond the phirni of all the villages falling under the Faridabad Municipal Corporation and which is considered unauthorized by the Corporation ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop the said residential areas ; if so, the scheme under which the funds will be provided for it ?

शहरी विकास मैत्री (श्री ए०सी० चौधरी):

(क) हां श्रीमान् जी।

(ख) माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 1006/2007 तथा 17002/2006 में ऐसी कालोनियों को नियमित करने बारे लगाई गई रोक के दृष्टिगत ऐसी कालोनियों का विकास नहीं किया जा सकता।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जबाव के 'क' पार्ट में मंत्री जी ने हां की है और मंत्री जी ने पहली बार हां की है।

पिछले सवाल का मैं जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन सवाल के दूसरे पार्ट के जबाव में कह दिया कि पंजाब हाई कोर्ट का कोई फैसला अनअथोराइज्ड कालोनीज के विषय में है। मंत्री जी ने माना है कि यह अनअथोराइज्ड कालोनीज की परिभाषा में नहीं आता। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक अनअथोराइच्छ कालोनीज जो म्यूनिसिपल कार्पोरशन से विशेष तौर से बाहर बनी हैं, यह फैसला उन पर लागू होता है। फरीदाबाद में ग्राम पंचायत में तकरीबन 18–20 गांव हें जो निगम के अन्तर्गत आते हैं और उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष कृपा की है और समुचित तौर पर फरीदाबाद के विकास को एक बार फिर नये आयाम देने का प्रयास किया है। जो 20 गांव निगम के अंदर हैं जहां तोषी आबादी है उनके गांवों की फिरनी को 40–50 साल से बढ़ाया नहीं गया था। ये गांव की वह आबादी है जो गांव के लोगों ने ही अपने चारों तरफ बसायी है वहां अगर डिवैल्पमैंट नहीं होगी तो फिर कैसे समग्र विकास कर पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए पूछना चाहूंगा कि यह कालोनियां हाईकोर्ट के दायरे में नहीं आ सकतीं, इसको फिर से देखें ये बहुत बड़े गांव हैं केवल 4–5 गांवों को छोड़कर हुडा के एरिया में जो आ गए हैं उनको तो डिवैल्प कर दिया गया है लेकिन बाकी गांवों को डिवैल्प नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि बाकी के गांवों को भी चाहे किसी भी निधि से लें, चाहे स्लम डिवैल्प करने की निधि से लें या चाहे ग्रामीण विकास निधि से लें, इनको भी डिवैल्प कराएं, नहीं तो फरीदाबाद की डिवैल्पमैंट नहीं

हो सकेगी। **श्री ए०सी० चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी का ध्यान उनके प्रश्न की ओर ही आकर्षित करूं कि इन्होंने कहा है कि फरीदाबाद नगर निगम के अधीन पड़ने वाले जो गाँव निगम में आ गए हैं तो वह कार्पोरेशन का एक हिस्सा हो चुके हें उन्हें गांव नहीं माना जा सकता। उस लिहाज से कार्पोरेशन के अंदर 51 ऐसी कालोनीज हैं जो ऐक्सटैंशन सैंटर्स के तौर पर बाद में बनी हैं लेकिन ऐपूव्ड नहीं हैं। हम लोग इस बारे में कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का काफी समय लिया और इसके बारे में हुडा और अर्बन लोकल बाडीज महकमे के अधिकारियों की एक कमेटी प्रिंसीपल सैक्रेटरी टू सी०एम० की अध्यक्षता में बना दी है जो आज इस बात के लिए गौर करेगी कि किस तरीके से हम अर्बन लोकल बॉडीज को इम्पावरमैंट दें वह कमेटी ही आगे चल कर के एक्ट में कोई एमैंडमैंट करेगी। इसके बाद ही हम सभी सदस्यों को चिन्ता से मुक्त कर सकेंगे। यह हमारा दायित्व है कि हम हर एक नागरिक को सिविक एमेनिटीज दें लेकिन जब हाईकोर्ट के आर्डर आ जाते हैं तो हमारे हाथ बंध जाते हें। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई न कोई कंक्रीट प्रोपोजल आज की मीटिंग में निकल जायेगी। **श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः** अध्यक्ष महोदय, में माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि आज फिर एक बार इस मामले को दिखवा लें। एक मामला पहले भी एक कालोनी के विषय में आया था कि हाईकोर्ट की अड़चन आ रही है तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा विभाग को आदेश दिए

कि आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर देखिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है। उस समय वही बात साबित हुई जो हमने शंका जाहिर की थी। इसलिए मैं मंत्री जी से एक बार फिर आग्रह कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश तो बहुत पुराना है। इससे पहले म्यूनिसिपल कारपोरेशन में जो माक आ गये हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। 51 कालोनीज गांवों में हैं जो आज से 20–30–40 साल पहले कारपोरेशन एरिया में आ गये थे इसलिए वह आदेश इस पर लागू नहीं होता। इससे पहले भी दूसरी निधियों से पैसा उन एरियाज के गांवों में खर्च होता रहा हे। इसलिए उस समय हाई कोर्ट के आर्डर कहां चले गये थे? अगर पहले भी ऐसा हुआ है तो इसका मतलब हे कि वह भी गैर कानूनी हुआ है। क्या अब उसमें इसको डिवैल्प नहीं कर सकते?

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आज की मीटिंग में कोई फैसला हो जाएगा तो उसके बाद जो कारपोरेशन के अन्दर गाँव आये हुए हैं उनको गाँव माना जा सकता है और उन गाँवों को सुविधा दी जा सकती है लेकिन मेरे दिमाग में अभी तो कोई बात अपील नहीं करती है। स्पीकर साहब, आज की मीटिंग में यह फैसला हो जायेगा कि हम इम्पावरमैंट के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं? उसके लिए एग्जामिन हम कर लेंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जबाव नहीं आया है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया कि आज की मीटिंग इस बारे में हो रही है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में लीगली एग्जामिन कर लेगी और जो भी मुनासिब होगा उसी हिसाब से कर लिया जायेगा।

Release of New Tubewell connectlons

***1168. Shri Tejendra Pal Slngh Mann:** Will the Power Minister be pleased to state whether the Government has any plan to release new tubewell connections applied for after 31-12-2007 ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Power Utilities release tubewell connections on an on-going basis as per seniority of applicants. As per current position for release of connections the cut off date in respect of UHBVN is 31.12.2007 and 30.11.2008 in respect of DHBVN. This date is revised from time to time depending upon the progress of release of tubewell connections. However, the concept of cut off date does not apply to applicants opting for the Self Execution Scheme. As per HERO guidelines, the connections under Self Execution Scheme are released as and when the applicants complete the installation work.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, कैथल जिले में खास तौर पर पाई हल्के में सब सॉयल वाटर होता था परन्तु सबमर्सीबल टयूबवैल्ज लगने के बाद उस हल्के के अन्दर मीठा

पानी आ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 31.12.2009 को लगभग कनैक्शन पूरे हो चुके हैं। इससे एग्रीकल्चर प्रोडैक्टिविटी बढ़ने के चान्स हो गये हैं। इसकी अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य के प्रश्न के जबाव में मैंने बता दिया है कि पिछले चार वर्षों के मौजूदा सरकार के शासनकाल में कुल 82399 कनैक्शन रिलीज किए गये हैं जोकि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आलमोस्ट हम लेटैस्ट डेट तक लेकर आये हैं। जैसा मैंने दोनों उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा की डेटस बताई भी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कई इश्यूज उत्पन्न होते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दे रखे हैं कि किसान सबसे पहली प्राथमिकता है और गरीब आदमी सबसे पहली प्राथमिकता है हम प्रयास करेंगे कि और ज्यादा बिजली के कनैक्शन दे सकें। मैं मेरे काबिल और वरिष्ठ दोस्त को यह बताना चाहता हूं कि खास तौर से आपके जिले के लिए उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एच०वी०डी०एस० की स्कीम भी शुरू की है। सर, अगर मेरे आकड़े गलत नहीं हैं और जहां तक मुझे याद है तकरीबन 37 हजार टयूबवैल कनैक्शनंज आपके यहां हैं। सभी 57 हजार किसानों को 11 हजार वाट की लाईन ले जाकर उनको अपना–अपना टयूबवैल ट्रांसफार्मर देंगे ताकि एक–एक ट्रांसफार्मर से पहले जो 4–4 से 6–6 कनैक्शन दिए जाते थे उनसे किसानों को राहत मिल सके

और उससे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी की सुचारू बिजली मिलने में मदद मिल सके।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की बात बिलकुल सही है। सैग्रीगेशन भी लगभग हो गई। ये नई स्कीम भी लागू हो जाएगी। बिजली के मामले में रिवोल्यूशन हो रहा है। मेरे ही हल्के में 6 सब–स्टेशंज लगाए गए हैं लेकिन ये बिजली के कनैक्शन एक साल के लिए और दे दिए जाएं तो किसानों को फायदा होगा और प्रोडक्टिटिटी भी अच्छी होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम इतने पोटैंशियल है कि अभी हम बाजरा लगाते हैं फिर और कोई अच्छी फसल लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसे दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम की कनैक्यान देने की कट ऑफ डेट 30.11.09 है उसी प्रकार हमारे यहां भी अगर छ महीने के लिए ही ये कनैक्यान दे दिए जाएं तो हमारे यहां के लोगों का फायदा हो जाएगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा आगे तक कनैक्शन हम किसान को दे दे

तारांकित प्रश्न संख्या – 1188

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय उदस्थ श्री दिनेश कौशिक सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Widening of Roads

***1214. Shri Sahid a Khan:** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that there are frequent traffic jams on the N.H. 31-B from Sohna to Taoru and on the road from Nuh to Taoru due to heavy rush of traffic ; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the said roads to ease the flow of traffic ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Yes Sir, the road from Sohna to Taoru which is a part of NH-71B (and not NH-31B) is being widened except a small reach of 2.25 Kms where land acquisition is involved. As regards Nuh-Taoru road, the improvement of this stretch is part of widening and strengthening of Hodal-Nuh-Taoru-Pataudi-Pataudi road for which the work is in progress.

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सोहना पहाड़ पर जो सड़क है वह काफी पुराने समय से बनी हुई है लेकिन उसको आज तक चौड़ा नहीं किया गया। अब नैशनल अथोरिटी ने उस रोड को ले लिया है। 20—20, 30—30 टायर वाली गाड़ियां उस रोड पर चलती हैं। इस सड़क के मोड़ बहुत छोटे—छोटे हैं जिस कारण वहां हमेशा जाम लगा रहता है। यह जाम दो—दो तीन—तीन दिन तक लगातार लगा रहता है। अध्यक्ष महोदय, कम से कम जैसे भी हो किसी भी मशीन से उस सड़क की पहाड़ वाली साइड को चौड़ा किया जाए। यह रोड चौड़ा तो हो रहा है लेकिन इसमें गड्ढे बहुत ज्यादा हैं पिछले सैशन में भी मैंने इस बारे में सवाल

दिया था और तब मंत्री जी ने भी माना था कि यह रोड ठीक नहीं है। इस सड़क के टांके तक नहीं भरवाए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह नूंह की जो पहाड़ी सड़क है वह भी काफी छोटी है जिस कारण वहां पर भी जाम लगा रहता है। हमें नूंह और गुड़गांव दोनों साइड से तावडू के अंदर एंट्री करने में बड़ी मुश्किल हो रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, यह जो 71 बी रोड है इसकी 44 किलोमीटर तक वाइडनिग का वर्क हो रहा है। 16.15 करोड़ रुपये की लागत से यह काम चल रहा है। इसी प्रकार 44 किलोमीटर से लेकर 47 किलोमीटर तक और 48 किलोमीटर से लेकर 54 किलोमीटर जो कि सोहना तक है उसका काम भी 11.96 करोड़ रुपये की लागत से अण्डर प्रोसैस है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सही कहा है कि 2.50 किलोमीटर सड़क ऐसी है जो पहाड़ी एरिया में आती है उसकी वाइडनिंग के काम को हम इस साल जो कि वर्ष 2009–10 का बजट है उसमें ले रहे हैं। इसका लैंड ऐक्वीजिशन और वाइडनिंग का काम हम करेंगे। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि थोड़े से टुकड़े के कारण समस्या होती है और हम इसके लिए चिन्तित हैं। इस साल इस 2.25 किलोमीटर सड़क की लैंड एक्वीजिशन भी करेंगे और यह काम भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो इन्होंने होडल, नूह, तावडू और पटौदा–पटौदी रोड की है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष तौर पर

एन०सी०आर० के तहत इस सड़क कै लिए पैकेज दिलवाया है। 550 करोड़ रुपये की लागत से इस सड़क पर काम कर रहे हैं। इस सड़क पर 259.86 करोड़ रुपये की लागत से काम चल रहा है। इसके अलावा नूंह से तावहपटौदा–पटौदी सड़क पर भी एन०सी०आर० के तहत काम चल रहा है। अब तक हमने तकरीबन 24.78 लाख रुपये खर्च कर दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने भी देखा होगा कि वहां पर काफी मशीनें लग रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेवात का मैंने विशेष तौर पर ख्याल रखा है। मुख्यमंत्री महोदय ने भी मेवात का विशेष ख्याल रखा है। 550 करोड़ रुपये की लागत से हमने इनके यहां काम किए हैं। इनके हल्के में करीब 20 रोडस ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ली गई हैं।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पहाड़ चौड़ा करने के बारे में तो बताया ही नहीं कि इसको चौड़ा करेंगे या नहीं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको बता दिया है कि जो 2.25 किलोमीटर सड़क है हम उसकी वाइडनिग भी करेंगे और पहाड़ को तोड़कर चौड़ा भी करेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने कितना बड़ा कन्सैश्न

एक सैकेण्ड में खड़े होकर दे दिया कि पहाड़ तोड़कर इनके यहां सड़क बनाई जायेगी। हमारे देश को आजाद हुए 80 साल से अधिक हो गये लेकिन ऐसा आश्वासन कभी किसी ने नहीं दिया कि पहाड़ तोड़कर सड़क बनाई जायेगीं इसके लिए माननीय साथी को मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए और संसदीय कार्यप्रणाली की अनुपालना करनी चाहिए।

श्री अमीर चंद मक्कडः अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से मेरे हल्के की एक–दो सड़कें हैं जिनके बारे में पूछना चाहूंगा। एक सड़क लालपुरा से डाणी कतोपर–कुराणा तक की है जिसके बारे में हांसी के लोगों की बहुत पुरानी मांग है। यह सड़क कच्ची है इस पर पक्की सड़क बनाई जाये ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। दूसरी सड़क खरकडा वाया डहाणी केंदू से अनाज मण्डी तक की है जो आधी बनी हुई है। इसको भी मंत्री जी जल्दी से जल्दी बनवायें।

Mr. Speaker: Makkar Sahib, it is not possible. मक्कड साहब, आप अपना सवाल लिखकर भिजवा दें, मंत्री जी आपको जबाव दे देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1217

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम किशन फौजी सदनमें उपस्थितकी थे।)

ताराकिंत प्रश्न संख्या 1224

(यह प्रश्न स्व नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नरेश यादव सदन में उपस्थित नही थे।)

Breeding of Murrah Buffaloes

***1221. Shri Shamsher Singh Surjewala:** Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state whether it is a fact that Kaithal district is among the areas in Haryana where Murrah Buffaloes are being bred by the farmers and the landless people in large numbers ; if so, the steps taken by the Government to promote the breed of Murrah Buffaloes and other tattles in the said district during the last four years ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha): Sir, a statement is placed on the Table of the House.

Statement

Yes Sir. As per 18th Livestock Census (2008), total Murrah buffalo population in Kaithal district is 2,17,853 of which 2,27,681 are female. Following steps have been undertaken by the State Government for the improvement of the breed of Murrah Buffaloes:

- The Department of Animal Husbandry & Dairing, Haryana has a network of 2789 Veterinary Institutions to provide Veterinary care and animal breeding facilities to the livestock in the State. Out of this, 121 institutions exist in Kaithal district.

The Haryana Livestock Development Board has been constituted with a view to boost the genetic improvement of

livestock in the State. It is the State Implementing Agency of National Project for Cattle and Buffalo Breeding (100% Centrally Sponsored Scheme). Different breeding activities, starting from quality frozen semen production to doorstep A.I. services are carried out under this programme.

- To preserve, improve and multiply the quality Murrah germplasm, a novel programme of identifying top yielding Murrah buffaloes and giving incentive to the owners of such recorded animals is in operation for the last few years showing encouraging results. In the district of Kaithal, the number of top milk yielding Murrah buffaloes in the year 2004-05 was only 6 which has incresaed to 130 in the current year (2008-09).

- All the identified buffaloes are insured and 100% insurance premium in the case of Scheduled Castes and 75% in the case of general category farmers is borne by the Government. Similarly, Haryana is the first State to provide an insurance cover to Haryana cows and bullocks and 50% of the insurance premium in the case of general category farmers and 100% in the case of Scheduled Castes farmers is borne by the Government.

- Male calves born to these high yielding buffaloes are purchased by the Government and reared as future bulls for supply to the Gram Panchayat at subsidized rates.

- The topmost bulls categorized on the basis of dam yield are being maintained at the high-tech sperm stations (Frozen Semen Production Centres) for production of

semen.

- To promote indigenous cattle production and conservation, 252 registered Gaushalas in the State of which 11 are in Kaithal district are assisted from time to time through various State & Central agencies.

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जबाव में यह कहा है कि the Department of Animal Husbandry & Dairying has a network of 2789 Veterinary Institutions in the State और उनमें से 121 इन्स्टीच्यूशंज कैथल जिले में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 121 वैटनरी इन्हीच्यूट कैथल जिले में हैं वे कौन–कौन से गांव में हैं और उनका स्टेट्स क्या है? वे वैटरनरी डिस्पैंसरीज हैं या हॉस्पिटल हैं इस बारे में भी मंत्री जी पूरी जानकारी दें। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी को यह भी कहना चाहता हूं कि इन्हींने माना है कि कैथल जिले में बुफैलोज बहुत स्पैशल हैं। लेकिन बड़े दुःख कही बात है कि कैथल जिले में 6 बड़े–बड़े गांव हैं जिनकी आबादी 5 से 10 हजार के बीच है और उन छ गांवों में एक भी वैटरनरी हॉस्पिटल नहीं है, केवल डिस्पैंसरी बनी हुई हैं। जिनमें एक कर्मचारी होता है और वह भी शहर चला जाता है।

श्री अध्यक्षः वैटरनरी हास्पिटल्ज बनाने के कुछ नार्म्ज होते हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः सर, ये गांव सारे नार्म्ज पूरे करते हैं। मंत्री जी कृपा बतायें कि कैथल जिले में कहां–कहां वैटरनरी डिस्पैंसरीज हैं और कहां–कहां हास्पिटल्ज हैं तथा उनका स्टेट्स क्या है?

सरदार एच०एस० चट्ठाः अध्यक्ष महोदय, कैथल जिले मैं गुहला, अंदरावली, बुढाखेडा, सीवन, भागल, कैथल, क्योड़क, बाबा लदाना, बाढडा, डोर आदि गांवों में वैटरनरी हॉस्पिटल हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः सर, बाढ्डा में हॉस्पिटल नहीं है।

सरदार एच०एस० चट्ठाः अध्यक्ष महोदय, वहां हॉस्पिटल है। There are 40 veterinary' hospitals and 50 veterinary dispensaries.

श्री अध्यक्षः अब अपग्रेड हो गये होंगे आपको जानकारी नहीं होगी।

सरदार एच०एस० चट्ठाः सर, इनके अलावा अब हम और भी हास्पिटल बनायेंगे। आज के दिन हरियाणा में हर तीसरा गांव या तो वैटरनरी हॉस्पिटल है या डिस्पैंसरी है और ऐसा ही माननीय साथी के कैथल जिले में है।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, लेकिन कैथल जिले में हर तीसरा गांव वैटरनरी हॉस्पिटल या डिस्पैंसरी नहीं दैन्य।

सरदार एच०एस० चट्ठाः अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार आई उस समय इनके यहां कैथल जिले में जो बैस्ट बुफैलोज थी उनकी संख्या 6 थी और अब इनके यहां 130 बैस्ट बुफैलोज हैं। इसका कारण यह है कि अब हमने बैस्ट सीमन दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि फरोजन सीमन दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब तो मुख्यमंत्री जी की कृपा से और भी नई टैक्नीक आ गई है कि हम सैक्साईजिंग भी करने लग गये हैं। अगर अब कोई ककी चाहता है तो ककी ही पैदा होगी और यदि कोई कटडा चाहता है तो कटडा ही पैदा होगा। स्पीकर साहब, अब टैक्नीक यहां तक पहुंच गई है इस बारे में आप को भी पता है।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कैथल जिले में 11 रजिस्टर्ड गऊशालाएं हैं जिनको सरकार ग्रांट देती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन गऊशालाओं को पिछले चार साल के दौरान कितनी ग्रांट दी गई है?

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इस दौरान कितनी ग्रांट दी गई उसकी फिगर मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है

लेकिन मैं विश्वास के साथ इतना जरूर कह सकता हूं कि जितनी ग्रांट हुड्डा साहब की सरकार ने दी है इससे पहले इतनी ग्रांट इनको किसी भी सरकार के समय में कभी नहीं मिली है।

श्री रमेश कुमार गुप्ताः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि मेरे हल्के में कुछ वैटरनरी हॉस्पिटल्ज की सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की जा चुकी है लेकिन उनका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंसे कि मेरे हल्के के मंजूर किये गये वैटरनरी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा।

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर सर, हमारी सरकार द्वारा 80 वैटरनरी हास्पिटल नये बनाये जाने प्रस्तावित हैं। ये 90 वैटरनरी हॉस्पिटल कहां–कहां पर बनाये जायेंगे अभी इस बात का फैसला नहीं हो पाया है। जब इस बात का फैसला हो जायेगा तभी हम इस बारे में कोई आगामी कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जबाव दिया कि हॉस्पिटल बन रहे हैं और पशुओं की केयर की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है कि डिस्पैंसरीज और हॉस्पिटल्ज में और खास तौर पर हमारे क्षेत्र में न तो वी०एल०डी०ए० हैं, न डॉक्टर हैं और न ही चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ है। डिस्पैंसरीज और

हॉस्पिटल्ज में जो स्टाफ की कमी है यह कब तक पूरी हो जायेगी। क्या मंत्री जी इस बारे में कोई आश्वासन देंगे।

सरदार एच० एस० चट्ठा: स्पीकर सर, माननीय सदस्य मुलाना साहब की बात आज से तीन सादे तीन साल पहले तो ठीक हो सकती थी लेकिन अब हमने कई 100 डॉक्टरों और वी०एल०डी०ए० की भर्ती की है। इसके अलावा अभी हमने लगभग 125 डॉक्टर और लगभग 15० वी०एल०डी०ए० के पदों को भरने के लिए रिक्वीजिशन हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को भेजी हुई है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्दी ही हमारी डिस्पैंसरीज और वैटरनरी हास्पिटल में स्टाफ की कोई कमी नहीं रहेगी। श्री भूपेन्द्र चौधरी: स्पीकर सर, जब गुड़गांव जिले की बात आती है तो उसका 60 प्रतिशत दूध अकेले पटौदी से आता है लेकिन वहां पर एक तो वैसे ही पशुओं की डिस्पैंसरीज और हास्थिटल्ज बहुत कम हैं और जो हैं उनमें स्टाफ भी बहुत कम है। वहां पर 50 प्रतिशत भी स्टाफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: भूपेन्द्र जी, क्या आपने इस बारे में मंत्री जी को लिखित रूप में दिया

श्री भूपेन्द्र चौधरी: जी स्पीकर सर, मैंने इस बारे में लिखकर भी माननीय मंत्री जी को कई लैटर दिये हें।

सरदार एच०एस० चट्ठा: स्पीकर सर, माननीय सदस्य का लिखित में तो मेरे पास कुछ नहीं आया लेकिन अगर ये आज मुझे

लिखित में दे दें तो मैं कोशिश करूंगा कि सैशन के बाद जल्दी ही इनके यहां हॉस्पिटल्ज में स्टाफ पूरा कर दिया जाये।

डा० शिव शंकर भारद्वाजः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता है कि मैंने भी भिवानी हल्के के राजगढ़ गांव में डिस्पैंसरी खोलने की डिमांड दी हुई है। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई आश्वासन देंगे कि वे हमारी डिमाण्ड को पूरा करेंगे?

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो हमारी सरकार द्वारा 90 डिस्पैंसरीज खोली जानी हैं उसमें we will consider it.

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर सर, मेरे हल्के में एक दीवाना गांव है। वहां पर पिल्ली सरकार के समय में एक हॉस्पिटल खोला गया था उसकी कागजों में मंजूरी नहीं है। मैं इस बारे में कई बार लिखकर माननीय मंत्री जी को रिक्वैस्ट कर चुकी हूं। लेकिन इसके बावजूद भी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर सर, जब हम नये हॉस्पिटल्ज बनायेंगे तब जो–जो इन्होंने लिखकर दिया है उसको कंसीडर किया जायेगा।

श्रीमती अनीता यादवः स्पीकर सर, वैसे तो मंत्री जी का जबाव आ गया है कि वी०एल०डी०ए० और डॉक्टर्ज लगाये हैं लेकिन मेरा आपके माध्यम से इनसे अनुरोध है कि ढलांनवास गांव मातनहेल के अन्दर आता है जिसकी लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और इसी प्रकार से खेड़ा थरू गांव है जो कि बहू के पास पड़ता है। उनमें से कोई एक वी०एल०डी०ए० भेज दिया जाये तो इससे गांव वासियों को सुविधा हो जायेगी।

Mr. Speaker: It is not possible for minister to make reply offhand at this stage.

Monitoring of Private Nursing Homes

***1227. Shri Tejendra Pal Singh Mann:** Will the Health Minister be pleased to state:—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to monitor the private nursing homes, as has been done in Punjab through an act ; and

(b) the steps taken by the Government to provide safety to private nursing homes against unlawful elements ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):

(a) Yes sir. The matter is under consideration of the overnment.

(b) The proposed legislation will be comprehensive.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, अभी पिछले ही दिनों करनाल और कैथल में बहुत से नर्सिंग होम्ज में मार–पिटाई तक हुई। अगर कहीं किसी का परिजन मर जाता है तो इस तरह की घटना आम बात है। स्पीकर सर, ऐसे केसिज में कोई नैग्लीजेंसी की बात करता है और कोई दूसरी तरह की बात करता है। स्पीकर सर, पंजाब के डॉक्टर्ज ने मुझे बताया है कि पंजाब में इस प्रकार का एक्ट लागू किया गया है जिसमें डाक्टर्ज को प्रोटैक्ट करने का प्रावधान भी है और जो मरीज गलत काम करते हैं उनको गलत काम करने से रोकने का भी उसके अन्दर कहीं न कहीं प्रावधान रखा गया है। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से यही रिक्वैस्ट है कि हरियाणा प्रदेश में भी ऐसा एक्ट लागू किया जाना चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त का सजैशन ठीक है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम इस मामले में पूर्णतः सजग हैं और दोनों तरह की बातों के लिए कानून लेकर आ रहे हैं। इनमें पहला यह है कि हम नर्सिंग होम्ज की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून लेकर आ रहे हैं ताकि वे भी कोई गड़बड़ न कर सकें और किसी गरीब आदमी को डॉक्टर या उसके स्टाफ की लापरवाही की वजह से अपने परिवार के किसी सदस्य की जान का नुकसान न उठाना पड़े।

Mr. Speaker: Hon'ble Members now the question

hour is over.

वर्ष 2010 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members now general discussion on the Budget Estimates for the year 2009-2010 will be resumed.

श्री आनन्द सिंह दागी (महम): स्पीकर सर, माननीय वित्त मंत्री जी ने 13 फरवरी, को इस प्रदेश के विकास व विभूति के लिए वर्ष 2009– 10 का जो अनुमानित बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सारी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पिछले 4 साल से लगातार विकास की तरफ बढ़ रही है और यह हरियाणा प्रदेश भी विकास की ओर अग्रसर है। अध्यक्ष महोदय, 4 साल पहले जो सरकार थी उसका 6 साल का बजट कल श्री के०एल० शर्मा जी ने हर साल के हिसाब से सदन के सामने प्रस्तुत किया। उनका बजट किसी साल में भी दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं गया। उस दौरान भी जितना बजट खर्च के लिए रखा गया, वह सारा भी ये खर्च नहीं पाये। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्य श्री शादी लाल बतरा पदासीन स्पे समापत्ति महोदय, आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का जो राज आया है और उनका सहयोग हमारे आदरणीय भाई चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, वित्त मंत्री के पद पर विराजमान हो कर दे रहे हैं।

इन्होंने हर साल इस हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए इतना जबरदस्त बजट पेश किया है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की वाहवाही हो रही है। सभापति महोदय, 10 हजार करोड़ रुपये से भी०पर हमारा बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी की नीति, नियत और प्रदेश की उन्नति के प्रति वचनबद्धता, निष्ठा, प्रदेश के चहुंमुखी विकास व उत्थान के प्रति कटिबद्धता का परिणाम है। सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं है और यह एक बहुत बड़ा संयोग है कि हमारे दोनों नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए और हरियाणा प्रदेश की भलाई के लिए, इस प्रदेश के उत्थान के लिए बहुत बड़ी विभूति हैं। इन दोनों का सम्बन्ध इस हरियाणा प्रदेश की दो बहुत बड़ी विभूतियों से है। इस देश और प्रदेश के किसान नेता के रूप में विख्यात रहबरे–आजम सर छोटूराम जी का ही खून चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की रगों में दौड़ रहा है। उसी प्रकार से एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक आदर्शवादी इंसान जिन्होंने अपना जीवन सदैव गरीब के लिए, किसान के लिए और हर वर्ग के उत्थान के लिए लगा दिया उनका खून आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की रगों में दौड़ रहा है और उसी का परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश चहुंमुखी विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। आज अगर किसान सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो मैं समझता हूं कि वह रहबरे–आजम सर, छोटूराम जी की

ही देन है। जब यह देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, किसान वर्ग हर तरह से दबा हुआ था उस वक्त रहबरे–आजम सर छोटूराम ने किसानों की आवाज उठाई और किसानों को हर प्रकार का सम्मान इस देश में दिलवाया। उस रहबरे–आजम सर छोटूराम का खून आज वित्त मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह के रूप में हमारी इस विधान सभा में विराजमान है। उसी प्रकार उससे आगे बढ़ कर आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, जिनकी रगों में एक महान स्वतंत्रता सेनानी का खून है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के पिता चौधरी रणबीर सिंह जी एक महान आदर्शवादी नेता थे जिनका सारा जीवन सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहा। एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व चौधरी रणबीर सिंह जी थे कि अगर उनके जीवन की झलक को देख कर चलें उनकी जो नीति थी, उनके जो आदर्श थे उनको धारण करके हम चलें तो मैं समझता हूं कि यह देश और प्रदेश सारी दुनिया में एक नम्बर पर आ सकता है। उनके जीवन के त्याग और तपस्या को देख कर चलें तो मैं समझता हूं कि उनके जो निजी आदर्श हैं उनको लेकर हम चलें तो हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेंगे। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे आदर्श कम से कम आज के समय में तो नहीं हो सकते हैं। आज से करीब 31 –32 वर्ष पहले उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर इस समाज के लिए इस प्रदेश के लिए और देश के उत्थान के लिए अपनी जीवन धारा में परिवर्तन किया और उसके बाद मैं समझता हूं कि ऐसा व्यक्ति इस देश और प्रदेश में कोई और नहीं हो सकता। आज के

नेता आखिरी सांस तक, मृत्युशैया तक यह सोचते हैं कि जब भी सांस निकले वह किसी न किसी पद पर रहते हुए निकले। सभापति महोदय, उस महान नेता को सच्ची श्रद्धांजलि इस बात के लिए देना चाहता हूं कि 31 साल तक जो उन्होंने जनसेवा की, फ्रीडम फाईटर्ज के लिए जो कुछ किया, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों के लिए जो कुछ किया और राजनीति से हट कर के जो काम किये वे ऐसे उदाहरण थे जो आज देश के अन्दर कहीं नहीं मिलते हैं। चाहे आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हों और चाहे हमारे अजीज दिपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हों हालांकि ये दोनों राजनीति में सक्रिय रह कर चुनाव लड़ते रहे हैं और राजनीति करते रहे हैं लेकिन 31 साल के जीवन में आदरणीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने कभी भी अपने सुपुत्र और पौत्र के लिए वोट के लिए किसी व्यक्ति से आग्रह नहीं किया। सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ा त्याग हे, एक किस्म से यह एक संन्यास है। सभापति महोदय, और ज्यादा न कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जिस ढंग से इस प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए और जन–जन की सेवा के लिए, जन–जन के उत्थान के लिए हर व्यक्ति के दु:ख दर्द को समझते हुए जो घोषणाएं की हैं और जो अनुदान दिये हैं वे सराहनीय हैं। इस प्रदेश के हर तरह से विकास तथा पुनर्निमाण के जो कार्य उन्होंने किये हैं उनसे आज हरियाणा प्रदेश की जनता में चारों तरफ उनकी वाहवाही है। मुख्यमंत्री जी जिस रास्ते से भी गुजरते हैं हजारों की तादाद में लोग उनके

रूपा गत के लिए खड़े मिलते हैं और उनकी जय–जयकार करते हैं क्योंकि उनका ऐसा व्यक्तित्व है। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सर्वागीण विकास के साथ–साथ हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कार्य किये हैं। चाहे बुढ़ापा पैंशन हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हैं, नम्बरदार हैं, चौकीदार हैं, पंचायत के सदस्य, जिला परिषद् के साथ पंचायत समितियों के सदस्य सभी को ऐसे प्रोत्साहन दिये हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो किया है वह आज पूरे हरियाणा प्रदेश में वाहवाही के बायस बने हैं। सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ जो बुढ़ापा पैंशन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये की है वह एक सराहनीय कार्य है। सभापति महोदय, आज से करीब चार साल पहले प्रदेश की बागडोर जिन लोगों के हाथ में थी वे खाली बातों से जनता की झूठी वाहवाही लूटने के लिए अखबारों और रेडियो पर डीगें मारते थे कि हम पैंशन 700 रुपये कर देंगे, हम 500 रुपये कर देंगे। छः–छः साल लोग राज में बैठकर चले गए लेकिन कभी पैंशन बढ़ाने का नाम नही लिया और आखिरी दिनों में जब थोड़ा सा समय रह गया और इलैक्शन नजदीक थे तो प्रोत्साहन के लिए 100 रुपये बढ़ा दिये, उनको पता था कि आगे जो भी सरकार आएगी वह भुगतेगी। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक जनप्रिय नेता के रूप में जन–जन की भावनाओं के साथ जुड़ कर इस प्रदेश को चहुंमुखी विकास देना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो 500 रुपये बुढ़ापा पैंशन वृद्धों के लिए की है वह एक बहुत अच्छा और बढ़िया काम होने के साथ ही साथ

उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान भी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह बुढ़ापा पैंशन ही नहीं है बल्कि यह एक किस्म से बेसहारा लोगों को भारी प्रोत्साहन देने की बात है। विदेशों में यूरोप के देशों में अमेरिका जैसे विकसित देश में जो बूढो के लिए किया जाता है ऐसा प्रयास हरियाणा प्रदेश में किया गया है और हर प्रकार से उनके बुढ़ापे का सहारा बन कर सरकार मदद कर रही है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो उदारवादिता आपने कहने से पहले ही दिखा दी है वह कोई और नहीं दिखा सकता है। आजकल के जमाने में सभी आपकी तरह से नहीं हैं। सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी के पिता चौधरी रणबीर सिंह जी 22 दिनों तक एक ऐसी अवस्था में रहे कि उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी था। उस वक्त मुख्यमंत्री जी सारे सरकारी काम काज छोड़ करके एक स्तन बन कर के उनकी सेवा में लगे रहे थे। आज इस देश में ऐसी सेवा का कोई उदाहरण देखने को मिलता नहीं हे। लेकिन आज भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपने बुजुर्गो की कमाई खाते रहे हैं और जब उनके बुजुर्ग बीमार हुए तब उनको अपने बुजुर्गो की सेवा करने का मौका मिला लेकिन उन्होंने उनकी सेवा नहीं की और उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। जिस आदमी ने अपने बच्चे को बचपन से लेकर बड़े होने तक सम्भाला हो और जब उस बच्चे को उसकी सेवा का मौका मिला तो उन्होंने उसको पूछा तक नहीं। सभापति महोदय, यह सेवा तो वही कर सकता है जिसकी रगों में अपने मां–बाप का

असल खून होता है। मुख्यमंत्री जी, आज जो बुजुर्ग बेसहारा है उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको उनके लिए बजट में कुछ और करना होगा ताकि वे अपना बुढ़ापा आसानी से जी सकें।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि यह जो वृद्धावस्था भत्ता है यह हमने दूसरी दफा बढाया है। हम यह भत्ता उनको पैंशन के रूप में नहीं देना चाहते हैं। हम उनको यह अधिकार सम्मान के रूप में देना चाहते है। आईन्दा इसका नया नाम वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना होगा। सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि वित्तमंत्री जी के सुझाव से हमने फैसला किया है कि जो भी बुजुर्ग 10 साल से लगातार पैंशन ले रहा है हम उसको 500 रुपये की बजाए 700 रुपये सम्मान भत्ता देंगे। इसके अलावा जिनको हमने 500 रुपये का सम्मान भत्ता दिया है उसमें भी हम सालाना वृद्धि 50 रुपये की करेंगे ताकि उनको हमारी तरफ से सम्मान मिले।

वित्त मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा जोकि मुख्यमंत्री जी बोलते हुए छोड़ गए हैं। ये जो 700 रुपये दिए जाएंगे वे उनको दिए जाएंगे जिनको 1 .4.2008 तक पैंशन लेते हुए 10 साल हो गए हों। इसके अलावा

यह जो 50 रुपये सालाना वृद्धि दी जाएगी यह उनको दी जाएगी जिनको 10 साल नहीं हुए होंगे। इसके अलावा हमारी सरकार हर चौथे साल इसका रिव्यू करेगी कि बढ़ोतरी की जरूरत है कि नहीं हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन पुरुष और महिला बुजुगी बुजुर्गों को पैंशन लेते हुए 10 साल हो गए हैं उनको हम साफा, होगा और शॉल देंगे

वर्ष 2010 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री आनन्द सिंह दांगीः चेयरमैन सर, जैसा मैंने करनी और कथनी की बात कही थी परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वित्तमंत्री महोदय की रगों में उन दोनों महान विभूतियों का ही खून दौड़ रहा है। उन दोनों महान विभूतियों ने अपना सारा जीवन गरीब के उत्थान के लिए, किसान की भलाई के लिए ही बिताया है और उसी का रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि एक महान सपूत ने एक छोटे से भाई के निवेदन पर जो आज लोगों को बिना मांगे देने की बात कही है वह वास्तव में महान है। चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जुग–जुग जिएं और जब तक जिएं इसी तरह से हरियाणा के जन–जन की सेवा करते रहें, इस प्रदेश का विकास करते रहें। ये जब तक भी जिएं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहकर इस प्रदेश की सेवा करते रहे। मैं इसके

लिए हरियाणा प्रदेश के खे की तरफ से इनका बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं और इसके लिए इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि छोटे भाई ने जो प्रार्थना इनके सामने रखी उसको इन्होंने स्वीकार करके कहा कि कोई 70 साल का बूढा जिस दिन हो जाएगा उसको 700 रुपये देने के लिए इन्होंने कहा है। चेयरमैन सर, वाकई 70 साल की उम्र में असलियत में बूढा छा हो जाता है और उस वक्त की उम्र में उसको साथ और सेवा की जरूरत होती है। चेयरमैन सर, यह बड़ी स्पष्ट बात है कि सारे बूढे चौधरी रणबीर सिंह नहीं हो सकते। वे तो 64 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति से अपना पल्ला झाड़कर जन सेवा में लीन हो गये थे। ऐसा व्यक्ति को और नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने एक बात कही थी कि राजनीति तो एक ऐसो चीज है जहां पर आदमी मृत्यु तक यह सोचता है कि जब उसकी आखिरी सांस निकले तो वह किसी पद पर रहकर निकले। यह तो कुछ विरले ही होते हैं जो समाज की या मानव सेवा के लिए आते हैं। केवल अकेला उदाहरण चौधरी रणबीर सिंह का ही है। चेयरमैन सर, 700 रुपये का जो सम्मान आदरणीय मुख्यमत्री जी ने बूढो को दिया है वह बहुत सराहनीय बात है। इसके साथ ही साथ हर साल 70 साल की उम्र के नीचे के बूढो के लिए भी 50 रुपये बढ़ाने की जो बात अभी मुख्यमंत्री जी ने कही है तो यह बहुत वधू सम्मान उन्होंने उनको दिया है जिसकी वाहवाही अब पूरे प्रदेश में होगी। चेयरमैन सर, यही नहीं और भी अनेक वर्गों के लिए जैसे विधवा पैंशन जो पहले 350 रुपये प्रति माह दी जाती है, अब उसको बढ़ाकर 550

रुपये प्रति माह कर दिया गया है। बेसहारा बच्चों को जहां पहले 100 रुपये दिए जाते हैं वहां अब इसको बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए फिक्स चिक्सिा भत्ता 750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, पैंशनर्ज को घूमने फिरने के लिए भी अब एल. टीसी. की सुविधा प्रदान कर दी गयी है। यह बहुत बड़ा कार्य पैंशनर्ज के लिए किया गया हे। इसी तरह से पंच, सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद् के सदस्यों, पंचायत समिति के सदस्यों यानी सब का वेतनमान बढ़ाया गया है इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। नगरपालिका के चेयरमैन, नगर परिषद् के मेयर, उप मेयर सबका वेतन बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से आगनवाडी वर्कर्ज और हैल्पर्ज का भत्ता भी बढ़ाया गया है। चौकीदार का मानदेय जो पहले एक हजार रुपये होता था, अब उसको बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके साथ ही उसका वर्दी का, सीटी का और बैटरी का भत्ता भी बढ़ाकर जो गरीब आदमी को सहारा दिया है वह बहुत बड़ी बात है। चौकीदार दिन रात गांवों की सेवा करते हैं और रखवाली करते हैं। इन सबकी मुख्यमंत्री जी को दुआएं मिलेंगी। इसी प्रकार से बेरोजगारी भत्ते के बारे में मैं कह सकता हूं कि यह थोड़ा सा होता है लेकिन जो बेरोजगारी भत्ता दसवीं, प्लस टू बी.ए. और बी. एस.सी. के बच्चों को मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने दिया है उसके बारे में मैं कह सक्ता हूं कि आज कोई भी व्यक्ति अपने आपको बेरोजगार नहीं मानेगा,

बेरोजगार नहीं समझेगा। उसको थोड़ा सा जेब खर्च सरकार ने दिया है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ नम्बरदारों का मानदेय बढ़ाया है, आगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया है। खेल स्टेडियम बनाने और उनमें कोच डिप्यूट करने की घोषणा की है। शहरों में कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मकान बनाने और अंगहीन लोगों की पैंशन बढ़ाने का काम किया है और ये जितने कार्य किये गये हैं ये ऐसे कार्य किए हैं जो कि प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। जो कुछ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के विकास के लिए किया है ऐसा सारी दुनिया में कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। सभापति महोदय, हरियाणा प्रदेश एक किसान प्रधान प्रदेश है यहां हर व्यक्ति चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे काश्तकार है, चाहे दस्तकार है. चाहे मजदूरी करता है सबकी रोजी रोटी जमीन के साथ जुड़ी है, किसान के साथ जुड़ी है। किसान दिन–रात मेहनत करके फसल. पैदा करता है यदि उसको छः महीने के बाद भी फसल की सही कीमत न मिले तो उसको बहुत तकलीफ होती है। सभापति महोदय, पिछले चार साल के शासन काल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को जो कुछ दिया है उससे हर वर्ग खुशहाल है, किसान खुशहाल हैं, सब खुशहाल हैं। पहले एक जमाना था सर छोटू राम जी का समय था तब यह कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार। एक वक्त ऐसा था जब खेती को उत्तम माना

जाता था। उस वक्त भी खेती के ठीक भाव मिल जाते थे। बीच के समय में उस समय की सरकारों ने किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। किसान की जिन्स के बारे में सोचा नहीं गया। राजनीति करने वाले खाली राजनीति करते रहे और लोगों से वोट लेते रहे, उनसे नोट लेते रहे, उनको बर्बाद करते रहे और उनकी जिन्स के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। लेकिन आज जो केन्द्र में सरकार है वह आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की रहनुमाई में है और आदरणीय भाई चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की इस प्रदेश में सरकार है। आज मैं कह सकता हूं कि इस राज में मनुष्य ही नहीं वरन् चाहे कोई जीव भी है वह शाम को पेट भर कर सोता है। चाहे कोई कुत्ता है, बिल्ली है या कोई मनुष्य है हर कोई पेट भरकर सोता है और पेट भरने के साथ ही साथ आराम की नींद सोता है। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हे। पहले के शासनकाल में लोगों को रातों की नींद नहीं आती थी। मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है 1 जनता का पालक और रक्षक होता है। जनता को सुख सुविधा के साथ–साथ अमर चौन देना उसका फर्ज होता है और ऐसे में यदि कोई मुख्यमंत्री यह कहे कि वह मुख्यमंत्री ही क्या जिसके नाम से हर के कोई व्यक्ति रात को सोते–सोते चारपाई से न गिर जाए। ऐसे लोगों पर लानत है जिन्होंने राजनीति में आकर प्रदेश में गंदा वातावरण पैदा किया। आज हर व्यक्ति आराम की नींद सोता है। किसी के सामने कोई दिक्कत नहीं है और उसका परिणाम यह है कि आज जो किसान मेहनत करता है, दिन रात न देखकर अंधेरी रात में अपनी

फसल में पानी देता है और सारी–सारी रात जागकर के इस हरियाणा प्रदेश और देश का पेट पालने का काम करता हे। उसी किसान को सही मूल्य दिलाने के लिए जैसा कि आप सभी जानते हें कि मुख्यमंत्री जी ने झाडली की रैली में आदरणीया श्रीमती सोनिया गांधी से प्रार्थना की। आप में से बहुत सारे लोग झाडली रैली में उपस्थित थे।

श्री सभापतिः दौगी साहब, टाईम ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री आनंद सिंह दागीः सभापति महोदय, ये बात मैं नहीं मानूंगा क्योंकि तीन अकेजन हो लिए हैं। औबीच्युरी का अकेजन हो लिया, गवर्नर साहब का ऐड्रस हो 'लिया, डिमांड्स हो ली लेकिन मुझे चर्चा का अवसर नहीं दिया गया। सभापति महोदय, आपका नाम भी मैंने भेजा था। आपको बोलने का मौका दे दिया गया और मेरा नाम रख दिया गया। मैं तीनों अकेजंस पर नहीं बोला हूं। सभापति महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए और हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। जहां तक किसान की जिन्स का भाव देने की बात है। (विघ्न) चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि ' जब झाडली गांव में बिजली के प्लांट का उद्घाटन करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी आई थी उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने रैली में खड़े होकर एक ही आवाज उठाई थी कि किसान जो देश का पेट पालता है, देश का पेट

भरता है उसकी जिन्स का मूल्य ठीक समय पर मिलना चाहिए। उस किसान को आज उसकी मेहनत का भाव भी नहीं मिल रहा है और मुख्यमंत्री ने यह कहा कि किसान की गेहूं की फसल का भाव कम से कम 550 रुपये से 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर श्रीमती सोनिया गान्धी जी ने गेहूं का भाव 540 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एक ही जुबान से बढ़ाया। जितना ज्यादा गेहूं का भाव इस समय बढ़ाया गया है उतना भाव आज प्रदेश और देश क्या सारी दुनिया में नहीं बढ़ाया गया और यह एक ऐतिहासिक फैसला था। कई राज आये और कई मुख्यमंत्री भी आये, प्रधान मंत्री भी बनकर चले गये लेकिन किसान के लिए किसी ने नहीं सोचा। कभी 5 रुपये कभी 7 रुपये और कभी दो रुपये का भाव बढ़ाया गया। जितनी ज्यादा जलालत किसान के साथ पिछले राजों में हुई उतनी कभी नहीं हो सकती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सारे देश के किसान की तरफ अपनी निगाह डाली। किसान बेचारा एक असहाय व्यक्ति है क्योंकि जिन्स की बोली एक व्यापारी लगाता है जबकि कोई भी व्यक्ति चाहे वह सुई बनाता है या कोई छोटा औजार बनाता हे तो उस फैक्टरी का मालिक उस चीज की कीमत खुद तय करता है। लेकिन किसान एक ऐसा व्यक्ति हे जो सारे देश के पेट को पालता है सबसे ज्यादा मेहनत करता है। चाहे ओले पड़े, प्राकृतिक विपदा आये, तूफान आये कुछ भी आये वह खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता हे। तूफान उसकी सारी फसल को उड़ा कर ले जाता है लेकिन

वह बेचारा मन मारकर बैठ जाता है ओर उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज जिन्स का भाव सम्मानित तरीके से दिलवाया गया है। पिल्ले साल गेहूं का भाव एक हजार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया गया वह एक बहुत बढ़िया भाव था। जिसकी चारों तरफ हर किसान ने वाहवाही की है। इसी प्रकार से धान का भाव भी बढाया गया है। हमारे साथी कह रहे हैं कि क्या भाव बढ़ाया है। पिछले सीजन में जब धान की परचेज की बात आई तो बीच में ही कुछ दिन के लिए परचेज को रोक दिया गया। उस समय हमारे विपक्ष के ' भाईयों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। प्रदर्शन किस बात के लिए किए कि धान के भाव बढ़ाये जायें। आप यह बतायें कि डी०सी० से रिक्वैस्ट करने से क्या भाव बढ़ाये जाते हैं या एस०डी०एम० से रिक्वैस्ट करने से भाव बढ़ाये जाते हैं। डी०सी० और एस०डी०एम० को क्या पॉवर है कि वह भाव बड़ा दें। धान का भाव बढाने की पावर दिल्ली में बैठे लोगों के हाथ में है। दिल्ली अगर एस०डी०एम० के माध्यम से कोई चीज जाती है तो वह 10 या 20 दिनों मे जाती है तब तक तो किसान लुटकर अपने घर में बैठ जाता है। चेयरमैन साहब, में भाई भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब धान के भाव के लिए चर्चा चली कि किसान को धान का भाव ठीक नहीं मिल रहा है तो उस समय ये विदेश ले गये हुए थे। ये बीच में ही अपनी विदेश की यात्रा को छोड्कर सीधे दिल्ली में कृषि मंत्री, प्रधान मंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिले और अगले ही दिन धान की खरीद को खोल दिया गया और किसानों को तीन हजार से 3200

और सादे तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का भाव दिया गया। जो भाव धान का हिन्दुस्तान के किसानों को दिया है उतना भाव आज तक कभी नहीं गिला। पूसा 1120 वैरायटी जो विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदा होती हे उसका भाव तीन से साढ़े तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल दिलवाना एक बड़ी बात है। चेयरमैन साहब, मैं एक किसान हूं और मैं एक समझदार किसान हूं। खेत में जीरी झाड़ी, ट्राली में डाली और सीधी मण्डी में भेज दी। चेयरमैन साहब, मेरे पास 30 एकड़ धान की फसल थी जो 3300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी और एक एकड़ की पैदावार के रूप में 58000 रुपये मुझे मिले हैं। सभापति महोदय, अगर 58 हजार रुपये एक एकड़ की 6 महीने की पैदावार किसान को मिल जाती है तो इससे ज्यादा कोई और बात नहीं हो सकती। उसके बाद दूसरी फसल आ जाएगी। सभापति महोदय, अब गेहूं की फसल आ जाएगी। कम से कम 25 या 50 हजार रुपये एक एकड़ की गेहूं की उपज के आ जाऐंगे। जब किसान को साल में एक एकड़ की उपज के 60 हजार, 70 हजार या 90 हजार रुपये मिल जाएंगें तो में समझता हूं कि वही पुराना सुनहरा युग आने वाला है। यह युग लाने का सबसे बड़ा श्रेय हमारी सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को जाता है। आज आदमी को खेती में ओर व्यापार में कोई कमी नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो कृषि मंत्री जी बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि कई बार बीज में गड़बड़ आ जाती है,

पैस्टीसाइडस नकली मिल जाता है जिससे किसान को बहुत हानि उठानी पड़ती है। उसके लिए मैं कृषि मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की बातों को रोकें। इस तरह की गड़बड़ियों को चौक करवाएं। कोई भी ऐसा तरीका निकालें जिससे कि इस तरह की गड़बड़ियां न हों ताकि भोले भाले किसान को नुकसान न हो ओर वह अपने जीवन को अच्छी प्रकार से आगे बढ़ा सके। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज चारों तरफ विकास है, आज चारों तरफ तरक्की हे, जन–जन को सहूलियतें हैं। आज वह जमाना नहीं है कि मुख्यमंत्री बने और इलाकावाद शुरू, भाई भतीजावाद शुरू, कौम परस्ती शुरू। उन्होंने तो सब तरीके से ग्रस्त होकर पूरे हरियाणा को गर्क में डालने का काम किया था। आज की सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने किसी दूसरी तरफ नजर न करके केवल इस प्रदेश के विकास की तरफ नजर रखी है। ये इस प्रदेश को चहुंमुखी विकास की तरफ ले गए हैं। हम सफेद कुर्ते पाजामे वाले चाहे कुछ भी कह लें, राजनैतिक द्वेष भावना से चाहे कुछ भी कहें लेकिन यदि हम आम आदमी से दिन में जाकर, रात में जाकर, घर में या बैठक में बैठकर, हाली से जाकर पूछें, पाली से जाकर पूछें कि आज हरियाणा में विकास हुआ है या नहीं तो वह यही कहेगा कि आज हरियाणा में विकास के कार्यो की लाईन लगी हुई है। हरियाणा के किसी भी कोने में हम चले जाएं, हर कोने में यही आवाज मिलेगी कि हरियाणा में विकास कार्य हो रहे हैं। जो व्यक्ति हरियाणा के खेतों में डागर

चराते हैं या हल जोतते हैं उनसे हम अपनी गाड़ी को रोककर पूछें कि तेरे गांव में क्या पोजीशन है तो हर व्यक्ति यह कहेगा कि हमारे गांव में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। पूरी सड़कें बनी हुई हैं, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है तथा किसी बात की दिक्कत नहीं है। यह एक सच्चे सेवक का काम होता है क्योंकि जो व्यक्ति सेवक के रूप में, ठीक–नीति से और ठीक नियत के साथ जन सेवा करता है वह हमेशा आगे बढ़ता ही बढ़ता है और भगवान भी हमेशा उसका साथ देते है। उसका यह परिणाम है कि आज किसी के पास हमारी सरकार के खिलाफ बोलने का मुद्दा नहीं है, कोई कहने के लिए बात नहीं है। आज हम किसी भी प्वांयट पर जाएं चाहे गरीब आदमी की बात हो, हरिजनों की बात हो, किसान भाईयों की बात हो, व्यापारियों की बात हो या नौकरी पेशा लोगों की बात हो हर किसी के लिए हमारी सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम ने जो किया है ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हो सकता। किसानों के लिए तो यहां विशेषकर काम किए गए हैं। सभापति महोदय, ये बड़े–बड़े ऐजीटेशज की बात करते हैं कि किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव ली गई, किसानों की जमीन जबरदस्ती ली गई। सभापति महोदय, जबरदस्ती जमीन तो ये लोग लेते थे। आज किसान को जमीन का मुआवजा और कीमत बहुत ज्यादा मिली हे। सभापति महोदय, इनके समय में जब सरकार जमीन एक्वायर करती थी तो 2–2 या अढाई–अढाई लाख रुपये जमीन कै मिलते थे। आज हर किसान यह कहता है कि मेरी

जमीन एक्वायर कर लो, मेरी जमीन एक्वायर कर लो क्योंकि जो कीमत आज जमीनों की दी गई है उसकी हर व्यक्ति सराहना करता है। सभापति महोदय, एक साल का 15 हजार रुपये पर एकड़ का पट्टा दिलवाने का जो काम किया गया है वह सारी दुनिया में कहीं नहीं है। सभापति महोदय, कोई आदमी अपनी जमीन बेच दे जैसे मैंने अपनी जमीन बेच दी, घर बेच दिया और उसकी पूरी कीमत वसूल ली तो उसके बाद मेरा अपनी जमीन पर कोई हक नहीं रह जाता। लेकिन आज की हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने यह किया है कि किसी भाई फी एक एकड़ जमीन सरकार किसी भी काम के लिए चाहे सड़क बनाने के लिए, चाहे माईनर बनाने के लिए या किसी दूसरे विकास कार्य के लिए एक्वायर करती है तो उसको पूरे देश में सबसे ज्यादा कीमत दी जाएगी। इसके साथ–साथ 15 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सालाना जो मुआवजा देने की बात मौजूदा सरकार ने की है पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती। इसमें 500 रुपये सालाना बढ़ौतरी भी होगी। 33 साल तक तीन पीडियां निकल जाती हे और अरबों रुपये प्रति एकड़ के बन जाते हें। सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के साथी कहते हें कि सरकार ने किसानों की जमीन एक्वायर करके उनको बेघर कर दिया और घपला कर लिया। मैं इनसे अना चाहता हूं कि किस चीज का घपला कर दिया। इन लोगों को यह भी नहीं मालूम कि कौन जमीन खरीदता है और कौन जमीन बेचता है। सरकार तो देश और प्रदेश के हित के लिए जमीन

एक्वायर करती है। चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे नहर बनाने की बात हो या कोई और काम हो ये सभी कार्य प्रदेश और देश के हित के लिए होते हें। यदि इण्डस्ट्री के लिए या अपने काम धन्धे के लिए कोई आदमी जमीन खरीदता है तो यह सरकार का काम नहीं है। यदि कोई आदमी अपने काम के लिए जमीन खरीदता है ओर कोई बेचता है तो यह सभी का मौलिक अधिकार है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में भी एक बड़ा काम किया है कि यदि कोई इण्डस्ट्री या बिल्डिंग बनाने के लिए हरियाणा प्रदेश में जमीन खरीदता है ओर अपने रोजगार को आगे बढ़ाता है तो प्रति एकड़ के हिसाब से 50 हजार रुपये प्रति साल 33 साल तक जिसकी जमीन खरीदेगा उसको मुआवजा दिया जायेगा और मुआवजे में हर साल एक हजार रुपये की बढ़ौत्तरी भी होगी। इस प्रकार 33 साल तक अरबों रुपये मुआवजे के हो जायेंगे। विपक्ष के साथी तो लोगों को हमेशा बहकाते रहे हें। पहले भी इन्होंने बहकाया कि हम बिजली के बिल माफ कर देंगे बिल मत भरी। हम यह करेंगे, वह करेंगे। झूठ बोलकर राज ले लेते थे और सिवाय प्रदेश की बरबादी करने के कुछ नहीं करते थे। जबकि आज प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बद रहा है और देश में नम्बर एक प्रदेश बन गया है। जिस समय विपक्ष के साथियों की सरकार थी उस समय हरियाणा प्रदेश 14वें स्थान पर था और हमारे मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम के लगन से कार्य करने पर अब हरियाणा प्रदेश पहले नम्बर पर है। मौजूदा सरकार ने प्रदेश में बहुत विकास करवाया है

और यही कारण है कि आज हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में भी सबसे आगे है, जो कि गौरव की बात है। सभापति महोदय, इसके साथ–साथ आज हमारी सरकार ने किसी प्रकार की कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी है।

11.00 बजे

सभापति महोदय, जहां तक कृषि की बात है इस समय कृषि मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। कृषि के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि किसान की तरफ सरकार विशेष ध्यान दे क्योंकि आज जो किसान तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है वह अपनी मेहनत से कर रहा है। इसमें विभाग का ज्यादा सहयोग नहीं है। सभापति महोदय, हर गांव में ए०डी०आज० और ग्रामीण सचिवों की ड्यूटी लगी हुई है लेकिन हमने नहीं देखा कि वे कभी कोई गोष्ठी किसानों की लेते ही और किसानों को नये बीजों और पैस्टीसाईडस की जानकारी देते हों। मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है और मैं अपने गांव का सबसे बड़ा किसान हूं। मेरे को भी यह नहीं मालूम कि मेरे गांव का ए०डी०ओज० कौन है। इसी प्रकार दूसरे किसानों को भी नहीं मालूम कि उनके यहां ए०डी०ओज० कौन है। यह कितना बड़ा धोखा किसानों के साथ है। इसको मंत्री जी को चौक करने की जरूरत है क्योंकि जो नये बीज और पैस्टीसाईड्स आते हैं उनके बारे में किसानों को जानकारी नहीं होती और वे कई बार गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उनकी फसल खराब हो जाती है। यदि ए०डी०ओज० और ग्राम सचिव समय–समय पर

किसानों को एकत्रित करके गोष्ठी करें तो किसानों को नये बीजों और पैस्टीसाईडस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और उसका वे फायदा भी उठायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी ए०डी०ओज० को ठीक गाईडलाईज दें और कम से कम 6 महीने में एक बार ब्लॉक लैवल पर या जिला लैवल पर किसानों की गोष्ठी भी शुरू करनी चाहिए ताकि किसानों को नई–नई जानकारियां और टैक्कीक्स फसलों से संबंधित मिल सकें तथा अपनी उपज बचाकर अपना जीवनयापन ठीक प्रकार से कर सकें।

सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरा वह हल्का है जिसके०पर बड़ी–बड़ी राजनीति हुई और बड़े–बड़े राजनेता होकर चले गये। वहां पर उन बड़े–बड़े दिग्गज नेताओं ने राजनीति की जो हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचे और बहुत से लोगों ने वहां से हरियाणा को चलाया। वे लोग झूठ और बल की राजनीति करते थे। सभापति महोदय, छ साल तक श्री ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रह कर चले गये और उसी पार्टी का महम से विधायक था लेकिन चेयरमैन सर, त् साल का रिकॉर्ड है कि किसी एक स्कूल को भी अपग्रेड नहीं किया गया। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आज मेरे हल्के महम का एक नी स्कूल ऐसा नहीं है जिसकी अपग्रेडेशन की डिमाण्ड पैंडिंग हो। चाहे हमारी मिडल स्कूल की डिमाण्ड थी, चाहे हाई स्कूल की थी और चाहे कोई +2 के स्कूल

की थी मेरे हल्के में जिस गांव की जो भी डिमाण्ड थी वे आज सारी की सारी पूरी करके शिक्षा के स्तर को०चा उठाया गया है। प्रदेश के गरीब बच्चों को जो अच्छी शिक्षा की सुविधा देने की बात आई है इस मामले में सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। आज मेरे हल्के के एक भी स्कूल की अपग्रेडेशन की डिमाण्ड शेष नहीं है। यह सब क्यों और कैसे हुआ। यहां मैं यही कहना चाहूंगा कि यह नियत और नीति की बात है। सभापति महोदय, इसके साथ–साथ जहां तक खेल और खेलों के मैदान की बात है शिक्षा के साथ–साथ खेल भी बहुत जरूरी हैं। खेल के बिना किसी बच्चे का जीवन पूर्ण रूप से नहीं निखर सकता। खेलों में भाग लिए बिना बच्चा जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सक्ला। सभापति महोदय, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने खेलों के प्रति जो नीति बनाई है उसके तहत हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाए गए हैं और स्टेडियम के साथ–साथ खिलाड़ियों के खुराक भत्ते को भी दुगुणा और तिगुणा किया गया है। सभापति महोदय, इसके बाद जो होनहार बच्चा अपनी खेल प्रतिभा के बल पर अपने प्रदेश और देश का नाल०चा करता है और एशिया लैवल के खेलों में, वर्ल्ड लैवल के खेलों में ओलम्पिक लैवल के खेलों में कोई मैडल लेकर आता है उनके लिए लाखों रुपयों के ईनामों की घोषणाएं की गई हैं। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने करोड़ों रुपये के ईनाम देकर के अपने नौजवान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। हमारी सरकार ने गोल्ड मैडल लाने वाले अपने खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये इनाम स्वरूप दिये हैं। सभापति

महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी पिछले दिनों बीजिंग ओलम्पिक खेलों में जो हमारे नौजवान पदक लेकर आये। उनको इतना बड़ा सम्मान हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया है। इसे देखकर प्रत्येक बच्चे के अन्दर एक जुनून सा उठता है कि मैं भी खेल के मैदान में जाकर अपने आपको एक अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में स्थापित करूंगा। इसके साथ–साथ पदक लाने वाले ऐसे खिलाड़ियों को डी०एस०पी० और इंस्पैक्टर जैसे अच्छे–अच्छे पद भी सरकार की तरफ से दिये जाते हैं। इस प्रकार से इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सभापति महोदय, यह एक सही रास्ता है. एकु सही लाईन है, एक सही विचार है जो हमारे युवाओं को प्रोत्साहन देकर उनकी प्रतिभा को उभारकर इस प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का जच्चा पैदा करेगा। सभापति महोदय, मैं इसके लिए अपनी सरकार को बधाई देना चाहूंगा। सभापति महोदय, इसके साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में देहाती परिवेश में एक यूनिवर्सिटी का खोलना और वह भी महिलाओं के लिए, इस प्रकार की बात भी कोई सोच नहीं सकता। एक देहात के प्रांगण में एक महिला यूनिवर्सिटी खानपुर में खोलने का जो काम सरकार ने किया है इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। सभापति महोदय, महिलाओं का योगदान सभी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। उनके उत्थान के बारे में हमें अपने से भी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसा करके सरकार ने एक बहुत ही बड़ा काम किया हे। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का

बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे हल्के के एक गांव लाखन माजरा में लड़कियों का कालेज खोलने की घोषणा की है। सभापति महोदय, इसी प्रकार से तकनीकी शिक्षा, आई०टी०आई०, पालिटैक्निक और इंजीनियरिंग कालेजिज की तरफ भी ध्यान दिया गया है। आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से तकनीकी शिक्षा पर जो जोर दिया गया है यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सभापति महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज का युग तकनीकी युग है और जो बच्चा अपने हाथ का हुनर सीखेगा वही भरपेट रोटी खायेगा। सिर्फ खाली 10+2, बी०ए० या एम०ए० करने वाले विद्यार्थी आज धक्के खाते फिर रहे हैं। अगर कोई अच्छा इंटैलीजैंट बच्चा है और उसमें अच्छी प्रतिभा है वह तो किसी कम्पीटीशन को क्लीयर करके आगे निकल सकता है वरना तो हजारों–हजारों की फौज जिन्होंने सिर्फ बी०ए० की हुई है वे धक्के खाते फिर रहे हैं। आज के युग में तकनीकी शिक्षा का प्रचार–प्रसार और इसके लिए सहूलियतें देना बहुत जरूरी है और वह आज हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने सब जगह दी हैं और बिना किसी भेदभाव के दी हैं। सैंकड़ों कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लगभग हर हल्के के अन्दर पालीटैक्निक कालेज, आई०टी०आई० तथा सब जगह जो सहूलियतें दी हैं उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। महम की पहले कोई सुध नहीं लेता था। लेकिन अब वहां पर एक पॉलिटैक्निक कालेज दिया गया है और मेरे गांव मदीना में भी एक आई०टी०आई० दी है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उनके०पर काम जल्दी शुरू करवाये जायें। इसके साथ ही साथ मैं सिंचाई की बात भी करना चाहता हूं। हांसी–बुटाना लिंक नहर और दादूपुर नलवी नहर बनाने की बात है यह बहुत अच्छा कदम है। वेस्ट पानी को सही ढंग से प्रयोग करना और हर किसान के सूखे खेतों और सूखी फसलों को पानी पहुंचाना हर सरकार का कर्त्तव्य होता है। मुद्दे बना कर उनसे लाभ उठाना, ग्राऊंड पर कुछ न करना खाली वाहवाही लूटना यह पहले की सरकारी की रीत रही है लेकिन आज की सरकार काम करने में विश्वास रखती है। हांसी–बुटाना लिंक नहर का निर्माण हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह से दादुपुर शाहपुर नलवी नहर बनने पर यमुना कैनाल का पानी हमारे खेतों में जायेगा। इस तरह से यह भी हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है। सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे हल्के की कुछ माईनर्ज हैं जिनके नाम मैं बता रहा हूं एक माली–सामाण माईनर है, एक भैणी भैरों माईनर है, एक दोरड माईनर है और एक न्यू मदीना कोरसाण माईनर बनना है। इन सबकी प्रोपोजल आई हुई है उनको बहुत जल्दी पूरा कराने का कष्ट करें क्योंकि उनकी लोगों को बहुत जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोताही न करके बहुत जल्दी इनका काम होगा। इसी प्रकार से कल मान साहब ने भी कच्चे खालों को पक्का करने की बात कही थी, मैं भी उसका

समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक बहुत जरूरी कदम है और इस बारे में मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन हे कि जो भी इस तरह के 9 इंची खालों की प्रोपोजल आये उसको बिना किसी देरी के अप्रूव कर देना चाहिए। उससे पानी की भी बचत होती है और एक लम्बी सहूलियत किसान को मिलती है। एक बार अगर हम 9 इंच खालें ठीक ढंग से बना दें और मैटीरियल ठीक ढंग का लगा दें तो मैं समझता हूं कि 25–50 साल तक किसानों को दिक्कत नहीं होगी और जो पानी वेस्ट जाता है उसका भी बचाव होगा। साथ ही इससे किसानों की पैदावार भी बढ़ेगी और उत्स अच्छा लाभ हर किसी को मिलेगा।

श्री सभापतिः दौगी साहब, आप वाइंड–अप कीजिए।

श्री आनंद सिंह दांगीः ठीक है सर, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। इसी प्रकार से बिजली की बात है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान जरूरी है। सभापति महोदय, इसके समाधान के लिए हमारी सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं वे आज किसी से छिपे नहीं हैं। हरियाणा प्रदेश बनने के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किसी सरकार ने इस समस्या को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए कार्य किया है। हमारे विपक्ष के भाई सरकार में रह कर गये लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौराः सभापति महोदय, मेरा प्याइंट ऑफ ऑडर्र है। दौगी साहब कौन से भाइयों के बारे में कह रहे हैं। एक तो वे जो दिल्ली वाले कहते हैं कि भाई लोग और एक भाईचारे का भाई होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगीः सभापति महोदय, भाई तो भाई होता है। स्वार्थ के लिए जो भाई को मरवा दे वह भाई नहीं है। जो प्रजातंत्र पर डाका डाले, उसका हनन करे वह किसी का भाई नहीं वह किसी का साथी नहीं होता, किसी से उसका कोई संबंध नहीं होता। वह सिर्फ स्वार्थ सिद्धि का सम्बन्ध होता हे। (विघ्न)

श्री सभापतिः दांगी साहब, प्लीज, आप वाइंड–अप (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगीः सभापति महोदय, मैं बिजली के मामले में कहना चाहता हूं कि जितनी बिजली हमारे पास है उसका टाईम मैनेजमैंट तो ठीक का से होना चाहिए। अगर आप पांच घंटे बिजली देते हैं तो वह इस तरीके से दी जाये कि उसमें हमारे रोजमर्रा के काम बाधित न हों। किसी को सानी काटनी है, किसी को दूध बिलौना है, आटा पिसाई का काम है, बच्चों की पढ़ाई करनी है। आज पूरी बिजली तो नहीं दी जा सकती लेकिन उपलब्ध बिजली को ठीक ढंग से देकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इससे पहले बिजली के कारखाने नहीं लगे, कोई प्लांट नहीं लगे जिससे बिजली बने। आज जो कारखाने इस

प्रदेश में लग रहे हैं उनके बनने में तो अभी समय लगेगा और वे कारखाने धीरे–धीरे बन कर हमारी जनता को समर्पित होते जा रहे हैं। लेकिन आज जो दिक्कत है उसको टाईम मैनेजमैंट के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। सभापति महोदय, इसके साथ ही आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो एक कल्याणकारी और विकास की दृष्टि से, इस प्रदेश की भलाई के लिए जो बजट पेश किया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं।

चौ० हर्ष आर (हथीन): चेयरमैन सर, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट अनुमान भाषण प्रस्तुत किये हैं जिस तरह से हर साल बजट अनुमान पेश होते हैं, हर साल वित्त मंत्री जी के भाषण सरकार की कार्यशैली तथा सरकार के कार्यों को दर्शाते हैं। हर साल हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह के काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी तथा वित्त मंत्री जी कर रहे है वह कोई स्वाभाविक नहीं है बल्कि यह सारे संस्कारों की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मन्त्री हों या विधायक हों कोई भी व्यक्ति हो जो जनहित के कामों के लिए इस विधायिका में शामिल हो गया यह बात उन सब पर समान रूप से लागू होती है कि अगर वे अपने स्वयं के काम करेंगे तो वे जनता के काम नहीं कर सकते हैं। चेयरमैन सर, जनता के काम तभी हो सकते हैं जब अपने स्वयं के काम छोड़ कर जनता के हित की तरफ चलें यह तभी सम्भव

होता है जब ऐसे संस्कार हों। यह संस्कार दृष्टि माननीय मुख्यमंत्री जी में उनके परिवार के संस्कारों से पैदा हुई है। स्वामी दयानन्द जी और महात्मा गांधी जी के संस्कार माननीय वित्त मंत्री जी में उनके परिवार से आए। स्वामी दयानन्द जी और सर छोटू राम जी के संस्कारों का प्रभाव उनके परिवार पर था। दोनों परिवारों में जो संस्कार हैं ये संस्कार वैदिक काल की तहजीब के परिचायक हैं। वैदिककाल की नियत से दोनों परिवारों में संस्कार पैदा हुए हैं। दोनों परिवारों के संस्कार आज मिल कर जिस तरह से इस प्रदेश की तरक्की और प्रदेश को०चाई तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं इसके लिए ये दोनों बहुत–बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। चेयरमैन सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो कि हाल ही में इस असार संसार से चले गये हैं उनके संस्कारों को मैं धन्यवाद दूंगा। आज महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा हमारे इस सदन में लगाई गई है यह सारे हालात बताती है और सारी चीज दर्शाती है कि कौन सा व्यक्ति किस नियत और कार्यक्रम के साथ प्रदेश की सेवा करने के लिए आया है। चेयरमैन सर, मेरे से पहले बोलते हुए माननीय दोगी साहब ने सारी बात विस्तार से सदन को बताई है और उनका उल्लेख किया है। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से समाज को०पर उठाने का गरीब आदमी, हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोगों को०पर उठाने का सपना हमारे डॉक्टर भीम राव अम्बेदकर, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा और उनके साथ महात्मा गांधी जी ने देखा था। उनकी सोच थी कि यह वर्ग जब तक हमारे देश की मुख्य

धारा में शामिल नहीं होगा तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं बन सकता है। जिस देश का आधार धर्मनिरपेक्षता है, जाति निरपेक्षता है अगर हम उनको नहीं अपनाते हैं तब तक देश जातिवाद से०पर नहीं उठ सकता है। उनके सपने को साकार करने के लिए आज गरीब, हरिजन और बैकवर्ड क्लास को जो रियायत हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार ने दी है वह अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है और एक मिसाल है। मुख्यमंत्री जी के पिता चौधरी रणबीर सिंह जी ने अपने जीवन से राजनीति को निकाल दिया और समाज सेवा में लगा दिया था। वे अपना जीवन राजनीति से संन्यास लेकर संन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह आम आदमी नही कर सकता है। सभापति महोदय, इस सरकार के द्वारा गरीब हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लड़के और लड़कियों को शिक्षित करने के लिए उनको और अधिकार दिए गए हैं और जिस प्रकार की रियायतें दी गई हैं, यह उनके लिए एक वरदान साबित हो गई हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और इनकी सरकार का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, यह जो बजट अनुमान पेश किया गया है यह हर सरकार पेश करती है। आज से पहले जब भी बजट पेश होना होता था तो आप यह सुनते थे कि कीमतें बढ़ेगी, नए टैक्स लगेंगे। परन्तु इस सरकार ने जब यह बजट अनुमान प्रस्तुत किया तो न तो कीमतें बड़ी हैं और न हो कोई टैक्स लगा है। लेकिन फिर भी ये हर साल बजट अनुमान में प्रदेश की तरक्की के लिए

नई योजनाएं लेकर आते हैं। इसका कारण इनकी निष्ठा और लगन है। आज जिस प्रकार से प्रदेश की साख हिन्दुस्तान में और विदेशों में बड़ी है उसका कारण सिर्फ इनकी नियत साफ होना है। इसी वजह से हरियाणा में विदेशी कम्पनियों ने निवेश किया है। आज इस सरकार की नियत पर लोगों को विश्वास हुआ है। आज हरियाणा की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं और यहां पर निवेश करने के लिए आए हैं। सभापति महोदय, आज भारतवर्ष के सामने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने मंदी का दौर चल रहा है। इस मंदी के दौर में भी हरियाणा सरकार ने 11,000 करोड रुपये का बजट अनुमान प्रस्तुत किया हे, यह अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। जहां तक किसानों की बात है इसमें कोई दो राय नहीं हे कि किसान जो मेहनत करता हे। वह किसी मौका परस्ती या लालच की वजह से नहीं करता है बल्कि वह एक भावनात्मक मेहनत करता है। उसका लगाव है अपने देश से, अपनी जमीन से इसलिए वह न रात देखता है, न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है ओर न बरसात देखता है। वह ओले भी झेलता है, वह बिजली भी झेलता है और वह रात भी झेलता है। लेकिन वह अपना फर्ज मानते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश को अन्न खिलाने का काम करता है। चेयरमेन सर, जिसने उस किसान की बिना कहे परवाह की है वह हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने उसकी टीस को समझते हुए नयी नयी टैक्निक के जरिए, कृषि संयत्रों के जरिए कई रियायतें दी हे। किसान को उसकी कृषि उपज का मूल्य देने की जो सेवा हरियाणा

के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने की है वह काबिलेतारीफ है। चेयरमैन सर, पहले भी ऐसा होता था, पहले ऐसे लोग भी थे जिनके जहन में एक ही बात थी कि अगर किसान तरक्की कर गया, किसान का परिवार पढ़ गया, किसान जागरूक हो गया तो उसको राजनीति में बेवकूफ बनाकर उसके वोट हासिल नहीं कर सकते इसलिए ऐसे लोगों ने किसानों का दमन किया। चेयरमेन सर, आज मुख्यमंत्री जी की फिराखदिली की दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने किसान के उत्थान के लिए जो काम किए हैं वह भी अपने आप में एक मिसाल हैं। लेकिन आज किसान के लिए कुछ और भी करने की जरूरत है। आज एक दौर है जिसके बारे में हमारे साईंटिस्ट और डाक्टर्ज भी कहते हें कि जितना खेती में आज कैमीकल फर्टीलाइजर्स का और पैस्टीसाईडस का इस्तेमाल हो रहा है उसका उतना ही असर अनाज में आ रहा है, उसका उतना ही असर पशुओं के चारे में आ रहा है जिसके कारण आज कुछ लाइलाज बीमारियाँ भी बड़ी हें। चेयरमैन सर, मेरा इस बारे में एक सुझाव है। आज हमारे गन्ने की खेती भी लुप्त होती जा रही है। पहले शुगर मिल्ज कह, 7–7 महीने चलती थीं लेकिन अब ये शुगर मिल्ज भी केवल दो दो महीने ही चलती हैं जिसके कारण वहां अब कितने ही इम्प्लाईज बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। हमें इसके लिए एक पैकेज बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि यह पैकेज धान का होगा, यह पैकेज गन्ने का होगा और यह पैकेज गेहूं का होगा। चेयरमैन सर, यह बहुत जरूरी हो गया है। इसके अलावा खेती के साथ–साथ डेयरी के लिए भी किसान को सहूलियत

मिलनी चाहिए। अगर किसान खेती के साथ ही डेयरी भी करें तो इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और खेती के लिए गोबर की खाद भी मिलेगी। फर्टीलाइजर्स के पूज के लिए हमारे साईटिस्टस जोर दे रहे हें लेकिन अगर हमारे किसान गोबर के खाद का भी उत्पादन करें तो हमको शुद्ध अनाज, शुद्ध सब्जियाँ और पशुओं के लिए शुद्ध चारा मिल सकता है। मेरी इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और सरकार को एक सलाह है कि खेती के साथ–साथ डेयरी भी कम्पलसरी करनी चाहिए और डेयरी के लिए किसान को उसी तरह की सुविधा मिलनी चाहिए जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक एकड़ जमीन पर 9 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा किसानों को दी है। अगर एक एकड़ जमीन पर किसान को डेयरी के लिए भी इतना ही लोन का साधन मुहैय्या हो जाए तो किसान डेयरी की तरफ जरूर जाएगा और यदि ऐसा होगा तो गोबर का खाद भी किसान को मिलेगा। यह खाद नैचुरल खाद है। अगर यह खाद पूज होगा तो इससे हमें शुद्ध अनाज, शुद्ध सब्जियाँ और शुद्ध चारा किसान को मिलेगा।

श्री सभापतिः हर्ष कुमार जी, अब आप वाईड अप करें।

चौधरी हर्ष कुमारः सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। मैं धीरे–धीरे बोलता हूं। चेयरमैन सर, कोई काम एक साथ नहीं होते। ये भी ठीक है कि लोग अपेक्षा भी करते हैं काम करने वाले से। जो काम नहीं करता उससे कोई उम्मीद भी नहीं करता। जो काम करते हैं उनसे उम्मीद बढ़ती है, कामों की

फैहरिस्त बढ़ती हैं आज प्रदेश की जनता इस सरकार से बहुत इच्छाएं और अपेक्षाएं रखती हैं, उम्मीद रखती है। बिगडा हुआ माहौल सरकार को मिला इसमें भी कोई दो राय नहीं। बनाने में समय लगता है बिगाड़ने में कुछ समय नहीं लगता। मैं सरकार को उसके कार्यो के लिए मुबारकबाद देता हूं और हौंसला अफजाई भी करता हूं कि जिस कर्मठता और मेहनत से ये प्रदेश की भलाई में लगे हैं यदि ये इसी तरीके से काम करते चले जाएं तो मालिक इनको और भी समय देगा। मुख्यमंत्री जी व सरकार गांधी जी का, डा० भीमराव अम्बेदकर साहब और चौधरी रणबीर सिंह जी का सपना पूरा करने में लगी है। सरकार ने गांवों में गरीब तबके को जो रिहायशी जाट देने का सिलसिला शुरू किया है यह बहुत सराहनीय है लेकिन मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि लोगों की जेहनियत सही रास्ते पर चलने की नहीं है, अधिकारियों की भी नहीं है, हम जैसे लोगों की भी नही है। प्लाट का जिनका वाजिब हक बनता है उनको उनका हक मिलने में बहुत परेशानी है। इसलिए ऐसे निर्देश जारी किए जाएं कि जिनका प्लाट का हक बनता है उसे उसका हक जो नहीं देगा वह दंड का अधिकारी होगा। जिसका हक बनता है उसको उसका प्लाट बिना मेहनत किए, बगैर जलील हुए मिलना चाहिए।

श्री सभापतिः हर्ष कुमार जी, आपके काफी सारे सुझाव आ चुके हैं। अब आप वाइंड अप कीजिए। टाइम लिमिटेड है।

चौ० हर्ष कुमारः सभापति महोदय, मैं जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले हम गांवों में और शहरों में कुओं से पानी भरते थे लेकिन अब जमीन का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। सरकार ने जो ट्यूबवैल लगाए हैं वे ट्यूबवैल क्ले हो गए हैं। पानी नीचे चला गया है। पहले मीठा पानी होता था अब वह खारा हो गया है। पीने के पानी की बहुत समस्या आ गई है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे मेवात का जो पिछड़ा हुआ इलाका है वहां रैनीवैल स्कीम शुरू की है और उस पर तेजी से काम चल रहा है लेकिन देहातों की हालत ऐसी है कि गरीब आदमियों को पानी नहीं मिलता। जो जोर जबरदस्त आदमी हैं वे अपने हक से अपने अधिकारों से भी फालतू पानी ले लेते हैं। उसके घरों में छिड़काव होता है, फर्श धुलते हैं, उसके पशु नहाते हैं और उससे आगे जो गरीबों का मोहल्ला हे वहां वे लोग बर्तनों की लाइन लगाकर बैठते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको 4–5 मिनट मुश्किल से पानी मिलता है। इस स्मस्या के हल के लिए मेरा सुझाव है कि जिस तरह से बिजली विभाग और सिंचाई विभाग का कानून है कि अगर कोई उनकी चोरी करता है, कोई नुकसान करता है तो उनके पास उनको दण्ड देने का प्रावधान है। इसी तरह से जन–स्वास्थ्य विभाग का भी कानून बनना चाहिए कि अगर कोई अपने हक से ज्यादा पानी लेता है या उस पानी की चोरी करता है तो उसको दण्ड देने का प्रावधान होना चाहिए। आज पानी की

लाईनों में पी०वी०सी० पाईप लगे हुए हैं जिसके जी में आये कुस्सा गर्म किया और पाईप में घुसाया।

श्री सभापतिः हर्ष कुमार जी, घड़ी चल रही है और टाईम लिमिटेड है बाकी माननीय सदस्यों को भी बोलना है इसलिए आप जल्दी कनक्लूड कीजिए। Time will be divided equally and all Members will be entitled.

चौ. हर्ष कुमारः चेयरमैन साहब, अगर आपको मैं बोलता हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बैठ जाता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है।

श्री सभापतिः आप बोलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन टाईम लिमिटेड है। इसलिए जल्दी कनक्लूड कीजिए।

चौ० हर्ष कुमारः चेयरमैन साहब, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज की सरकार के समय में काम करने का माहौल है। एक बात और है कि जब पाईप लीक हो जाती है तो पानी लीक होकर बाहर इकट्ठा हो जाता है जो गंदा हो जाता है। जब पीने का पानी उस पाईप में आयेगा तो फिर वह गन्दा पानी उस पाईप में मिल जायेगा। जब उस पानी को लोग पीते हैं तो बीमारी बढ़ती है इसलिए पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के एस०डी०ओ०, एक्सियन और एस०ई० के हाथ में ऐसा कानून होना चाहिए ताकि वे ऐसे लोगों पर अंकुश लगा सकें जो पानी की पाईप को फोड़ते हैं जहां पर पानी की सप्लाई सही है लेकिन फिर

भी कोई पानी की चोरी करे तो उन पर जुर्माना होना चाहिए। अगर कोई पाईप को तोड़े तो उन पर भी जुर्माना लगना चाहिए। वह वहां घूमते हैं उनको कोई नहीं पूछता उनके कहने से प्रशासन नहीं चलता उन्हें कोई सहयोग देने वाला नहीं है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बात देहात से जुड़ी हुई है और देहात में अलग–अलग मानसिकता के लोग रहते हैं। इसके बारे में मेरा एक सुझाव है कि इसके लिए कोई न कोई कानून बने ताकि गरीब आदमी के लिए भी पानी की व्यवस्था हो सके। जब तक इस प्रकार का कानून नहीं बनेगा तव तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी की नियत है वह पूरी नहीं होगी। सभापति महोदय, हमारा देहात का एक मसला है। अब नेशनल हाई–वे और स्टेट हाई–वें चौड़े हो गये हैं। इनके ठेके प्राईवेट कम्पनियों को दे दिए गए हैं। ये बड़ी–बड़ी प्राइवेट कम्पनियां इनको बना भी रही हैं। इसके अलावा डी०एम० रोड्ज भी का गये हैं और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत दूसरी सड़कें भी बन गई हैं। लेकिन जो हमारी डी०एम० रोड्ज और लिंक रोड्ज बनाये गये हैं उनके लिए पुराने नार्म्स ये हैं कि उनकी कारपैटिंग पांच साल के बाद होती है चाहे वे रोड्ज मार्किट कमेटी ने बनाये हों चाहे पी०डब्ल्यू०डी० ने बनाये हों। यह पांच साल के बाद कारपैटिग का नार्म्स उस समय का बना हुआ है जब इन रोड्स पर बैल गाड़ियां चलती थी और ट्रैक्टर पर 50 मन से ज्यादा माल नहीं ढोया जाता था और बुग्गिया चलती थी या छोटी गाड़ियां चलती थीं। आज जब उन रोडज पर 50–50 टन का सामान लेकर हैवी व्हीकल्ज चलते हैं तो वे सड़कें जल्दी ही

टूट जाती हैं। चाहे वे कहीं की भी सड़कें हों चाहे मार्किट कमेटी की हों, चाहे बी० एण्ड आर० विभाग की हों। मैं उन नार्म्स को बदलने की बात करता हूं जो पांच साल के बाद इन रोड्स की कारपैटिंग करने की है वह समय पांच साल की बजाए तीन साल के होने चाहिएं। यह बदलाव का समय है। इस पुराने ढर्रे से अलग हटकर कुछ काम करने का समय है और इस पांच साल के नार्म्स को तीन साल के लिए होना चाहिए। यह मेरा एक सुझाव है।

श्री सभापतिः हर्ष कुमार जी, कनक्लूड कीजिए।

चौ० हर्ष कुमारः चेयरमैन साहब. जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मेरा लिंक टूट जाता है।

श्री सभापतिः हर्ष कुमार जी, टाईम लिमिटेड है। बाकी माननीय सदस्यों को भी बोलना है इसलिए आप जल्दी कनक्लूड कीजिए।

चौ० हर्ष कुमारः चेयरमैन साहब, मैं भी अपना अधिकार मांग रहा हूं। मुझे पहली बार बोलने के लिए समय दिया गया है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी का हमदर्द हूं लेकिन जिस व्यक्ति से नियत मिल जाती है, जहन मिल जाता है और आदर्श मिल जाते हैं तो उस व्यक्ति का फर्ज है कि वह उसको सुझाव भी दे और मजबूत भी करे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री जी को जनता के सहयोग की

जरूरत है। जब आदमी जनता के लिए इतना कर रहा हो, गरीब के लिए इतना कर रहा हो, इंडस्ट्रीज के लिए इतना कर रहा हो, व्यापारी के लिए इतना कर रहा हो, मजदूर के लिए इतना कर रहा हो और शिक्षा के लिए इतना कर रहा हो तो उसके असली उद् देश्य तक ताकि उसका लक्ष्य पूरा हो, उसकी उस नियत के लिए, उसको जनता का सहयोग और हम जैसों का सहयोग जरूरी है। उनको सहयोग देना हम सबका फर्ज भी है। सभापति महोदय, वैटरनरी के मसले के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह ठीक है कि अस्पतालों की अपग्रेडेशन के काम किए गए, डिस्पैंसरीज को होस्पिटल्ज में अपग्रेड किया गया। मुर्रा नस्ल की बात अलग है। दुग्ध उत्पादन की सरकार ने कोशिशें की हैं लेकिन उसके बाद भी हम लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम वैटरनरी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज हरियाणा जैसे प्रदेश को वैटरनरी यूनिवर्सिटी की जरूरत भी है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि में पशु आता है। कृषि और किसान के लिए वेटरनरी यूनिवर्सिटी जरूरी है। इस यूनिवर्सिटी को चाहे जहां मर्जी बनाया जाए। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से और सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से सिफारिश हे तथा मेरा एक सुझाव है कि मुख्यमंत्री जी के पिता स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जिन्होंने गौ रक्षा आन्दोलन में भाग लिया था, उनमें पशुओं के प्रति बहुत लगाव था, गऊ के प्रति लगाव था, जिनकी किसान के प्रति टीस थी, किसान को उठाने के

लिए जिनकी नियत थी, उन्हीं रणबीर सिंह जी के नाम से यह वैटरनरी यूनिवर्सिटी बना लेनी चाहिए। इसमें हमें कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। (विघ्न) सभापति महोदय, मैं अपनी बात शोर्ट में कहते हुए सिर्फ एक बात कहता हूं कि प्रदेश के लिए यह बहुत कल्याणकारी बजट पेश हुआ है। इस बजट से प्रदेश की जनता की भलाई होगी और प्रदेश का कल्याण होगा। यह बजट जनता के हित का बजट है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यह बजट पास ही न हो बल्कि यह पुरजोर तरीके से पास हो। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि उनके लिए ऐसा सुनहरा मौका नहीं होगा। यह उनके लिए बहुत भाग्यशाली दिन होगा कि वे अपना समर्थन इस बजट को पास करने में दें। सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री सभापतिः अब गीता भुक्कल जी बोलेंगी।

श्रीमती गीता भुक्कल (कलायत, एस०सी०): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, मुझे भी बजट पर बोलने का अवसर दिया जाये। (विघन)

श्री सभापतिः मलिक साहब, प्लीज आप बैठें।

डा० सीता रामः सभापति महोदय, नरेश मलिक की बी०जे०पी० के सदस्य हैं इनको भी बजट पर बोलने का समय मिलना चाहिए।

श्री सभापतिः डॉक्टर साहब, आप इनकी सिफारिश न करें।

डा० सीता रामः सभापति महोदय, बी०जे०पी० पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है मैं इनकी सिफारिया क्यों न करूं। (विघ्न)

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, मुझे यह बताया जाए कि आज जो मैंबर बोलेंगे उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है।

श्री सभापतिः हर मैंबर को दस मिनट का समय बजट पर बोलने के लिए दिया जाता है लेकिन कोई भी मैंबर दस मिनट में अपनी स्पीच पूरी नहीं करता।

श्री नरेश मलिकः सभापति महोदय, आज विपक्ष का एक भी सदस्य नहीं बोला है। क्या मुझे बजट पर आज बोलने का समय दिया जायेगा?

श्री सभापतिः मलिक साहब, प्लीज आप बैठें। कल बजट पर 59 मिनट डॉक्टर सीता राम जी बोले और 14 मिनट ईश्वर सिंह पलाका जी बोले। ये दोनों मैम्बर बजट पर टोटल 72 मिनट बोल चुके हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदया, विपक्ष के भाई क्या महिलाओं के बोलने के खिलाफ हैं। जब भी मैं बोलने के लिए खड़ी होती हूं ये शोर मचाने लग जाते हैं।

डॉ० सीता रामः सभापति महोदय, हम इनके खिलाफ नहीं हैं।

श्री सभापतिः गीता भुक्कल जी, आप बजट पर बोलें और दस मिनट में अपनी स्पीच खत्म करें।

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदय, मैं दस मिनट से ज्यादा समय लूंगी क्योंकि मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बोलने का समय नहीं मिला।

श्री सभापतिः बहन जी, आप एडवोकेट हैं इसलिए आप दस मिनट में एक घंटे की बला कह सकती हैं। प्लीज आप दस मिनट में ही अपनी बात पूरी करें।

12.00 बजे

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदय, विधान सभा के सदन में चौधरी रणबीर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक प्रस्ताव रखा गया था। मैं भी हमारे संविधान सभा के एक मात्र जीवित सदस्य जो कि 1 फरवरी 2009 को अपनी सांसारिक यात्रा क्ये पूर्ण कर पंच तत्व में विलीन हो गये उनको श्रद्धांजलि देती हूं। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे लोक सभा और राज्य

सभा के मैम्बर रहे। इसके अतिरिक्त वे संयुक्त पंजाब के समय में मंत्री भी रहे। वे एक बहुत ही योग्य प्रशासक और सच्चे राष्ट्रवादी थे, वरिष्ठ नेता थे और संविधान सभा के शिल्पकार थे। उन्होंने डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर के साथ मिलकर हिन्दुस्तान के संविधान की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जो कि विश्व में सबसे महानतम और सबसे बड़ा संविधान है। वे गरीबों, दलितों, किसानों और मजदूरों के सबसे बड़े हितैषी थे। वे हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के पिता और हमारे युवा सांसद भाई दीपेन्द्र हुड्डा के दादा जी थे। उनको मैं भी शत्–शत् नमन करती हूं और सभापति महोदय आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। सभापति महोदय, मैं एक मांग करती हूं कि चौधरी रणबीर सिंह जी ने हरियाणा प्रांत अलग से बनाने की मांग सबसे पहले उस समय उठाई थी जिस स्तव हरियाणा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वे पहले आदमी थे जिन्होंने हरियाणा का अस्तित्व न होते हुए भी हरियाणा के हितों की मांग उठाई थी इसलिए उनका स्टैचू लोक सन्स और विधान सभा दोनों जगह लगना चाहिए। सभापति महोदय, अब मैं बजट पर बोलते हुए कहना चाहूंगी कि हमारे वित्तमंत्री जी ने जो 13 फरवरी, 2009 को सदन में बजट पेश किया है मैं उसके अनुमोदन के लिए खड़ी हुई हूं और वित्तमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं कि यह बजट सर्वहितैषी बजट है। यह बजट किसान, मजदूर, शिक्षित बेरोजगार, महिलाओं, विकलांगों, एस०सीज०, रिटायर्ड कर्मचारी, कर्मचारी और

आम आदमी के डिवैल्प ओरियटिड बजट है। सभापति महोदय, बजट के जो आकड़े को हैं वे यह दर्शाते हैं कि किसी भी सरकार की नियत क्या है। हमारी सरकार ने जो यह बजट पेश किया है उससे सरकार की नियत और नीति का पता चलता है। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्यर, सोशल सैक्टर, हैल्थ और एजुकेशन पर विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। बुढ़ापा पैंशन 500 रुपये प्रति मास से बढाकार 500 रुपये प्रति मास किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं इसके अलावा जो आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 10 साल लगातार जिसको यह पैंशन मिलेगी यानि 70 साल की आयु में यह राशि 700 रुपये प्रति मास हो जायेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का भी मैं स्वागत करती हूं। विधवा पैंशन को 200 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 550 रुपये प्रति मास किया गया है, हैंडीकैप्ड की पैंशन बढाई गई है। सभापति महोदय, इसके अलावा हमारी जो महिलायें 60 साल से०पर आयु की हैं वे अगर बसों में यात्रा करेंगी तो उनको किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। विशेष तौर से जो शिक्षित बेरोजगारों के लिए भत्ते की धोषणा की गई है ये यह दर्शाता है कि हमारी सरकार शिक्षा और बेरोजगारी के प्रति कितनी चितिंत है। सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा आगनवाडी वर्कर और हैल्पर के मानदेय में भी बढावा किया गया है इसके लिए भी हमारें माननीय मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पत्य हैं। विशेष तौर से जो इलैक्टिड मैम्बर हैं चाहे जिला परिषद् के चेयरमैन हैं, चाहे जिला परिषद् के मैम्बर

हैं, चाहे ब्लॉक समिति चेयरमैन, वाईस–प्रेजीडैंट, ब्लॉक समिति मैम्बर, सरपंच, पंच नम्बरदार चौकीदार हैं, मैं यह कहना चाहूंगी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष वा वर्ग नहीं रहा जिसका कि हमारी सरकार ने ध्यान न रखा हो। विशेष तौर से खेलों में जो हमारे प्रतिभाशाली युवक वे जो अवाडी थे उनके लिए भी पैंशन भत्ते की जो सुख्यात हमारी सरकार ने की है इसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पत्र है। इसके साथ–साथ लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिन दम्पत्तियों के यहां केवल दो बेटियां हैं उनके बुढ़ापा पैंशन 45 वर्ष से ही शुरू हो जायेगी। यह कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए क्यारी सरकार का एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है। जो हरियाणा का बजट विधान सभा में पेश हुआ है बहुत से दूसरे राज्यों ने थी इसे सराहा हे और पूरे देश में इसकी सराहना हुई है। देश के दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे हैं। हरियाणा के सम्पूर्ण विकास की झलक इस बजट में है और हरियाणा को वाकई देश का नम्बर वन राज्य बनाने का जो प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह ख्य। जी ने किया है वह उसमें एक कडी का काम करता है। सभापति महोदय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का एक सपना था कि पंचायती राज को मजबूत किया जाये। उन्होंने decentralization of powers भी बात की थी। माननीय राजीव गांधी जी के सपने के ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पंचायतों को और ज्यादा अधिकार देने की घोषणा की है उसका भी क्य स्वागत

करते हैं जिसके तहत उन्होंने 5 लाख स्मये तक के कार्य सरपंचों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक के कार्य ब्लॉक समिति के चेयरमैनों के माध्यम से और 15 लाख रुपये तक के कार्य जिला परिषद् के चेयरमैनों के माध्यम से करवाने का प्रावधान करके जो इनकी पावर्ज का दायरा बढाया है यह पंचायती राज को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय क्लम है। सभापति महोदय, आज जहां सारा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है वहीं हरियाणा की विधान सभा में एक ऐल। बजट पेश हुआ जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था को सम्भालकर अच्छी प्रकार से पेश किया गया है। हमारा जो प्रस्तावित 2009–10 का वार्षिक योजना का आबंटन है वह 10 हजार करोड़ रुपये है और वार्षिक योजना में यह वृद्धि तकरीबन अक 50.38 है। भीख बजट में शिक्षा के लिए 1554.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। समाज ज्यादा के लिए 824.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 679.09 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला और बाल विकास के लिए 408 करोड़ स्मये का प्रावधान किया गया है। इस बजट में रोहतक में आई०एम०टी० स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हमारी सरकार ने न केवल जनरल एजुकेशन पर बल्कि टैक्नीक्ल एजुकेशन के साथ–साथ कम्यूटर शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया है यह भी एक सराहनीय कदम है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (सोनीपत) जो कि ग्रामीण अंचल का अपनी किस्म का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि हरियाणा

सरकार द्वारा केवल मात्र महिलाओं के लिए खोला गया है। इसके अलावा खानपुर कलां में ही 30 करोड़ रुपये की लागत से 500 बिस्तर का जो अस्पताल बनाने और एक मैडिकल कालेज खोलने का बजट में प्रस्ताव है यह भी हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा प्रदेश में स्कूल न जाने वाले मैंटली रिटार्डिड बच्चों के लिए हमारी सरकार ने 200 रुपये प्रति मास के भत्ते की शुरुआत की है। इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति के स्कूल जाने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति योजना के तहत या किसी अन्य योजना के तहत पैसा मिलता है। इसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। सभापति महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश गांवों में बसता है। पहले भी बजट पेश होते रहे हैं। यह बजट देखकर हमें महसूस होता है कि इससे पहले वाली सरकारों के बजटों में गांवों की अनदेखी होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने ग्रामीण अंचल में रहने वाली माताओं–बहनों, किसान, मजदूर सबके दर्द को समझा है और पूरी तरह से गांवों के विकास के लिए पूरा पैसा दिया है। गांवों के तालाब जो कि पुराने है। पुणे थे, कई तालाब बंद हो चुके थे, उन गांवों के तालाबों की हालत का सुधार करने के लिए और उनकी रिमाडलिंग के लिए तकरीबन 1 हजार गांव हमारी सरकार ने छांटे हैं जिन पर नरेगा स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपये का कार्य प्रस्तावित है। हमारे श्रमिक भाइयों के घर औद्योगिक इकाईयों से दूर होने की वजह से उनकी जीवन शैली प्रभावित होती थी

इसलिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी श्रमिक आवास मकान बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है और इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से पुलिस कर्मचारियों के लिए भी आवास की अलग से व्यवस्था करने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। विशेष तौर से अगर गांवों की बात करते हैं तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो कि इस समय पूरे हिन्दुस्तान में दिये जा रहे हैं। इस योजना से गांवों में साफ–सफाई और स्वच्छता पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है और उसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। हमारी सरकार इस बात के लिए भी बधाई की पात्र है कि हरियाणा इस बारे में पूरे देश में तीसरे नश्वर पर आया है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि लोग गांवों में खुले में शौच न जाए ताकि साफ–सफाई का पूरा ध्यान रखा जाये। जीवन स्तर का सुधर करने के लिए तकरीबन 11 हजार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। अब अगर आप गांवों में जायें तो गांवों में अब हमारी ज्यादातर सड़कें सी०सी० ब्लॉक्स की बन चुकी हें उसके साथ ही इन सफाई कर्मचारियों ने सफाई का भी बहुत अच्छा काम किया है। सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है जिस तरह से चौकीदारों के लिए वर्दी का भत्ता दिया गया है इसी तरह इन सफाई कर्मचारियों के लिए भी वर्दी मुहैया करवाई जाये और इनके लिए भी महीने में एक अवकाश की घोषणा की जाये। अनुसूचित जाति परिवारों के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत पानी देने की बात हो, चाहे शिक्षा से संबंधित बात हो। मुख्यमंत्री अनुसूचित

जाति निर्मल बस्ती योजना के तहत 50 परसैंट से ज्यादा जहां पर अनुसूचित जाति की आबादी है उन गांवों में मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए जो 50–50 लाख रुपये गांवों में और एक करोड़ रुपये म्यूनिसिपल कमेटीज में देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है उसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। इससे हमारे 391 गांवों का विकास होगा। इस योजना के तहत हमारा आधारभूत ढाँचा जिसमें कम्यूनिटी सैन्टर्ज, चौपालें, पटवारखाने, साइ०सी० की सड़कें और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन स्पे अध्यक्ष महोदय, महात्मा गाँ थी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 2 अक्तूबर को एस०सी०/बी०सी०ए वर्ग को 100–100 गज के प्लॉट देकर महात्मा गाँधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। सरकार द्वारा 100–100 गज के प्लाट देने का जो काम किया गया है यह तारीफ के काबिल है। अध्यक्ष महोदय, 100–100 गज के प्लाट दिये जाने की प्रक्रिया अभी जारी है लेकिन बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम पात्र हैं लेकिन हमारे नाम इसमें शामिल नहीं हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि इसके लिए एक अपील का प्रावधान किया जाये कि जो अपने आपको इसका पात्र समझते हैं लेकिन वे अगर छूट जाते हैं तो वे किसको अपील करें ताकि उनके नामों को भी इसमें शामिल किया जा सके। महिला शक्ति के लिए सरकार ने बहुत सा काम किया है। महिला शक्ति सदन, महिला चौपाल गांव–गांव में बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है यह भी बहुत ही काबिल–ए–तारीफ काम है। हमारी जो सैल्फ हैल्थ ग्रूप की महिलाएं हैं या एस०एम०एस०

की हैं वे इनमें बैठ कर पूरी चर्चा कर सकती हैं और अपने कार्य को निपटा सकती हैं। विशेष तौर से हमारे कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने जो बजट में प्रावधान किया है यह बहुत अच्छा काम किया है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ जहां विश्व मंदी का दौर है फिर भी लगभग 40 परसैंट की वृद्धि इसमें की गई है। हरियाणा देश भर में पहला राज्य है जिसने इतनी वृद्धि की है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार वाकई ही कर्मचारी हितैषी सरकार है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता, उनमें अनुशासन, उनकी जवाबदेही, उनकी गुणवत्ता बहुत जरूरी है और सरकार इन चीजों को भी ध्यान में रखे। जो सिक्सथ पे–कमीशन लागू किया गया है इसमें कुछ कर्मचारी केडर्ज के वेतनमानों में कुछ एनामलीज हैं। सरकार से मैं यह निवेदन करूंगी कि उनकी मांगों पर भी गम्भीरता से विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, बी०पी०एल० परिवारों के लिए हमारी सरकार ने दोबारा सर्वे भी करवाया है और बी०पी०एल० के आईडैंटिफिकेशन मार्क्स भी घरों पर लगाए गए हैं। कई बार जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो देखने में आता है कि कई जगहों पर पक्की कोठियां बनी हुई हैं और उन लोगों के पास ट्रैक्टर हैं लेकिन उनके घरों पर बी०पी०एल० आईडैंटिफिकेशन मार्क्स लगे हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं लेकिन वे अपने नाम बी०पी०एल० सूची में से कटवाने के लिए खुद आगे नहीं आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि इस तरह के जो अपात्र लोग इस सूची में शामिल हो गए हैं उनके नामों को उसी

सूची में से काटने की एक प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। स्पीकर सर, वर्ष 2009 को हमारी सरकार ने 'किसान मजदूर वर्ष' घोषित किया हैं इस सरकार से पहले जो सरकार सत्ता में थी वह अपने आप को किसानों की हितैषी सरकार कहती थी। हमें मालूम है कि उस किसान हितैषी सरकार ने कन्डेला में किस तरह से गोलियां बरसाई थी और हमारे शिमला गांव का समसरूप और कई दूसरे साथियों को गोलियों से भूना गया था। लेकिन हमारी सरकार ने उन परिवारों के व्यक्तियों को नौकरियां भी दी और उन परिवारों को पूरा मान–सम्मान भी दिया। इसके अलावा जो यह जमीन की नीलामी का काला कानून था उसको भी हमारी सरकार ने समाप्त किया है। एक एकड़ वाले किसान भी आज ट्रैक्टर लेने के लिए इलिजिबल हुए हैं जो कि किसान हितैषी सरकार होने का परिचायक है। स्पीकर सर, अपना लोन न चुका सकने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का जो काला कानून था उसको समाप्त करके भी हमारी सरकार ने किसान हितैषी सरकार होने का प्रमाण दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति भूमिहीन हैं, कारीगर, मजदूर हैं, एस०सी०, बी०सी० हैं उन लोगों को भी कम ब्याज दर पर बैकवर्ड क्लासिज निगम या फाईनैंशियल डिवैल्पमैंट कारपोरेशन के तहत ऋण दिलवाये जाने चाहिएं।

श्री अध्यक्षः आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं इसलिए अब आप ककलूड करें।

श्रीमती गीता भुक्कलः स्पीकर सर, मैं केवल दस मिनट का समय और लूंगी।

श्री अध्यक्षः दस मिनट का जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि अभी काफी और आनरेबल मैम्बर्ज ने बोलना है। उनका ध्यान रखना आपका फर्ज बनता है और हमारा फर्ज भी बनता है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस पर भी मुझे बोलने का समय नहीं मिला था।

श्री अध्यक्षः अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरा कहना यह है कि हम दूसरे मैम्बर्ज के साथ ज्यादती कर रहे हैं क्योंकि अभी बोलने वाले मैम्बर्ज बहुत ज्यादा हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः सर, आप जितना समय देंगे मैं उतने समय में ही अपनी बात समाप्तं कर लूंगी।

श्री अध्यक्षः आप दो मिनट में कन्कलूड कर लें।

श्रीमती गीता भुक्कलः स्पीकर सर, मैं अपने हल्के की बहुत जरूरी मांगे रखना चाहती हूं इसलिए मुझे पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री अध्यक्षः आप क्वैश्चन आवर में भी अपनी बात उठा लेती हैं और दूसरी जगहों पर भी उठा लेती हैं। आप एप्रोप्रिऐशन बिल पर बोल लेना।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, हमारे जो एस०सी०,बी०सी० के बहुत से मैरिटोरियस स्टूडैंट्स हैं जो आई०टी०आई० के माध्यम से या दूसरे तरीके से आगे की शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान होना चाहिए। स्पीकर सर, चाहे पंचायत विभाग हो, पी.डब्ल्यू.डी. हो या इरीगेशन डिपार्टमैंट हो काफी पैसा हमारे पास आया हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगी कि इसमें आफिसर्ज की भी एकाउटीबिलिटी होनी चाहिए, उनकी जबावदेही होनी चाहिए और कामों की टाईम लिमिट फिक्स होनी चाहिए तथा सभी डिपार्टमैंट्स की बीच में को–आर्डिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि गांवों में शिडयूल्ड कास्ट्स के रहने वाले लोगों की कई ऐसी गलियां हैं जहां इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के तहत टंकिया–टूँटिया फी दी गई और पाईपलाईन बिछाने का कार्य किया गया है। पाईप लाईन्ज बिछाने के कारण गलियों की हालत काफी बिगड़ गई है औंर काफी गलियां टूट गई हैं। मेरा यह सुझाव है कि ऐसी गलियों की रिपेयर के लिए बजट में प्रावधान किया जाए और दस–दस लाख रुपये हर गली के हिसाब से देने का प्रावधान किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारा कलायत हल्का पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा हे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने वहां के लिए आई०टी०आई० की घोषणा की थी। मेरा निवेदन है कि उसको बनाने का काम अतिशीघ्र शुरू करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि कलायत में बस

स्टैंड बनाने की बहुत पुरानी मांग थी उस बस स्टैंड के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा मिड–डे मील स्कीम के तहत पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मिड–डे मील स्कीम को बढ़ाया गया है। अब आठवीं तक के बच्चों को खाना दिया जाएगा। स्पीकर सर, इसके लिए मैं यह सुझाव दूंगी कि मिड–डे मील के लिए रसोई की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए और भण्डारण के लिए भी ठीक व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि इसमें कई हजार मासूमों की जान की बात होती है इसलिए इस ओर भी पूरा ध्यान दिया जाए और एक ऐसी अच्छी रसोई का निर्माण करवाया जाए या फिर वीटा के माध्यम से या हरियाणा टूरिज्म के माध्यम से बना–बनाया खाना उनको दिया जाए ताकि इसमें पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखा जा सके। स्पीकर सर, इस समय हमारे कलायत और खेड़ी लाम्बा की जो जमीन है वह सेम की वजह से काफी खराब हो गई है, उस बंजर भूमि पर भी ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि हमारे इंग्लिश टीचर्ज लगाने की भी अभी घोषणा की गई है। हमारे स्कूलों में इंग्लिश टीचर्ज का कैडर काफी वीक हैं। ऐलिमैंट्री लैवल पर इंग्लिश के टीचर्ज के साथ ही मिडल क्लास और हाई क्लास में भी इस बात को लागू किया जाए।

श्री अध्यक्षः ठीक है बहन जी, अब आप बैठें, आपकी जो बात रह गई है वह आप लिख कर भिजवा दें that will link into the proceedings.

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हरियाणा में चारों तरफ चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की तारीफ हर तबके द्वारा की जा रही है, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोग हों। आज से चार साल पहले जब भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त हरियाणा की साख दुनिया में गिरी हुई थी और इसकी पर–कैपिटा इन्कम घट गई थी। उस वक्त हरियाणा दल बदल के लिए, करप्शन के लिए बदनाम था, दंगा मस्ती के लिए बदनाम था, हरियाणा के सारे क्रिमिनल उस समय पोलिटिशियन्ज के घरों में सोते थे। यहां तक कि हरियाणा की इन्डस्ट्रीज हरियाणा को छोड़ कर बाहर जा रही थीं और हरियाणा में निवेश कम हो रहा था लेकिन उस वक्त जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने सत्ता सम्भाली तो उन्होंने कहा था कि मैं हरियाणा प्रदेश को नम्बर एक बनाऊंगा। वास्तव में आज हरियाणा प्रदेश देश में नम्बर एक पर है और आज हरियाणा प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो रहा है। हर डिपार्टमैंट के माध्यम से लोगों की बेहतरी के लिए नई–नई योजनाएं बनाई जा रही हें जिससे हरियाणा प्रदेश की बहुत तरक्की हो रही है और पूरे देश में और विदेशों में भी इसकी साख बड़ी है। जो नामी गिरामी क्रिमिनल थे

या तो वे आज प्रदेश को छोड्कर चले गए हैं या हरियाणा की जेलों के अन्दर बंद पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में बिजली बनाने के लिए जो प्रोजैक्टस चल रहे हैं वे इस सरकार के बहुत ही सराहनीय कदम हैं। अध्यक्ष महोदय, उत्तरी हरियाणा में जमीन के पानी के लैवल में बहुत ही गिरावट आती जा रही थी लेकिन इस सरकार के द्वारा यह जो दादूपुर नलवी नहर खोदी गई है यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसका श्रेय हमारे मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से फार्मर्ज कम्यूनिटी के बारे में मैंने ही 1982 लें आवाज उठाई थी कि लैंड मोर्टगेज बैंक और कोआप्रेटिव बैंक्स के अधिकारी किसानों के बच्चों को उठाकर जेलों में डाल देते थे और 40 दिनों तक जेलों में रखते थे और उनका खर्चा भी उनके खाते में ही चढ़ाकर उनको छोड़ा जाता था, जिसकी वजह से उनको बहुत अपमानित होना पड़ता था। इस बारे में मैंने पिछली सरकार के वक्त में भी रिक्वैस्ट की थी कि उनकी कर वसूली का तरीका कमर्शियल बैंकों की तरह हो। इस सरकार ने अब उस काले कानून को खत्म किया है और कहा है कि लैंड मोर्टगेज बैंक के अधिकारी कर वसूली के लिए किसानों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब तो किसान की जमीन को नीलाम भी नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ किसान जब एक ट्रैक्टर के लिए लोन लेता था तो उसके बदले में उसको अपनी तीन एक्क जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। इस सरकार ने फैसला लिया है कि अब किसान को तीन एकड़ जमीन की जगह एक एक्क जमीन ही गिरवी रखनी

पड़ेगी। यह इस सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज जीन्स के जो भाव मिले हैं और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो किसानों की लड़ाई लड़ी है वह बहुत ही सराहनीय है। इसी तरह से गरीब और हरिजनों के बच्चों के लिए वजीफे की स्कीम शुरू की है, चौकीदारों का सम्मान किया है और लोगों के वैल्फेयर के लिए कई नई स्कीमों को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा आज सदन में वृद्धों के लिए एक और घोषणा की गयी हे कि जो वृद्ध दस साल से पेंशन ले रहे हैं उनके लिए सम्मान भत्ता 700 रुपये प्रतिमाह कर दिया है और नए पेंशनर्ज के लिए 500 रुपए के साथ प्रति साल 50 रुपये की वृद्धि की गयी है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य हें। इन सबके बारे में तो हरियाणा के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि यह सरकार इतनी भलाई का काम उनके लिए करेगी। यहां तक कि बेकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए भी वजीफा देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन में कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के वक्त में हरियाणा के लोगों की हेल्थ में और बच्चों की शिक्षा के स्तर में बहुत गिरावट आ गई थी। उन्होंने इन दोनों विषयों में कुछ काम नहीं किया था। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि ये अंग्रेजी के 1000 शिक्षकों को भर्ती करेंगे और उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। यह बहुत ही अच्छा काम है। मेरा इस विषय में निवेदन है कि उनको 6 महीने की नहीं बल्कि एक साल की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस बारे में मेरा यह कहना है कि दुनिया के जो नम्बर वन के मैथ्स, इंग्लिश और साईंस के टीचर्ज

हैं उनसे एक साल के लिए कांट्रैक्ट किया जाए कि वे हमारे टीचर्ज को ट्रेंड करें। जिस क्लास तक टीचर ने पढ़ाना है उसके लिए पहले यह आश्वस्त जरूर कर लिया जाए कि क्या वह उस लैवल की क्लास तक पड़ाने की क्षमता रखता है या नहीं क्योंकि आज यह अति आवश्यक है और यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि एजुकेशन का स्तर गिर रहा है, इसलिए हमें हर कीमत पर इस लड़ाई को लड़ना है। स्पीकर साहब, हरियाणा के बच्चों में बहुत टेलैंट है लेकिन उस टेलैंट को सामने लेकर आने की आवश्यकता है। इसका तरीका यही होगा कि जिस तरह से राई में स्पोर्ट्स स्कूल है उसी तरह से हर जिले में भी स्पोर्ट्स स्कूल बनाने की आवश्यक्ता है। जो हमारे कोचिज हैं, टीचर्ज हैं वे सरकारी खजाने से बड़ी भारी तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन आज अगर उनको आप देखें तो वे किसी भी बच्चे को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। वे स्कूलों में जाते हैं और हाजिरी लगाकर बड़ा भारी अहसान करते हैं कि हम स्कूल आ गए या फिर वे खुद अपनी ही एक्सरसाइज करके चले आते हैं। अम्बाला कैंट में फुटबाल के मैदान में एक भी बच्चा फुटबाल खेलकर नहीं आता है। (विघ्न) कम से कम इस बात की गारंटी जरूर होनी चाहिए कि जो आदमी सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहा है वह बताए तो सही कि उसके कौन–कौम से 100 शिष्य हैं जिसने उनको फुटबाल खेलना सिखाया है, हाकी खेलनी सिखाई है। उसके पास कोई क्लास तो होनी चाहिए ताकि वह बता सके कि उसके ये स्टूडैंट्स हैं। आज इन कोचिज के पास कोई स्टूडैंट ही नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस बात

के लिए उनको बांधा जा सकता है कि तुम बताओ कि तुम्हारे पास कौन से स्टुडैंट्स ग्राउंड में रैगुलर आ रहे हैं। स्पीकर साहब, यह कम्पलसरी भी किया जा सकता है। जर्मनी में हिटलर ने पूरे जर्मनी को बाक्सिंग की ट्रैनिंग देकर दुनिया से लड़ने के लिए तैयार किया था। वहां पर हर बच्चे के लिए– बाक्सिंग सब्जैक्ट कम्पलसरी हो गया था। अगर वहां का बच्चा अच्छा बाक्सर नहीं था तो उसको दसवीं पास नहीं माना जाता था। स्पीकर साहब, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेजों ने उनके बच्चों को नेल पालिश लगवाकर, नाखून बनवाकर और लम्बे–लम्बे बाल बढ़वाकर कमजोर बना दिया था लेकिन तीन–चार साल बाद हिटलर ने वहां पर सब कुछ बदल दिया था। स्पीकर साहब, आपको इस बारे में पता ही है कि बाद में सारी दुनिया से वे लोग लड़े थे और वे तभी लड़ सके थे क्योंकि वे तकडे थे। स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए 12 मिनट दिए हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) के माध्यम से बहुत ज्यादा काम हुए हैं। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में टांगरी के पास एक बांध है उस पर एक रोड बननी है। वह रोड कब तक बन जायेगी?

श्री अध्यक्षः निर्मल सिँह जी, कैप्टन साहब आपके पुराने दोस्त हैं, नफीस दोस्त हैं आप उनसे इस बारे में बात कर लेना।

श्री निर्मल सिंहः सर, आप ठीक कह रहे हैं वे दोस्त तो हैं लेकिन ये मेरे उतने काम नहीं करते हैं जितने में इनके किया करता था। जब मैं पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर था तो उस वक्त मैंने

इनकी और मान साहब की कई स्कीम्ज 100 परसैंट पूरी की थी लेकिन ये हमारे काम नहीं करते हैं ये कमजोर दोस्त हैं। एक सड़क के लिए इन्होंने 9 करोड़ रुपये का बजट रखा जबकि वह 5–6 करोड़ रुपये में ही बन जाएगी। (विघ्न) स्पीकर साहब, 80 हजार कई आबादी के लिए वहां पर आने–जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है वहां पर बहुत थिक है जिसकी वजह से वहां पर हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है। वहां पर 90 हजार लोगों की आबादी है इसलिए अगर वह एक रोड बन जाएगी तो वह लोगों के लिए स्वर्ग के समान हो जाएगी।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): स्पीकर साहव, निर्मल सिंह जी के कहने पर ही इनके हल्के में मंसूरपुर लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम पर काम करवाया गया था।

श्री निर्मल सिंहः सर, यह भी कोई बात है। 6 साल पुरानी स्कीम को रिवाइज्ड करके ये मुझे चाकलेट खिलाने लग रहे हैं। 2700 क्यूसिक का वह नाला है ओम प्रकाश चौटाला ने वह नाला मेरी वजह से ही बंद कर दिया था। अगर ऐसा न होता तो चार सन पहले ही' उसमें पानी आ जाता।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, हमें इनका पूरा ध्यान है।

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, जब पूरे स्टेट में चहुंमुखी तरक्की हो रही है और बहुत ज्यादा पैसा बजट के माध्यम

से खर्च होने जा रहा है तो से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। सारे नदी नाले अम्बाला से ही होकर गुजरते हैं। पहाड़ की तलहटी में अम्बाला जिला पड़ता है इसलिए जब फ्लड आता है तो सबसे ज्यादा नुक्सान अम्बाला जिले का ही होता है। जब नहरी पानी की बात आती है तो मात्र एक नंगल लिफ्ट इरीगेशन स्कीम पुराने अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में ऐसी है जिसने आज तक 65 क्यूसिक से ज्यादा पानी नहीं उठाया है इसलिए पानी में हमारा शेयर कहां है? ये 2700 क्यूसिक का नाला बनाकर हमें दबाने लग रहे है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय दादूपुर नलवी नहर भी इनके हल्के में है उस पर हमने 287 करले रुपये की राशि खर्च की है। जहां तक इन्होंने जो टांगरी की सड़क की बात की है उसका हम बाकायदा सर्वे करवा रहे हूँ। मैं इनको एक ही आश्वासन दे सकता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि टांगरी वाली रोड को हम जल्दी बनवाएं।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, निर्मल सिंह जी ने जिस सड़क की बात कही है उसकी ओर जरूर व्यान दें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया है कि इनकी जो सड़क है उसका हम सर्वे करवाकर प्रपोजल बनवाकर और ऐस्टीमेट बनवाकर इनकी सड़क को बनवाएंगे।

श्री निर्मल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में मोहडा में 1991 मे एक पीली क्लीनिक बनना था लेकिन वह नहीं बना।' उसके बाद कई पीली क्लीनिक्स पर काम चल रहा है लेकिन मोहडा का पीली क्लीनिक नहीं बना इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के का भी पॉली क्लीनिक बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (नौल्था): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। वित्त मंत्री जी ने हाउस के अंदर जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। हमारी सरकार ने बहुत ही विकासात्मक और टैक्स रहित बजट पेश किया है जिससे हम समझते हैं कि हरियाणा में बहुत बड़ी तरक्की होगी। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले चार वर्षो के शासन काल में विकास की झड़ी लगा दी है। मुझे पहले भी कई बार हाउस में चुनकर आने का मौका मिला है। उस समय मैं देखती थी कि कोई एम०एल०ए० अगर 2–4 किलो मीटर की सड़क बनवा लेता था और 2–4 स्कूल खुलवा लेता था या अपग्रेड करवा लेता था तो वह समझता था कि मैंने बहुत काम करवा लिये। अब तो हम सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी से किसी काम के बारे में बात करेंगे तो उससे पिछले ही मुख्यमंत्री जी उस काम को करवाने की घोषणा कर देते हैं। इस देश को आजादी दिलवाने में, इस देश

के विकास में, लोकसभा में, विधान सभा में, हर क्षेत्र में चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। ऐसा महान सपूत पैदा होना मुश्किल है। उनकी जितनी भी हम सराहना करें उतनी थोड़ी है। मेरी प्रार्थना है कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की याद में पार्लियामैंट के सैंट्रल हाल में उनकी मूर्ति जरूर लगनी चाहिए। दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था वहां एक बहुत बढ़िया संस्था बनाई जाए जिसमें इस तरह की किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि अगर स्कूलों में उनकी जीवनी को किताबों में लगाया जाए तो आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा कि देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली। देश को आजादी दिलवाने के लिए कई लोग घर परिवार छोड़ कर जेलों में रहे, देश की आजादी में ऐसे दीवाने हुए कि उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, बच्चों की परवाह तक नहीं की। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4 साल में इतना अभूतपूर्व विकास प्रदेश के अंदर किया है कि यदि उसको गिनाने. लगें, बोलने लगें तो सारा दिन हमें इसके लिए चाहिए। किसी भी क्षेत्र में देख लें, शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, सड्कों के बारे में देख लें, हैल्थ के मामले में देख लें सभी क्षेत्रों में बहुत काम हुआ है। कल परसों पैंशनों में व मानदेय के मामले में हरेक आदमी को भारी राहत दी है। उनके इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनका शब्दों में वर्णन संभव नहीं हे। मुझे तो वह समय भी याद है कि जब महिलाओं को पंचायतों के अंदर सिर्फ

मैंबर बनने तक का ही अधिकार था। मैं माननीय स्व० श्री राजीव गांधी जी की आभारी हूं कि उन्होंने महिलाओं को और हरिजनों को सभी पदों में 20 परसैंट और सभी हरिजन महिलाओं को सभी पदों में तीसरा हिस्सा दिया। उससे हमारी महिलाओं में कितनी बड़ी जागृति आई, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी तक हमारे कुछ भाई यानी उन महिलाओं के पति उनके अधिकारों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह दिन दूर नहीं जब वे महिलाएं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से संभाल पाएंगी। उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी की ज्यादा बेटियां हैं उसके लिए क्या साधन हैं, गरीब बच्चे हैं, हरिजन हैं उनकी पढ़ाई के क्या साधन हैं इन सारी चीजों के लिए राहत दी गई है। स्पीकर साहब, मैं जिस गुरुकुल में पड़ती थी उसमें 3–4 कच्चे कमरे होते थे और फूस के छप्पर का एक कच्चा बरामदा होता था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में यह गुरुकुल इतना बड़ा विश्वविद्यालय बन जायेगा। इस बात के लिए मैं इस सरकार की बहुत आभारी हूं। महापुरुष भाई भगत फूल सिंह जी ने अपनी कुर्बानी देकर इस संस्था को कायम किया था। उससे भी ज्यादा कुर्बानी उनकी बेटी सुभाषिनी जी की थी जिसने अपनी सारी जिन्दगी, जवानी और बुढ़ापा इस गुरुकुल के विकास के लिए लगा दिया। इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया कि उस गुरुकुल को एक विश्वविद्यालय बना दिया और वहां पर बहुत बड़ा होस्पिटल तथा

दूसरी सब प्रकार की ट्रेनिंग देने के संस्थान खोले हैं इसके बारे में मैं आज बहुत गर्व के साथ कह सकती हूं कि वह ऐसी संस्था है जो लड़कियों के अन्दर बहुत अच्छे संस्कार भरती है और उनको स्वावलम्बी बनाती है। पढ़ाई तो दूसरे स्कूलों और कालेजों में भी होती है लेकिन ऐसी पढ़ाई नहीं होती जैसी इस विश्वविद्यालय में होती हे। इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए मैं मुख्यमत्री जी का जितना आभार प्रकट करूं उतना ही थोड़ा है। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने किसानों के कर्जे माफ किये, बिजली के बिल माफ किये। जो किसान कर्जा लेता है उसके ब्याज माफ किये। लेकिन मैं समझती हूं कि गरीब आदमी का ब्याज तो माफ किया गया लेकिन उसका कर्जा भी माफ करना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमत्री जो ऐसा कर देते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी खजाने की झोली भरे हुए हैं इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है इसलिए मैं इनसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि गरीब आदमी जिसके पास अपनी जमीन नहीं है उनके कर्ज लेने की लिमिट जो दस हजार है उसको 50 हजार रुपये किया जाए। ब्याज की दर भी उनके लिए ज्यादा है जबकि यह कम होनी चाहिए। जो नॉन एग्रीकल्चर लोग हैं उनके कर्जे की ब्याज दर ज्यादा है। इसलिए उनके लिए भी ब्याज की दर कम करनी चाहिए। ऐसा करने से उनको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। कोई व्यक्ति बुग्गी लेता है या कोई दूसरा कार्य करता है तो उसको कम ब्याज दर पर लोन देने से काफी फायदा हो सकता है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहती हूं

कि बी०पी०एल० के कार्ड जितने बनने चाहिए थे उससे भी ज्यादा सरकार ने बनाये हैं लेकिन उससे भी पूरा काम नहीं चलता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार किसानों की हालत देखते हुए फसलों के भाव बढ़ाये हैं यह बहुत अच्छी बात है। किसान जो अपने खेत में मेहनत करता है उसकी मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन गरीब आदमी को गेहूं खरीद कर खाना पड़ता है। जिस प्रकार से बी०पी०एल० कार्ड होल्डर्ज को गेहूं और तेल बहुत सस्ता मिलता है उसी प्रकार अगर हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को हम राशन कार्ड के हिसाब से उसी भाव से राशन दें जो बी०पी०एल० कार्ड होल्डर को मिलता है तो बी०पी०एल० कार्ड की मांग भी कम हो जायेगी और उनको राहत भी मिलेगी। इसके साथ–साथ मैं यह बात कहना चाहती हूं कि मिट्टी का तेल पानीपत में नहीं मिल पा रहा है जबकि वहां पर तो मजदूर तबका ज्यादा रहता है इसलिए वहां पर मिट्टी के तेल का प्रबन्ध करना चाहिए जिससे उन गरीब आदमियों को राहत मिल सके। वैसे तो हरिजनों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले हरिजन भाइयों ने कभी पक्की गली पर चलकर नहीं देखा था लेकिन आज हरिजन भाइयों के मौहल्लों में सीमेंटिड गलियां बनी हुई हैं जिनकी नहीं बनी हैं वे भी शीघ्र बन जायेंगी। काम करने में कोई कमी नहीं है। जिस पानी के बंटवारे के लिए लोग इंतजार करते थे कई–कई हफ्ते उनका पानी का नम्बर नहीं आता था जबकि कुछ एरिया ऐसा था जहां 24 घण्टे पानी चलता था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने पानी का बंटवारा

बराबर करके दिखा दिया है कि बेइंसाफी वाली बात हम नहीं होने दंगे। इसीलिए ये विकास पुरुष और इंसाफ पुरुष के नाम से मशहूर हुए। इनके पास दुश्मन भी आ जाए और कोई मांग करे तो उसके लिए ये ना नहीं कहते। यही चीज जो गरीब आदमी की दुआ है वह आदमी को आगे बढ़ाती है। सरकार ने विकास के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी है इसकी जितनी भी बढ़ाई की जाए उतनी ही कम है। आज भी ये विकास के कामों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इन्होंने बजट में किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा। सभी वर्गो को कोई न कोई फायदा पहुंचाया है। कहीं पैंशन में बढ़ौतरी की गई है तो कहीं मानदेय बढ़ाया गया है। मेरी बहन गीता भुक्कल से मैं सहमत हूं कि स्वीपर्ज को वर्दी मिलनी चाहिए। इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि स्वीपर्ज की भर्ती पुरानी जनगणना के हिसाव से हुई है। कई गांव बहुत बड़े–बड़े हैं उनमें हम स्वीपर्ज की कमी महसूस करते हैं। स्वीपर्ज की और भर्ती होनी चाहिए। स्वीपर्ज ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको जो सारी उम्र गंदा उठाना पड़ता है, क्या कोई सरकार ऐसी आएगी और उनकी इतनी तनख्वाह बांधेगी जिससे वे शान के साथ जिएंगें। आज किसी की कोई पुरानी मांग ऐसी नहीं है जो पूरी न हुई हो। अपोजीशन के भाइयों ने तो शोर मचाना होता है इनके पास ऐसी कोई बात नहीं रह जाती जिसकी ये मांग करें।

श्री अध्यक्षः बहन जी, आप कंक्ल्यूड करें। आपको बोलते हुए 11 मिनट हो गए

श्रीमती प्रसन्नी देवीः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मेरे भाइयों और बहनों ने बता दिया, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती। मैं जोरदार शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करती हूं और कहना चाहती हूं कि इस बजट को पास कर दिया जाए। जय हिन्द। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जो भी सदस्य बोलना चाहते हैं उन सभी को बोलने के लिए समय दिया जाएगा। (विघ्न) कहीं ऐसा न हो कि आप इधर–उधर चले जाएं और सुनने के लिए कोई न बैठा हो।

श्री बलवंत सिंह (सढौरा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। वर्ष 2009– 10 का जो बजट वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है वह आकडों का खेल था। सत्ता पक्ष की ओर से वाह वाही की जा रही है। अगर ''बजट एट ए ग्लाल ' देखा जाए तो इसमें प्रदेश के विकास के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोडस, एग्रीकल्चर, पॉवर और जो दूसरी मदें हैं जिनसे प्रदेश का विकास होगा उनके लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। अगर बजट की एक झलक देखें तो उसमें हर साल कटौती हुई है, कमी हुई है। एक तरफ रिवैन्यू रिसीट्स हैं और दूसरी तरफ प्लान एक्सपैंडीचर है। रिवैन्यू रिसीट् स घटती जा रही हैं और प्लान एक्सपैंडीचर बढ़ता जा रहा हे। वर्ष 2005–06 में रिवैन्यू रिसीट्स में 29 परसैंट इक्रीज थी, वर्ष

2007–08 में यह 17 परसैंट रह गयी, वर्ष 2009–09 में 10 परसैंट और वर्ष 2002– 10 में केवल 3 परसैंट इन्क्रीज रह गयी। दूसरी तरफ बजट में घाटा योजना खर्च में वर्ष 2009– 10 में वर्ष 2008–09 के मुकाबले 3 प्रतिशत की इन्क्रीज रह गई है जिससे हमारी रैवेन्यू रिसीट्स की बढ़ोतरी अनुमानित 666.40 प्रतिशत है हमने जो संशोधित प्लान के मुकाबले 35 प्रतिशत अधिक दिखाई है इसमें 2905 करोड़ रुपये कहां से आयेंगे, यह सोचने का विषय है? स्पीकर सर, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन आपने हमारा समय बांध रखा है इसलिए मैं कुछ विशेष बातें ही कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई की बात है मौजूदा सरकार किसान हितैषी होने के बड़े–बड़े दावे कर रही है। सिंचाई के लिए प्लान बजट में वर्थ 2007–08 में 1026 करोड़ रुपये खर्च किए थे। वर्ष 2008–09 में 885.76 करोड़ रुपये और वर्ष 2009–10 में यह खर्चा घटाकर 871.72 करोड़ रुपये कर दिया गया। एक तरफ तो कहते हैं कि सिंचाई के क्षेत्र में हम विकास करेंगे, तरक्की करेंगे और दूसरी तरफ ये बजट में पैसे का प्रोविजन कम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि सरकार किस प्रकार से बिना पैसे के अपनी स्कीम्ज को पूरा करेगी। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई व्यवस्था किसानों के लिए प्रोपर होना बहुत जरूरी है क्योंकि सिंचाई के बिना खेती नहीं हो सकती। हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारा देश कृषि पर निर्भर है और यदि हम इसकी

तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारे देश और प्रदेश का विकास कहां से होगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पावर जनरेशन के बारे में बात करना चाहूंगा कि सरकार वर्ष 2010 – 11 तक 5000 मेगावाट बिजली पैदा करने का दावा कर रही है। यदि बजट एट ए ग्लांस को देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2007–08 में बिजली के लिए 3422.12 करोड़ रुपये, वर्ष 2008–09 में 868.74 करोड़ रुपये खर्च किए गए और वर्ष 2009– 10 में इसके लिए 1339.81 करोड़ रुपये का बजट में प्रोविजन किया गया है। इतने कम पैसे का प्रोविजन करके ये किस तरह से बिजली में सुधार कर पायेंगे। सरकार जिन बड़े–बड़े प्रोजैक्ट्स का जिक्र करती है उनको ये इतने कम पैसे में कैसे बना पायेंगे यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सोशल वैल्फेयर की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी बड़े काबिल वित्त मंत्री हैं पर पता नहीं बजट से' सिर्फ आधे–पौने घंटे पहले ही मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी घोषणाएं कर दी जिनके लिए बजट में पैसे का प्रोविजन भी नहीं है। इस तरह बजट से पहले मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं ये सिर्फ वाह–वाही लूटने के लिए की हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इन्होंने बजट में प्रोविजन किए बगैर ही बुढ़ापा पैंशन बढ़ा दी, बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया, विकलांग भत्ता बड़ा दिया और किसी की पैंशन 500

रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी, किसी की पैंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी। (विघ्न) ये सब बातें अब मुख्यमंत्री जी के दिमाग में क्यों आई, चार साल पहले क्यों नहीं आई। इनकी सरकार को बने हुए चार साल हो गए उस समय इन्होंने बुढ़ापा पैंशन क्यों नहीं बढ़ाई। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने आनन–फानन में की हैं क्योंकि चुनाव सिर पर हैं तथा केवल वोट बटोरने के लिए राजनीति की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इण्डस्ट्रीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि सत्तापक्ष की तरफ से बहुत प्रचार किया जा रहा है कि प्रदेश में बहुत सी इण्डस्ट्रीज लगाई जायेगी जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आकड़े हैं यदि उनकी तरफ देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2007–08 में इण्डस्ट्रीज के लिए प्लान बजट में 116 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2008–09 में 143 करोड़ रुपये खर्च किए गए और वर्ष 2009– 10 में यह पैसा घटकर 64 करोड़ रुपये ही रह गया है। क्या इस तरह से बजट में पैसा कम करने से इण्डस्ट्रीज बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होगी और प्रदेश का विकास होगा? अध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवहन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा हमारे परिवहन मंत्री जी बड़े काबिल वजीर हैं। लेकिन मैं आकड़ों का जिक्र करना चाहूंगा कि प्लान बजट में परिवहन के लिए वर्ष 2007–08 में छठउ7 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वर्ष 2008–09 में प्लान बजट में 150.21 करोड़ रुपये खर्च किए गए और वर्ष 2009.10 में

ये पैसा घटकर 109.25 करोड़ रुपये ही रह गया है। इस तरह से परिवहन का विकास कैसे होगा। जो बजट परिवहन विभाग के लिए वर्ष 2009– 10 के लिए रखा गया है उससे कैसे ट्रांसपोर्ट की और गाड़ियां आयेंगी और कैसे ट्रांसपोर्ट को हम नम्बर एक पर लेकर जायेंगे। स्पीकर सर, हर मद के लिए जो बेसिक इंफ्रास्टक्चर जरूरी है सरकार उसके खर्च में हर वर्ष कटौती करती जा रही है। स्पीकर सर, मेरे कहने का भाव यह है कि आज जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि प्रदेश के विकास की गति बढ़ेगी सरकार उसके हर फील्ड ले कमी कर रही हे। स्पीकर सर, यह मेरे कहने की बात नहीं है बल्कि यह सब प्रदेश की जनता कह रही है। स्पीकर सर, अगर मैं एक–एक प्यायंट पर बोलूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। मेरी तो आपके माध्यम से सरकार से यही प्रार्थना है कि जो सरकार द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं और उनके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है उसमें यह क्लीयर किया जाये कि जहां हम इन सैक्टरों में विकास की गति को तेज करेंगे वहीं हम इसको कैसे पूरा कर पायेंगे क्योंकि ये बजट अधिवेशन तो है लेकिन साथ–साथ यह चुनावी अधिवेशन भी है। स्पीकर सर, यह चुनाव का साल है।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): स्पीकर सर, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, जो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि यह चुनावी वर्ष है और इसीलिए यह अधिवेशन भी चुनावी अधिवेशन है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय

साथी को यह बताना चाहूंगा कि न तो यह चुनावी वर्ष है और न ही यह अधिवेशन चुनावी अधिवेशन है क्योंकि स्टेट असैम्बली के चुनाव में अभी एक वर्ष से ज्यादा का समय शेष रहता है। जो इस साल चुनाव हो रहे हैं वे विधान सभा के न होकर लोक सभा के चुनाव हैं और इसी प्रकार से हमारा बजट भी केन्द्र का बजट न होकर स्टेट का बजट है।

श्री बलवंत सिंहः स्पीकर सर, इसी प्रकार से वाटर सप्लाई एण्ड सैनीटेशन बहुत ही अहम् विभाग है। उस पर वर्ष 2007–08 में हमारे टोटल बजट का 5.10 प्रतिशत खर्च किया गया, वर्ष 2008–09 में 4.68 प्रतिशत खर्च किया गया और वर्ष 2009–10 में 4.31 करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें इसको बढ़ाना चाहिए था लेकिन सरकार द्वारा इसे कम किया जा रहा है। इससे आम आदमी का जीवन बेहतर न होकर और ज्यादा बदतर ही होगा। स्पीकर सर, सोशल वैल्फेयर में भी सरकार द्वारा बहुत ज्यादा घोषणाएं की गई हैं जिनके लिए बजट में और धन अलाट किया जाना चाहिए था जबकि वर्ष 2007– 08 में इसके लिए बजट का 4.12 परसैंट, वर्ष 2008–09 में 4.79 परसैंट और 2009– 10 में 3.99 परसैंट सरकार द्वारा बजट में प्रावधान रखा गया है। इस धनराशि से किस प्रकार से सरकार द्वारा घोषित योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकेगा। स्पीकर सर, इस सबका सारांश यही है कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट में जो आकड़े दर्शाये गये हैं उनमें कहीं भी यह दिखाई नहीं देता कि स्टेट बहुत ज्यादा

तरक्की करेगा, स्टेट में बहुत बड़ी इण्डस्ट्रीज लगेगी, प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश में कहीं पर इस प्रकार की किसी अन्य योजना को अमलीजामा पहनाया जायेगा। स्पीकर सर, अब मैं स्टेट में बिजली की हालत के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। स्पीकर सर, यह बात ठीक है कि सत्ता पक्ष हाउस में मैजोरिटी के बल पर कुछ भी साबित कर सकता है। स्पीकर सर, आज गांवों में बिजली की हालत चिंताजनक है। यह मैं नही कह रहा हूं बल्कि यह प्रदेश का प्रत्येक आदमी कह रहा है। स्पीकर सर, जहां तक प्रदेश और देश में महंगाई का सम्बन्ध है इससे भी प्रदेश और देश का गरीब, अमीर, मजदूर और किसान बुरी तरह से पीड़ित, दु:खी और परेशान है। आज महंगाई पर अंकुश लगाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आज सरकार द्वारा महंगाई कौ रोकने के लिए किसी प्रकार की विशेष सबसिडी की घोषणा किये जाने की निहायत सख्त जरूरत है। स्पीकर सर, इसके साथ ही आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): स्पीकर सर. किसी प्रान्त या मुल्क की प्रगति का अगर कोई इंडैक्स है, कोई माप–तोल है तो वह उसका इंफास्ट्रक्यर है। स्पीकर सर, मुझे बड़े दु:ख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि इस सरकार के आने से पहले हरियाणा में न तो अच्छी सड़कें थी, न आर०ओ०बी० थे और न ही एस०टी०पी० थे, न ही गांवों और शहरों में पीने के

साफ एवं स्वच्छ पीने के पानी की समुचित व्यवस्था थी और न ही बिजली थी। इस सरकार ने बहुत ही थोड़े समय में हरियाणा का इकास्टक्यर जो पिछले 40 साल में नहीं बना था उसको बनाने की कोशिश की है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं कह चुका हूं कि सड़क, आर०ओ०बी०, सैनीटेशन, ड्रिकिंग वाटर, टैक्नीकल एजुकेशन, थर्मल पॉवर और नहरों आदि के बराबर के बंटवारे के काम सरकार ने किये हें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी भी बहुत से काम बाकी हैं इस प्रान्त को और आगे तेजी से ले जाने के लिए इस सरकार ने ऐलान भी किये हैं और इस सरकार की मंशा भी है। मेरा कहना यह है कि हमारा जो कम्यूनिकेशन है जिसमें रोड्स भी हैं, जिसमें रेलें भी हैं उसमें अभी हरियाणा में बहुत काम करने बाकी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कुण्डली–मानेसर–पलवल हाइवे सरकार बनाने लग रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि पूरे हरियाणा से जो माल जायेगा, जो ट्रैफिक जायेगा वह एक्सप्रैस हाइवे पर कैसे पहुंचेगा? हरियाणा की पुरानी सरकारें इस बारे में केवल चर्चा करती रही लेकिन कोई भी कार्य नहीं कर सकी। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि एक एक्सप्रैस हाइवे अगर चण्डीगढ़ से पंचकूला, अम्बाला और यमुनानगर के बीच से होते हुए यमुना नदी के साथ–साथ के०एम०पी० एक्सप्रैस हाइवे में मिला दिया जाये तो उससे वह पूरा एरिया भी उस रोड से जुड़ जायेगा और पंजाब और हिमाचल के एरिया से भी जो व्हीकल आते हैं वे भी वहां पहुंच सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार को दूसरी सलाह यह है

कि एक दूसरा एक्सप्रैस हाइवे बनना चाहिए जो चण्डीगढ़ से अम्बाला, कैथल, जीन्द और रोहतक होते हुए के०एम०पी० एक्सप्रैस हाइवे में मिला दिया जाये और तीसरा एक्सप्रैस हाइवे बनना चाहिए जो इन्हीं सड्कों से हिसार, भिवानी, नारनौल, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव होते हुए के०एम०पी० एक्सप्रैस हाइवे में मिला दिया जाये। ये अगर 3 एक्सप्रैस हाइवे हमारी सरकार बना सकेगी तो मैं समझता हूं इंडस्ट्री, कामर्स और एग्रीकल्चर के मामले में हरियाणा को बड़ा भारी बूस्ट मिलेगा और हरियाणा का नाम प्रोग्रैसिव स्टेट में आ जायेगा। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा बनने के बाद भी और हरियाणा बनने से पहले भी, इस एरिया में जिसको हरियाणा कहते हैं रेलवे ने कोई लम्बे–चौड़े काम नहीं किये हैं। चौधरी बंसीलाल जी ने तो एक रेलवे लाईन रोहतक–भिवानी निकाली थी और उसके बाद आज की सरकार भी 2 –3 छोटे–छोटे रेलवे लिंक्स बनवाने लग रही है जैसे रेवाड़ी–झज्जर और पलवल की हैं लेकिन ये बहुत ही कम हैं। चूंकि चौधरी बंसीलाल जी के बाद कोई भी रेलवे मंत्री इस एरिया से नहीं बना है इसलिए हमारा रेलवे में बहुत ही कम हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है जो अनाज का भण्डारण करता है। एक रेलवे लाईन पानीपत से सफीदों, असन्ध, राजौंद, कैथल और उससे आगे पंजाब के इलाके में खनौरी, पांतडा, संगरूर, मलेरकोटला और लुधियाना में मिल जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, पानीपत से लुधियाना की यह रेलवे लाईन हरियाणा के जिस इलाके में से

जायेगी उससे हरियाणा की इकानोमी को बहुत बड़ा स्म मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह जो कम्यूनिकेशन गैप है, सरकार इस पर गौर करे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने और बहुत–सी बातों के लिए भी बजट में काफी प्रोविजन किया है, ध्यान भी दिया है लेकिन अम्मी भी एक और एरिया ऐसा है, ऐसा जोन है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और वह है मैडीकल हैल्थ। हालांकि मैडीकल हैल्थ में शिक्षा की भी काफी की है। आज भी हजारों गांव हरियाणा के ऐसे हैं जो स्वास्थ्य की सुविधाओं से पूर्ण रूप से वंचित हैं। गांवों में कोई मैडीकल फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग बनी भी है तो वहां डॉक्टर्स नहीं हैं, इक्विपमैंट्स नहीं है जिसका आज नतीजा यह है कि गरीब से गरीब आदमी को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज के लिए शहर की तरफ दौड़ना पड़ता है। प्राईवेट डॉक्टर्स जिन्होंने लूट मचा रखी है, उनके०पर निर्भर रहना पड़ता है इसलिए इसके लिए सरकार को बहुत स्पैशल उपाय करने पड़ेंगे। मेरा सुझाव है कि सरकार को कम से कम दो मैडीकल कालेज और खोलने चाहिएं। एक तो जो गोहाना के पास गुरुकुल है वहां बनाने लग रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। स्पीकर सर, जो छः पुराने और बड़े–बड़े जिले हैं उनके अन्दर सुपर स्पैशलिटी होस्पीटल्ज बनाए जा रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत इलाका बाकी है जैसे करनाल और कैथल का इलाका है, यहां पर भी मैडीकल कॉलेज बनाया जाना चाहिए और

500 बैडज का होस्पीटल बनना चाहिए ताकि पूरे एरिया के लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके। हर बड़े गांव में होस्पीटल होने चाहिएं। मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत ज्यादा रुपये की जरूरत हे लेकिन सरकार का यह निशाना होना चाहिएं। यदि इसके लिए दूसरे काम बंद करने पड़े तब भी लोगों को यह सहूलियत मुहैय्या करवाई ही जानी चाहिए क्योंकि अगर लोगों की सेहत अच्छी नहीं होगी तो हम लोग चाहे कुछ भी कर लें, सरकार उनको कितनी भी सहूलियत दे दे लेकिन अच्छे स्वास्थ्य और सेहत के बिना प्रदेश भी तरक्की नहीं कर सकता है इसलिए लोगों की अच्छी सेहत के लिए सरकार को पूरे उपाय करने चाहिएं। स्पीकर सर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कृषि जगत में आज हरियाणा प्रदेश ने बहुत तरक्की की है और किसान खुशहाल हुआ है। सरकार ने किसान को बेशुमार कन्सैशन्ज दिये हैं लेकिन खेती के साथ–साथ ही जो छोटे जमींदार हैं, एक–एक दो–दो किल्ले वाले जो किसान हैं, सीमान्त किसान हैं, बिना जमीन वाले लोग हैं, जो खेती के साथ जुड़े हुए हैं और भूमिहीन लोग हैं, उनका गुजारा पशुपालन से होता था। जब फसल अच्छी नहीं होती थी और नहरी पानी भी नहीं होता था तब भी पशुपालन किसान के गुजारे का बहुत अच्छा साधन हुआ करता था लेकिन आज इस क्षेत्र में आगे जाने की बजाय हम पीछे चले गये हैं। स्पीकर सर, मुझे याद है कि जब मैं छोटा होता था तो हम देखते थे कि हर जिले में ही नहीं सब–डिवीजन में भी बड़े–बड़े पशु मेले लगते थे लेकिन आज वे पशु नदारद हैं, ऐसे मेले गायब हो गये हैं। छोटा

किसान पशु बेच कर, गांव में बछड़े बेच कर, भैंस की कटडी और दूसरी छोटी–मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा चलाता था और अपनी जिन्दगी का निर्वहन करता था। पशुपालन, जो कि खेती कै साथ सब से बधू व्यवसाय हुआ करता था, आज उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि सरकार इसकी तरफ भी पूरा ध्यान देने की कृपा करे। स्पीकर सर, दो साल पहले जब आपने मुझे पी०ए०सी० का चेयरमैन बनाया था तो उस वक्त हम कमेटी के साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार गये थे और हमने यह सिफारिश की थी कि जो वैटरनिटी होस्पीटल्ज हैं इनको यूनिवर्सिटीज बना दिया जाए। डिस्पैंसरीज में भी पशुओं के आहार, उनकी दवा–दारू और उनके इलाज की बड़ी भारी कमी है। स्पीकर सर, हरियाणा में तो एक से ज्यादा वैटरनिटी यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं। इन यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढेंगे वे वैटरनिटी के क्षेत्र में पूरे देश में जा सकते हैं। विदेशों में भी उनके लिए काफी डिमांड होगी इसलिए वे विदेश में भी जा सकते हैं। हरियाणा में भी इनकी बहुत कमी है। आज ही एक सवाल में माननीय चट्ठा साहब से मैं कह रहा था कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी में 54–35 गांव हैं और साथ में शहर भी है लेकिन वहां छः बड़े–बड़े गांवों में आज तक कोई पशु अस्पताल नहीं है। इस बारे 'में मैंने कई बार संबंधित डायरैक्टर्ज को लिख कर दिया और कई चिट् ठिया भी लिखी हैं। स्पीकर सर, हर बड़े गांव में पशुओं के लिए अस्पताल होना बहुत अनिवार्य है इसलिए इसके लिए सरकार को उपाय करने चाहिएं। आखिर में मैं स्पोर्ट्स के बारे में कहूंगा। इस

बारे में अभी श्री निर्मल सिंह जी ने बोलते हुए चर्चा की थी। हरियाणा के अन्दर लोगों के लिए खेल बहुत ही जरूरी हैं। हमारे यहां पहले ट्रेडीशनल खेल हुआ करते थे। गांवों में बेशुमार ऐसे खेल होते थे जिनके लिए कोई बहुत बड़े इन्फ्रास्टक्चर की जरूरत नहीं होती थी। मुझे याद है कि शहरों के स्कूल में और बड़े गांवों के स्कूलों में भी हॉकी, फुटबाल, वालीबाल की गेम्ज आम होती थीं लेकिन आज क्रिकेट ने इन खेलों का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस देश के अन्दर इन खेलों में कोई खास कमाई नहीं है लेकिन क्रिकेट में बहुत कमाई है। इसके सितारे और टैलीविजन चौनल्ज मिलकर फुटबाल, हॉकी, वॉलीबाल और बास्केट बाल जैसे खेलों को खा गए। स्पीकर सर, मेरा यह सुझाव है कि सरकार कृपा करके इस तरफ भी ध्यान दे। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सरकार ने घोषणा की है कि ब्लाक स्टेडियम बनाए जाएंगे लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक मजाक है। आप मुझे मुआफ करेंगे मैं यह कहना चाहता हूं कि हर बड़े गांव में जिसमें 10 जमा दो का स्कूल है या सीनियर सैकंडरी स्कूल हैं, उसमें खेल स्टेडियम्ज का होना बहुत जरूरी है लेकिन इसके लिए हमारे पास इन्फ्रास्तक्यर नहीं है, साथ ही साथ कोचिज भी नहीं है। हरियाणा प्रदेश में तो स्पोर्ट्स कालेज भी होना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि यहां पर क्य से कम छः स्पोर्ट्स कालेज होने चाहिएं ताकि हम अपने लिए कोचिज तैयार कर सकें। ये कोचिज तैयार होकर पूरे देश के अन्दर जा सकते हैं। खेलों की ट्रेनिंग देने वाले लोगों की आज बहुत भारी कमी है। स्पीकर सर, मैं अंत में यह बात कहूंगा कि हमारी जो

यूनिवर्सिटीज हैं चाहे वह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो, उन्होंने पिल्ले दस–बीस सालों से कोई रिसर्च नही की हे। सर, मुझे माफ करना आप भी आज से 10 साल पहले यूनिवर्सिटी में प्रोफैसर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः सुरजेवाला जी, मैं 10 साल पहले नहीं 22 साल पहले प्रोफैसर था।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः सर, फिर तो ठीक है तो मैं आपसे माफी भी नहीं मांगता हूं क्योंकि मैं पिछले 10–20 साल की बात कर रहा हूं। सर, पिल्ले 10–20 सालों से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कोई भी रिसर्च नहीं की है। उन्होंने खेतीबाड़ी के लिए कुछ भी नहीं किया है। न तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने और न ही रोहतक यूनिवर्सिटी ने कुछ रिसर्च का काम किया है।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है।

13.00 बजे

श्री एस०एस० सुरजेवालाः स्पीकर सर, ये मेरे जज्बात हैं मैं उनको ही बयान कर रहा हूं। हमारी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च का काम होना चाहिए। वहां पर भी कुछ नहीं होता है। आज हमारे जो साइंटिस्ट हैं वे आज केवल टूरिस्ट बन गए हैं, वे हमेशा ही किसी न किसी बहाने से विदेशों में जाने का बहाना ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से वे बाहर जा सकें। आज आप उनके रहने सहने का तरीका देखिए, पहनावा देखें, आज आप

यूनिवर्सिटीज में जाकर उनके फ्लैटस देखें कि वे कितने ही आलीशान बने हुए हैं, उनके बीवी और बच्चे खूब मौज कर रहे हैं। स्पीकर सर, मैं जब कालेज में पड़ता था तो उस वक्त मैं डॉ० रामधन, साईंटिस्ट से मिला था। वह आदमी बहुत ही सीधा सादा था और गांव में रहता था। सर, आज जो गेहूं 1080 हम पैदा कर रहे हैं यह उनकी ही देन है। क्या वह आदमी सूट पहनता था नहीं वह आदमी बहुत ही सीधा सादा था। लेकिन आज के साईंटिस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत ही दुःख की बात है। स्पीकर सर, आज आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड वाली को बुलाकर पूछें कि इनका कितना बजट है? जितना उनका बजट रखा है उतना किसी का भी नहीं रखा गया है। यह किसलिए रखा गया है? आज ये मार्केटिंग बोर्ड वाले या तो मण्डी बनाते हैं या फिर सड़क बनाते हैं लेकिन पिछले एक साल से तो इन्होंने एक भी सड़क नहीं बनाई हे। इनका फंक्शन मार्किटिंग, मोनिटरिंग, किसान को खाद और बीज मुहैया करवाने का और आने वाले समय में कैसा मौसम होगा और उस मौसम में किस फसल को बोया जा सकता है, के बताने के बारे में होता था लेकिन आज ये कुछ नही करते हैं। सरकार ने यह एक सफेद हाथी पाल रखा है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं और सरकार को सुझाव दे रहा हूं कि इसका जो बजट है वह लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। स्पीकर सर, सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट के लिए भी सरकार ने बजट में पैसे का प्रावधान किया है। आप गांवों में जाकर देखें और पता कर लें कि वहां पर सोशल वैल्फेयर का

आफिसर कौन है और क्या उसने सोशल वैल्फेयर के बारे में कभी कुछ पड़ा है या उसे कुछ पता है। स्पीकर सर, मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि गांव की जमीन औरत के नाम पर होनी चाहिए। आप आज इस महकमें में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत सी महिलाओं को ही नौकरी दी गई है, यहां तक अ० प्रतिशत इम्पलाइज वहां पर महिलाएं ही हैं। वहां पर जो महिलाएं हैं वे बहुत कम पढ़ी लिखी हैं और उनको सोशल वैल्फेयर के काम के बारे में कुछ पता नहीं है। यह ठीक है कि हमारी सरकार लोगों की भलाई के लिए, औरतों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए बहुत सी स्कीमें चला रही है लेकिन आप गांवों में जाकर देख लें आपको सोशल वैल्फेयर का दफ्तर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं कि वहां पर 20–20 दफ्तर हैं लेकिन वे ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। मैं भी अपने जिले का एम०एल०ए० हूं लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि उनका दफ्तर कहां पर है? सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट की तरफ से किसी भी स्कीम्ज के बारे में कोई कागज नहीं दिया जाता है, कोई पम्फलेट नहीं दिया जाता है कि स्कीम्ज कौन–कौन सी है? ये बिल्कुल भी कोओपरेट नहीं कर रहे हैं। ये सारे गरीब हरिजनों का शोषण करने लग रहे हैं। वीरेन्द्र सिंह जी, आप सरकार को कहकर कम से कम इनका दफ्तर एक जगह पर ही करवा दो, इनको एक जगह पर बिठा दो ताकि इनके दर्शन हो सके। स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री रमेश द्वार गुप्ता (थानेसर): स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब 6 फरवरी को गवर्नर साहब ने अपना अभिभाषण यहां पर दिया था तो उस पर भी मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया था। महामहिम ने जो अपना अभिभाषण दिया था उसमें भी सरकार की नीतियों और डिवैल्पमैंट के बारे में चर्चा की नयी थी। सरकार की जो नीयत है, नीति है, उसका उसमें उल्लेख था। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के मार्ग दर्शन में हरियाणा विकास की तरफ अग्रसर है। 13 फरवरी को जो वित्त मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया है उसमें भी विकास कार्यो का प्रतिबिम्ब नजर आता है। जो दस हजार करोड़ रुपये को योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यों पर खर्च करने की चर्चा की गयी है उससे पता लगता है कि हमारा बजट कितना साउंड है और वैल्फेयर के कार्यो के लिए कितना कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। जो अभी एक फरवरी को चौधरी रणबीर सिंह जी का स्वर्गवास हुआ वह हमारे लिए बड़े दुःख की बात है। वे संविधान सभा के एक मात्र जीवित सदस्य थे जिनको हमने खो दिया है। मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने सन् 1948 में संविधान कमेटी में किसान मजदूर की बात का उल्लेख किया था। हमारे बहुत से साथियों ने भी कहा कि जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था वहां पर उनकी याद में कोई न कोई स्थल जरूर बनना चाहिए और वह स्थल स्वतंत्रता सेनानियों

की याद में ही डिवैल्प होना चाहिए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। जो रास्ता उन्होंने दिखलाया था उसी पर हमारी यह मौजूदा सरकार चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान मजदूर के लिए अनेकानेक कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने किसान के और मजदूर के हक में कई स्कीम्ज चलायी हैं चाहे वह बिजली के बिलों की माफी की बात हो, चाहे ऋणों के ब्याज की माफी की बात हो, सब तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। हालांकि केन्द्र सरकार ने भी इस बारे में अपनी स्कीम किसानों के लिए चलायी हे। इसी तरह से हमारी इस सरकार ने फसलों के रेट भी बढ़ाए हैं। जब पिछली सरकार थी तो उस वक्त गेहूं का भाव सिर्फ 40–50 रुपये ही बढ़ाया गया था लेकिन हमारी सरकार के दौरान गेहूं के रेट में 450 रुपये के करीब बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह से जीरी के रेट में भी 350 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। ये रेट पिछले दो वर्षो में हमारे किसान को मिल रहा है। सर, जैसे डांगी साहब ने कहा कि इससे किसान की हालत मजबूत हुई है क्योंकि 50–60 हजार रुपये से ज्यादा एक एकड़ फसल का किसान को मिल रहे हैं। सर, मैं भी एक आढ़ती हूं इसलिए मुझे पता है कि किसान इस समय खुशहाली की ओर अग्रसर है। दो वर्ष पहले जब नोन बासमती के ऐक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी अपना विदेश का दौरा छोड्कर वापस आए थे और उन्होंने नोन बासमती का बैन हटवाया था। चौन लगने से इसके रेट गिर रहे थे लेकिन बैन हटने के बाद इसके रेट में इजाफा हुआ और इससे किसानों को फायदा मिला। इसी तरह से

पिल्ले वर्ष भी पूसा 1121 वैरायटी जो नोन बासमती में आती थी, काफी मात्रा में लगी हुई थी और उसका रेट गिर रहा था लेकिन मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से कहकर इसको भी बासमती में शामिल करवाकर इसका भी ऐक्सपोर्ट का बैन खुलवाया था। उन्होंने इसको बासमती में बदलवाया जिसके कारण इसका रेट बढ़ गया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी से कि इस वर्ष भी ये जो नॉन बासमती पर बैन हे इसको खुलवाया जाए क्योंकि अगर यह सुधार टाईम पर नहीं हुआ तो राइस मिलर्ज की हालत काफी खराब हो जाएगी। उन्होंने यह किस्म तेज मार्किट में खरीदी हुई है इसलिए इसका बैन समय पर न खुलवाया गया तो अगले साल इस बात का प्रभाव किसानों पर पड़ेगा। पहले एम०ई०पी० का रेट 1100–1200 रुपये प्रति डालर था लेकिन अब 100 डालर घटाए गए हैं। अब यह 1100 रुपये डालर प्रति टन किया है लेकिन इसको 900 डालर पर लाया जाए। यह मेरा सुझाव है। इसके अलावा बजट से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, बुढ़ापा पैंशन और जो दूसरे भत्ते सभी को दिये हैं, यह अपने आप में सराहनीय हैं। जो कमीपेशी थी वह भी आज उन्होंने यह कहकर पूरी कर दी है कि दस साल से जिनको बुढ़ापा पैंशन मिल रही है उसकी पेंशन 700 रुपये होगी। इससे सभी बुजुर्गों को लाभ होगा। इससे आम आदमी बहुत ही खुश हुआ है। सभी मुख्यमंत्री जी की सराहना कर रहे हैं। आज से दो तीन महीने पहले प्रदेश में एक समस्या से सभी लोग भयभीत थे। वह समस्या यह थी कि सड़कों के दोनों

ओर 20 मीटर के दायरे में जो बिल्डिंग्स थी उनको हाईकोर्ट के आर्डर ले गिराया जाना था। इस समस्या के बारे में मुख्यमंत्री जी ने समय पर कदम उठाया और जो पंजाब शिडयूल्ड रोड ऐक्ट है, उसमें संशोधन किया ताकि वे बिल्डिंग्स गिरने से बचाई जा सकें। बिल्डिंग गिराने से हमारे कई गरीब भाइयों और व्यापारियों को भी भारी मात्रा में नुकसान होता। मुख्यमंत्री महोदय ने उस समस्या से हमें राहत दिलाई है इसके लिए सभी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहे हैं और सभी ने जी०टी० रोड पर आभार प्रकट करने के लिए और धन्यवाद स्वरूप झंडे भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने यह एक बहुत अच्छा फैसला किया था। सभापति महोदय, अब कुछ बातें मैं अपने हल्के के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे तो मुख्यमंत्री जी सभी हल्कों में बराबर के विकास कार्य कर रहे हैं लेकिन मेरे हल्के की दो चार ऐसी मुख्य मांगे हैं जिनकी ओर मैं आपका खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश में पिछले 40 वर्षों के इतिहास में 16 आर०ओ०बी० बने लेकिन हमारी इस सरकार के बनने के बाद 9 आर०ओ०बी० बन चुके हैं और 6 शीघ्र ही बनने जा रहे हैं। इनमें मेरे हल्के का भी एक आर०ओ०बी० उमरी से डांड रोड तक है और वह सुंदरपुर फाटक पर जा कर मिलता है जिसकी स्वीकृति भी हो चुकी थी और उसके लिए रेलवे विभाग भी अपना शेयर देने के लिए तैयार है। के०डी०बी० की मीटिंग हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्किटिंग बोर्ड को इस काम के लिए कहा था क्योंकि यह सड़क

मार्किटिंग बोर्ड की है परन्तु मार्किटिग बोर्ड इस सड़क को बनाने में पता नहीं किस वजह से आनाकानी कर रहा है।

श्री अध्यक्षः आप कच्छ करें।

श्री रमेश कुमार गुप्ताः सर, मैं कच्छ कर रहा हूं। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी व ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि यह आर०ओ०बी० बहुत ही जरूरी है क्योंकि सूर्यग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है और लाखों की तादाद में यात्री यहां पर आते हैं। इसके अलावा माननीय विधायक साथी श्री के०एल० शर्मा जी ने कुरुक्षेत्र में मैडीकल कालेज बनाने की बात कही है मैं भी उसका समर्थन करता हूं। सोनीपत तो रोहतक के पास है और रोहतक में मैडीकल कालेज है इसलिए मैं चाहूंगा जो कुरुक्षेत्र सैन्टर प्लेस है इसलिए वहां पर मैडीकल कालेज बना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि ऐसा संभव नहीं है तो हमारा जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र अस्पताल है उसको ही अपग्रेड किया जाए। अध्यक्ष महोदय, उमरी की पंचायत ने 20 एकड़ जमीन पौलीटैक्नीक कालेज बनाने के लिए दी है लेकिन वह जमीन अभी तक वैसे ही पड़ी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आप अपने बाकी के सुझाव लिखकर भिजवा देना, वह हम प्रोसीडिंग्ज में शामिल करवा देंगे।

श्री रमेश कुमार गुप्ताः सर, मैं दो मिनट का समय और लूंगा। वह कालेज पंचायत द्वारा अभी तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से

बनना था। मेरी मांग है कि वहां या तो कोई शिक्षा संस्थान खोला जाये या फिर पंचायत को वह भूमि वापस की जाए। एक मेरे हल्के की राक्षी योजना है जिसकी बहुत पुराने समय से मांग थी। इसका पैसा भी सैंक्शन हो गया है लेकिन वहां पर लैंड ऐक्वायर होनी थी इसलिए अवार्ड होना रहता है वह जल्दी करवाया जाए। इसके अलावा लाडवा के स्पोर्टस स्टेडियम के लिए ग्रांट दी जानी है मैं निवेदन करूंगा कि वह ग्रांट शीघ्र दी जाए। मेरी पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर से मांग है जैसे कि अन्य सदस्यों ने भी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जिक्र किया है मैं भी कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से हमारे गांवों में व कस्बों में पानी की निकासी की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसके लिए कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे यह पानी की निकासी की दिक्कत खत्म हो जाए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सब्जी पर जो मार्केटिंग फीस है वह चार प्रतिशत है और उस पर कोई टैक्स नहीं है। उससे जो आलू प्याज पैदा करने वाले किसान हैं इस मार्किट फीस के चलते वे अपनी सब्जी मण्डियों में नही लाते क्योंकि उनको खेतों में ही सब्जियों का अच्छा भाव मिल जाता है इसलिए किसान के खेत में ही सौदे हो जाते हैं। कई ऐसी पार्टियां सब्जी ले लेती हैं जिसके कारण किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि वे लोग किसान को पेमैंट समय पर नहीं करते। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मार्केटिंग फीस को चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया जाए। इससे कोई रिवैन्यू की हानि स्टेट को नहीं होगी और सब्जियां भी ठीक तरह

से बिक सकेंगी। दिल्ली और राजस्थान में भी यह फीस एक प्रतिशत है। स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सुभाष चौधरी (जगाधरी): अध्यक्ष महोदय– वित्त मंत्री महोदय ने जो हाउस में बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट इस बात को दर्शाता है कि सरकार की नीयत और नीति क्या है। समाज के हर वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए और किसानों को उसकी फसल का भाव दिलाने के लिए इस बजट में भरसक प्रयत्न किया गया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, किसानों के प्रति जो बजट में आकर्षण दिखाया गया है वह पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में एक मिसाल हे। किसानों को उनकी फसल का अच्छा भाव मिला है इतना अच्छा भाव किसान को शायद पहले कभी किसी प्रदेश या देश के अन्दर कभी नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया हैं। उन्होंने आने वाली गन्ने की फसल का भाव 15 रुपये बढाकार किसानों की हौसला अफजाई की है जिससे किसान और ज्यादा गन्ने की पैदावार करेंगे। इसी प्रकार से चार साल के शासनकाल में गेहूं का मूल्य भी अच्छा बकाया गया है। गेहूं के भाव में 72 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है जो देश के अन्दर अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। स्पीकर सर, पिछले साल बरसात के समय यमुना नदी में आई भारी बाढ़ की ओर मैं

आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस दौरान यमुना नदी में 4 लाख 70 हजार क्यूसिक पानी आया था जिसके कारण यमुना नदी के साथ–साथ जो गांव हैं उन लोगों को उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ था। इस बाढ़ से लोगों की फसलें तबाह हो गई थी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से स्पैशल गिरदावरी हुई थी। उस समय किसानों की 100 प्रतिशत फसलें खराब हुई थी परन्तु आज तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है और न ही इस बारे में उन्हें कुछ बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। ऐसे ही कृषि क्षेत्र के अन्दर कुछ इण्डस्ट्रियल कनैक्शन किसानों ने लिए थे जिनके बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे है। इसलिए उनकी कुछ कैटेगरीज को तो सरकार ने एग्रीकल्चर सैक्टर में ले लिया था लेकिन कुछ कैटेगरीज को छोड़ दिया था। मेरा निवेदन है कि उन सभी कैटेगरीज को एग्रीकल्चर टयूबवैल्ज स्लैब प्रणाली में ले लिया जाए ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ कम हो सके। स्पीकर सर, सिंचाई के क्षेत्र में सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हांसी बुटाना नहर, दादुपुर नलवी नहर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा एक नई प्रोपोज्ड नहर ताजेवाला हैड से नारायणगढ़ और अम्बाला के लिए प्रस्तावित है। इन नहरों का निर्माण इस बात को दर्शाता है कि सिंचाई के प्रति सरकार की नीयत कितनी साफ है। सरकार यह चाहती है कि प्रदेश के हर किसान के खेत को पानी मिले। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में यमुना नदी के सारे के सारे बहाव

का रूख हरियाणा की ओर है। मैं इस बात से परेशान हूं और पिछली बार भी मैंने यह बात कही थी कि यू०पी० की सरकार यमुना नदी पर यू०पी० की ओर भारी बांध का निर्माण कर रही है जिससे यमुना का सारा बहाव हरियाणा की तरफ कन्वर्ट हो रहा है जिसके कारण हरियाणा के गांवों को बहुत नुकसान होता है। हमारे जिले के कई गांव जो यमुना नदी से एक एकड़ के फासले पर हैं, उन गांवों में इस बहाव से बहुत नुकसान होता है। अगर सरकार किसानों की जमीन को बचाना चाहती है तो वहां पर नदी के दोनों ओर स्टडस लगवाए जाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मेरा दोनों ओर कहने का मतलब यह है कि कई जगह हरियाणा के किसानों की जमीन यमुना के दूसरी ओर भी 4–4 किलोमीटर तक है। जिस तरह के लैंड डिस्पयूट दूसरे जिलों में हैं, हमारे जिले में उस प्रकार का कोई डिस्पयूट नहीं है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे जिले में यमुना नदी के दोनों ओर स्टडस लगवाएं जाए।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है जहां तक इन्होंने स्टडस की बात की है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें इस इशू को लिया गया है और इनके यहां स्टडस लगवाए जाएंगें।

श्री सुभाष चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा निवेदन

है कि स्टडस दोनों ओर लगें क्योंकि हरियाणा की जमीन 4 किलोमीटर तक यमुना के पार भी है। अध्यक्ष महोदय, अब तक का रिकार्ड यह रहा है कि स्टडस हमारी हरियाणा वाली साइड के लिए ही मंजूर होते हैं लेकिन यमुना पार वाली साईड के लिए स्टडस मंजूर नहीं होते। दोनों ओर स्टडस न होने के कारण इस बार भी फ्लड ने हमारे जिले की 700 एकड़ जमीन को अपनी चपेट में लिया है जिससे न जमीन रही और न ही फसल रही। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस मसले पर हमारी मदद करेंगें ताकि किसान की जमीन बच सके और उसकी फसल भी बरबाद न हो। अध्यक्ष महोदय, अब में इंडस्ट्रीज की बात करना चाहूंगा। इंडस्ट्रीज का पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से बहुत फैलाव हुआ है। साढे 12 हजार करोड़ रुपये का फौरन इन्वैस्टमैंट हमारे प्रांत में हो चुका है और 30 हजार करोड़ रुपये का अभी पाइप लाइन में है। इसमें कोई शक नहीं है कि नई आई०एम०टीज सरकार ने मंजूर की हैं। हमारे जगाधरी में भी एक आई०एम०टी० मंजूर हुई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर जल्दी काम शुरू है?। अध्यक्ष महोदय, मेरी कास्टीच्यूंसी में मेरा जगाधरी शहर इंडिस्ट्रियल टाउन भी है और कुछ समय पहले तक यहां की मैटल इंडस्ट्री सारे हिन्दुस्तान में मशहूर थी लेकिन आज इस शहर की मैटल इंडस्ट्री को ग्रहण लग गया है। वह इंडस्ट्री तबाही की कगार पर खड़ी है और इसका मेन कारण यह है कि दूसरे प्रदेशों में चाहे उत्तरांचल हो, चाहे हिमाचल हो और चाहे राजस्थान हो वहां इंडस्ट्रीज को इतनी सहूलियतें मिली हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज

उनसे कम्पीट नहीं कर पा रही हैं। मैंने पिछले सैशन में भी फाइनैंस मिनिस्टर से आग्रह किया था कि हमारे यहां वैट को 4 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हम टैक्स में कमी नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे यहां वैट को एक परसैंट कर दिया जाता है तो इससे हमारी इंडस्ट्रीज बच सकती है। ऐसा एक साल के लिए करके देख लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, वैट में एक बहुत बड़ी खामी है, मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार किया जाए। वह खामी यह है कि इंडस्ट्रियलिस्टस टैक्स दे देता है और टैक्स लेने वाला 10–20 लोगों से टैक्स खाकर नई दुकान खोल लेता है परन्तु डिपार्टमैंट उन्हीं को नोटिस देता है जो पहले टैक्स दे चुके हैं इससे हमारे शहर में तकरीबन 2 हजार आदमी इफैक्टिड हैं। इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले में कोई ठोस कदम उठाए जाएं ताकि उन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बचाया जा सके।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप कन्क्लयूड करें।

श्री सुभाष चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जगाधरी में विकास के कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत सरकार ने 72 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किये। हरियाणा सरकार ने भी ब्याज और कर्जे माफ किये। कोपरेटिव सैक्टर्ज में नॉन एग्रकिल्चर मैम्बर्ज की एक सोसायटी है। उनके पास जमीन नहीं है। वे लैंड लैस है और उनके०पर कर्जा खड़ा है। मैं आपके

माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो नॉन एग्रकिल्चर मैम्बर्ज के०पर कर्जा है वह भी माफ किया जाए क्योंकि वे छोटे–छोटे कर्जे हैं। किसी का 5 हजार का, किसी का 9 हजार का और किसी का 10 हजार रुपये का कर्जा है। अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के बारे में मेरा निवेदन है कि कई गांवों में स्वच्छ जल धारा के तहत पंचायतों के पास टयूबवैल हैं लेकिन पंचायतें बिल देने की स्थिति में नहीं हें, बिल न देने की वजह से उनके कनैक्शन कट जाते हैं 'और केबल उतार ली जाती हे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट उन ट्यूबवैल्ज को अंडर टेक कर ले और उनका सारा बिल वहन करें। अध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में सरकार की अभूतपूर्व सफलताएं हैं। सरकार ने वर्ष 2011 तक 5 हजार मैगावाट बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी करने का प्रावधान किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे जिले में भी एक कारखाना लगा था। वह कारखाना इस समय फुल प्रोडैक्शन के०पर है और 600 मैगावाट बिजली बना रहा है सरकार की यह घोषणा थी कि जब भी यह कारखाना पूरा होगा तब उस जिले को 16 घण्टे या 20 घण्टे बिजली देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमें 20 घंटे बिजली मुहैया करवाई जाये ताकि हमारे जिले के लोगों को भी राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, नई हल्का बंदी होने से हर हल्के में कुछ गांव टूटे हैं और कुछ नये गांव जुड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा कि छछरौली के

अंदर जो सरकारी कालेज हैं वह स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है।

श्री अध्यक्षः सुभाष चौधरी जी, प्लीज अब आप बैठें। यह बात तो अर्जन सिंह जी पहले ही उठा चुके हैं। आप यदि कुछ और कहना चाहते हैं तो आप लिखकर भिजवा देना। अब श्री जगबीर सिंह मलिक जी बजट पर बोलेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज के समय में ग्लोबल रिसैशन और वित्तीय क्राईसिज, वर्ल्ड वाईड फिनोमिना बने हुए हैं। ऐसे समय में वित्त मंत्री जी ने बहुत सूझबूझ से बजट पेश करके हिन्दुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को एक ऐसा मैसेज दिया है कि किस प्रकार से वित्तीय मैनेजमैंट चलता हे। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। छठा पे कमीशन लागू होने पर जो उठ महीने का कर्मचारियों का एरियर बकाया था उसके लिए हमारी सरकार ने 4350 करोड़ रुपये बजट में एडजस्ट किये हैं। 100 करोड़ रुपये का स्पैशल पैकेज खानपुर कलां महिला विश्वविद्यालय में मैडीकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए बजट में प्रोवीजन किया है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यह मैडीकल कालेज बहुत ही गरीब इलाके में बनेगा जहां पर लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी और

शायद यह पहला ऐसा मैडीकल कालेज हो जिसमें केवल लड़कियों को ही शिक्षा मिलेगी। यह भी एक रिकार्ड की बात है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस वर्ष को किसान और मजदूर वर्ष के रूप में मना रही है। हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में किसानों की भलाई के लिए बहुत सी घोषणाएं की हैं। अब किसी भी किसान की जमीन लोन न चुकाने पर नीलाम नहीं की जायेगी और ट्रैक्टर लोन लेने के लिए एक एकड़ जमीन की गारंटी ही काफी होगी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों की जिस, जमीन की रॉयलटी और बहुत सारी मदों पर मुआवजा बढ़ाकर किसानों की बहुत मदद की है। इस तरह के उदाहरण इस प्रदेश को छोडकर दूसरे किसी प्रदेश में नहीं मिल सकते।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक गांवों के विकास की बात है आज ग्रामीण इलाकों की सूरत शहरों के रूप में बदल रही है। आज गांवों की गलियां सी०सी० की बन रही हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने 11 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती गांवों की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए की है। इस तरह से गांवों में भी शहरों वाली सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। यही वजह है कि निर्मल ग्रामीण पुरस्कार योजना के तहत हमारे प्रदेश को देश में तीसरा स्थान मिला है। इतना ही नहीं महात्मा गांधी आवास

योजना के तहत हमारी सरकार ने गरीबों और हरिजन भाइयों को प्लाट देकर एक उदाहरण पेश किया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ग्राम सुधार बजट के लिए वित्त मंत्री जी ने 60.05 प्रतिशत की बढौत्तरी करके बहुत ही अच्छा काम किया है इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शहरों की बात करना चाहूंगा कि शहरों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने जो नया प्रोपर्टी डीलर्ज ऐक्ट पेश किया है। इस नये ऐक्ट के लागू हो जाने से जो प्रापर्टी डीलर्ज कालोनियों में खाट काटकर पैसे कमाकर चले जाते थे उन पर अंकुश लगेगा। इस प्रकार की कालोनियों में पानी, लाईट, सड्कों और सीवरेज की सुविधायें मुहैया नहीं होती थी और इन तमाम आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित कालोनी वासी स्थानीय एम०एल०ए० के पास जाते थे। इस ऐक्ट के लागू हो जाने से इस प्रकार की सारी गैर जरूरी परेशानियां समाप्त हो जायेंगी क्योंकि नये बने कानून के तहत कालोनाइजर्स को कालोनियों में ये तमाम सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करवानी होगी। इसके साथ–साथ इस ऐक्ट के लागू हो जाने से निकट भविष्य में शहरों में बसने जा रही नई कालोनियां के हालात को सुधारने के लिए भी मदद मिलेगी और इस दृष्टि से भी यह कदम बहुत अच्छा प्रयास साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी जो यह कहते हैं कि शहरों के विकास के लिए हमारी सरकार ने कोई भी काम नहीं

किया उनकी यह बात भी पूर्ण रूप से निराधार और असत्य है क्योंकि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार द्वारा मौजूदा बजट में शहरों के लिए आबंटित धनराशि में 256 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जो अपने आप में एक रिकार्ड की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा करके शहरों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। इस काम के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी सराहना की जाये उतनी कम होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए भी धन्यवाद के साथ बहुत–बहुत बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त शिडयूल्ड रोड ऐक्ट में जिस प्रकार से शहरवासियों और ग्रामीणों की जमीन को एक्वायर करने के लिए नोटिस जारी कर दिये गये थे और सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के नोटिस जारी करने के बाद जिन्हें अपनी जमीन के ऐक्वायर होने का डर सत्ता रहा था इस ऐक्ट के आ जाने से उनको भी भय से मुक्ति मिलेगी और वे चौन की नींद सो सकेंगे। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा जहां तक शिक्षा की बात है शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार द्वारा अभूतपूर्व कार्य किये गये हैं। मेरे सोनीपत जिले में जो राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी है उसमें ओ०पी० जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सियई के नाम से एक नई यूनिवर्सिटी स्थापित होने जा रही है। यह यूनिवर्सिटी इंटरनैशनल स्टैडर्ड की यूनिवर्सिटी होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ वहां पर विदेशों की यूनिवर्निटीज भी स्थापित होंगी। इसी प्रकार से सोनीपत जिले में सर छोटू राम कालेज को यूनिवर्सिटी बनाने

के बाद उसके अन्दर कैमीकल इंजीनियरिंग विंग का आज माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने गये हुए हैं यह भी अपने आप में एक इतिहास होगा। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से झज्जर में सेरामिक्स ओर अम्बाला में प्लास्टिक का सैन्टर है, इसी प्रकार से उठ चीजों में सैंटर आफ एक्सीलैंस सर छोटू राम यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ भगत फूल चन्द महिला विश्वविद्यालय बनाना भी अपने आप में एक इतिहास की बात हे, जिसे सदा–सदा के लिए .याद रखा जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं इस यूनिवर्सिटी के दो कैम्पस में से एक कैम्पस भैंसवाल कलां है जो कि ओरिजनल कैम्पस भी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता जी उस कैम्पस के विद्यार्थी रहे थे। उन्होंने प्राईमरी एजुकेशन भैंसवाल कलां की इसी यूनिवर्सिटी के एक कैम्पस से प्राप्त की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के उसी कैम्पस में आधारभूत शिक्षा देने के लिए एक इंस्टीच्यूट चलाया जाये। इसके अलावा मैं यह भी गुजारिश करना चाहूंगा कि लोक सभा और विधान सभा के साथ–साथ चौधरी रणबीर सिंह जी की एक प्रतिमा भैंसवाल कलां की यूनिवर्सिटी के इस इंस्टीच्यूट में भी स्थापित की जाये जहां से उन्होंने प्राईमरी एजुकेशन प्राप्त की थी ताकि वहां के आसपास के इलाके के लोगों को यह पता चल सके कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी जैसे महापुरुष ने इस कैम्पस में अपनी प्राथमिक शिक्षा

ग्रहण की थी। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उनके स्टैच्यू के साथ उनकी संक्षिप्त जीवनी भी दर्शायी जाये ताकि वहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उनके जीवन से भी शिक्षा प्राप्त करके निकलें और वे देश व समाज के निर्माण में उनके द्वारा बताये गये रास्ते पर चलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें।

Mr. Speaker: Mr. Malik, please conclude.

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, ऑनरेबल मैम्बर्ज के साथ यही तो समस्या है कि जब उनको दिया गया समय समाप्त होने बारे उनको सूचित किया जाता है तो वे कहते हैं कि अभी तो हमने शुरू ही किया है। I know very well that you can speak and you can deliver the lecture over together. I do agree that you have the capacity to speak and you have also the material to speak. मलिक साहब, आपकी जो बातें रह गई हैं उनको आप लिखवाकर भिजवा देना and we will incorporate your statement.

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा समय और दिया जाये मैं जल्द से जल्द अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। स्पीकर सर, अब मैं टैक्नीकल एजुकेशन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। यह भी सर्वविदित है कि टैक्नीकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम

किये हैं। हमारी सरकार द्वारा 428 नए इंस्टीच्यूट्स का निर्माण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि मैं अपने हल्के के गांव मोहाना में एक आई०टी०आई० खुलवाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि माननीय ' मुख्यमंत्री महोदय मेरी इस छोटी सी डिमाण्ड को जरूर पूरा करेंगे क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में 28 नई आई०आई०टीज० खुलने जा रही हैं। स्पीकर सर, मैं तो सिर्फ एक आई०टी०आई० खुलवाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मोहाना गांव में आई०टी०आई० खुलवाने की मेरी डिमाण्ड को जरूर पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं खेलों के बारे में एक–दो बातें कहना चाहता हूं। स्पीकर सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों–करोड़ों रुपये खर्च किए हैं जो कि अपने आप में एक रिकार्ड की बात है। हमारी सरकार निकट भविष्य में पूरे प्रदेश में 169 नये खेल स्टेडियम बनाने जा रही है। इनमें से कुछ स्टेडियम्ज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ का काम अभी अण्डर प्रोसैस है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ओलम्पिक खेलों में पदक लाने वाले प्रदेश के 9 खिलाड़ियों को डी०एस०पी० के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने का एक सराहनीय काम किया गया है। सौभाग्य से इनमें से एक हमारे गांव के श्री योगेश्वर दत्त पहलवान को भी डी०एस०पी० के पद पर नियुक्ति मिली है। उसने भी ओलम्पिक में भाग लिया था। अध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे गांव भैंसवाल में स्वर्गीय श्री बलराज सिंह के नाम से एक अखाड़ा चल रहा है। उस अखाड़े ने हरियाणा केसरी, दिल्ली केसरी, हिन्द केसरी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान दिये हैं। औलम्पिक खेलों में कुश्ती में मैडल लाने वाला पहलवान योगेश्वर दत्त भी उसी अखाड़े का शिष्य है। अभी हाल में 2000 में कनाडा में इन्टरनैशनल गोल्ड कप में 60 किलोग्राम में कुश्ती में योगेश्वरदत्त ने गोल्ड मैडल जीता है।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार क्रिकेट के लिए सरकार झज्जर में अकैडमी बनाने जा रही है और किलोई में बास्केटबॉल के लिए अकैडमी बनाने जा रही है उसी प्रकार से मेरे गांव भैंसवाल जहां से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान निकलते हैं वहां पर भी एक कुश्ती की अकैडमी सरकार को बनानी चाहिए।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप लिख कर भिजवा देना। श्री रणधीर सिंह जी, अब आप बोलिए।

श्री रणधीर सिंह (बरवाला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी रणबीर सिंह जी के स्वर्गवास होने पर हमारे

जितने साथियों ने श्रद्धाजलि दी है मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ते हुए उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। चौधरी रणबीर सिंह जी ने हरियाणा प्रान्त बनाने के लिए और इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ाईयाँ लड़ी। वे लोकसभा और राज्यसभा के भी मैम्बर रहे। वे संयुक्त पंजाब में सिंचाई मंत्री भी रहे। आज उन्हीं की वजह से हरियाणा प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था काफी सुदृढ़ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो वर्ष 2009–10 का बजट पेश किया है वह एक सराहनीय बजट है इसके लिए भी मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को लेकर चाहे वह चौकीदार हो, चाहे नम्बरदार हो या जिला परिषद का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, ब्लॉक समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, हर वर्ग को साथ लेकर चलने का फैसला किया है। हमारे विपक्ष के साथियों के पास केवल एक ही मुद्दा था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम बुढापा पैंशन 700 रुपये कर देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस मुद् दे को समाप्त करते हुए आज बुढ़ापा पैंशन 700 रुपये प्रति मास कर दी हे। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा उन्होंने हमारे बुजुर्गों को सम्मान देते हुए 700/– रुपये पैंशन के साथ–साथ एक पगड़ी और डोगा सम्मान के चौर पर देने का एलान किया है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से विकास कार्य किये हैं। वृद्धों के लिए जो 700/–

रुपये पगड़ी और होगे का इन्तजाम किया है इसके लिए विपक्ष के साथियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए और उनको बधाई देनी चाहिए। (विघ्न) जो डोगा दिया है वह इसलिए दिया गया है कि इन लोगों ने जो गलत काम किए उनको दिखाया जा सके।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। डोगा दिखाने के लिए नहीं होता बल्कि सहारे के लिए दिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर किस बात का है। डोगा तो जो भी कोई गलत काम करे उसको दिखाया जा सकता है। हमें भी दिखाया जा सकता है। यह तो डैमोक्रेसी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणधीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए जितने कार्य किये हैं उतने विपक्ष के हमारे साथियों ने जब इनकी सरकार थी, इन्होंने 6 साल में भी नहीं किये। फसलों के भाव पिछली सरकार के 6 साल के कार्यकाल में 40–50 रुपये बड़े थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और इस देश के प्रधानमंत्री ने श्रीमती सोनिया गांधी जी की रहनुमाई में साढ़े चार सौ रुपये तक किसान की फसलों के भाव बढ़ाये हैं। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और इनको बधाई देना चाहता हूं। आज हरियाणा प्रदेश के

मुख्यमंत्री ने चाहे वह गन्ना हो, चाहे कपास हो, चाहे बाजरा हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल या जीरी की फसल हो सबके भाव बढ़ाए हैं उसके लिए हरियाणा प्रदेश के किसान गदगद हैं। हरियाणा प्रदेश में कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था का जो कार्यक्रम था हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसके लिए बड़े भारी कदम उठाए हैं और बड़ी–बड़ी नहरों का निर्माण कार्य करवाया है। किसान की जमीन में एक–एक एकड़ की सिंचाई के लिए जो नालियां बनाई जानी थी। उनका काम भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सुनिश्चित किया है और यह नालियां बननी शुरू हुई हैं जिससे किसानों के खेत में सिंचाई की व्यवस्था सुचारू हुई है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे गरीब वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले जो साथी थे जिनके पास घर बनाने के लिए प्लाट्स नहीं थे उनको 100– 100 वर्ग गज के स्पॉट्स देने का कार्य किया है। गरीब वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले हमारे गरीब बच्चे जो शिक्षा ग्रहण ' करना चाहते हैं उनकी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गरीब वर्ग के बच्चों के लिए जो वजीफा देने का कार्य किया है वह भी एक सराहनीय कदम है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में चाहे कोई भी सरकार रही हो और चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो हरियाणा प्रदेश में लाईट की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कोई भी पग नहीं उठाया गया था लेकिन हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने वर्तमान

सरकार के आते ही, सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों के लिए तथा हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लाईट की व्यवस्था सुचारू करने के लिए हरियाणा प्रदेश में पांच हजार मैगावाट बिजली पैदा करने के लिए जो हाईडल और थर्मल पावर प्लांट लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है वह भी सराहनीय कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो गांव की मेन और छोटी गलियां हैं वह टूट चुकी थी और उनमें कोई भी गली चलने लायक नहीं थी आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास की योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के हर गांव में सी०सी० की गलियां बनाने का जो कार्यक्रम बनाया है वह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। आज हरियाणा प्रदेश का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है वह बहुत ही विकासात्मक बजट हे। हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जलसेवा के तहत तालाबों की खुदाई का जो कार्यक्रम है यह भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो पशु रहते हें उन्हें पीने के लिए स्वच्छ और बढ़िया जल मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी पेंशन योजनाएं, बिजली की ठीक व्यवस्था के लिए बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो बढ़िया कदम उठाए हैं उनके लिए मैं उन्हें मुबारिकबाद देता हूं। हमारे युवा छात्र–छात्राओं ने चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी हो, चाहे नर्सिंग से सम्बन्धित कोर्सिज करने हों या मैडीकल क्षेत्र में कोई

कोर्सिज करना चाहते हैं, उनको अपनी पढ़ाई के लिए पहले दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था। हमारे विद्यार्थी वहां पर ऐडमिशन लिया करते थे लेकिन हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि हरियाणा प्रदेश के जो प्पी छात्र–छात्राएं जिस क्षेत्र में भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए प्रदेश के अन्दर ही वैसी शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, अब आप कंकलूड करें।

श्री रणधीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय ओर लूंगा और अपने हल्के की कुछ मांगे रखना चाहूंगा। सरकार द्वारा जो महिला यूनिवर्सिटी पोलिटैक्निक कॉलेजिज तथा दूसरे कालेजिज बनाए गए हैं उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने मेरे इलाके के बरवाला शहर, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ इलाका था, उस क्षेत्र में भी कॉलेज शुरू करवाया है और वहां क्लासिज शुरू हो चुकी हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस कालेज के लिए अभी तक जमीन और पैसा नहीं दिया गया है। स्पीकर सर, आपके माध्यम से उनसे मेरा यह अनुरोध है कि इस कालेज के लिए जमीन की व्यवस्था करके उस पर बिल्डिंग लाने के लिए पैसा प्रदान करने की कृपा करें। इसके साथ ही साथ मेरे इलाके में 4–5 स्कूलों को

अपग्रेड किया जाना है वहां पर आठवीं से दसवीं तक, दसवीं से दस जमा दो में कुछ स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, बाकी आपकी जो बात रह गई है वह आप लिख कर भिजवा दें। वह इन्कलूड कर ली जाएगी।

श्री रणधीर सिंहः सर, इसी तरह से मैं यहां पर कुछ फ्लों के अपग्रेडेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर ढाणी ढाण मिडल स्कूल है इसको हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए, सढेरा मिडल स्कूल है इसको भी हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए तथा छांग में जो हाई स्कूल है उसको 10+2 में अपग्रेड किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे हल्के की कुछ सड़कें हैं मैं उनके बारे में भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप इनके बारे में लिखकर भेज देना। अब आप बैठ जाएं। कर्ण सिंह दलाल जी आप बोलें।

श्री रणधीर सिंहः ठीक है स्पीकर साहब, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा में यह सरकार बनी है तब से हरियाणा में चहुंमुखी विकास हुआ है इसके लिए मैं

मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। इन्होंने किसी भी तरफ विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने इस सरकार का चौथा बजट पेश किया है और हर वर्ष जब ये बजट पेश करते हैं तो हरियाणा में चहुँमुखी विकास होता नजर आता है। आज हरियाणा में मुख्यमंत्री जी द्वारा अच्छी नियत से काम किए जा रहे हैं जिसकी हरियाणा में चारों तरफ सराहना की जा रही है। स्पीकर सर, इस सरकार की नीति हरियाणा में चहुँमुखी विकास करवाने की रही है। स्पीकर सर, हमारी सरकार से पहले जो भाई यहां पर थे वे किसानों के हितैषी होने का ढोंग किया करते थे उन्होंने 1999–2000 से लेकर 2004–05 तक गेहूं की एम०एस०पी० में केवल क्य रुपये की बढ़ोत्तरी की थी। उस वक्त केन्द्र में एन०डी०ए० की सरकार थी और हरियाणा में इनैलो और बी०जे०पी० की सरकार थी। इनके उन पांच सालों में इन्होंने पैडी की एम०एस०पी० केवल 80–90 रुपए की बढ़ोत्तरी की थी। जबकि आज की सरकार ने चार साल के कार्यकाल में गेहूं की 450 रुपए और धान की 320 रुपये एम०एस०पी० बढ़ाई है। यह इस सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। स्पीकर सर, हमें सदन में मात्र आलोचना करने का काम नहीं करना चाहिए। हमारे विपक्ष के भाइयों को याद करना चाहिए कि इनकी सरकार के वक्त में किसानों के प्रति इन्होंने अपना दायित्व ठीक ढंग से नहीं निभाया था। स्पीकर सर, बिजली पैदा करने के लिए हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं उसके लिए हरियाणा का जन–मानस हमारी सरकार की भरपूर सराहना करता है और वह विश्वास करके बैठा हुआ है

कि आने वाले समय में हरियाणा में बिजली की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा हमारी सरकार ने वैस्टर्न यमुना कैनाल का कार्य किया है। यह भी बहुत ही सराहनीय है। इसी तरह से दादुपुर नलवी, हांसी बुटाना लिंक नहर आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी और हरियाणा के लोग इसको सदैव याद रखेंगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने और इनकी सरकार ने जहां हरियाणा के हर वर्ग के लिए काम किया है वहीं आज इण्डियन स्टैम्प ऐक्ट में अमैंडमैंट करने की सख्त जरूरत है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए मैं यह अमैंडमैंट इसलिए महसूस करता हूं कि जो एनसैस्ट्रल प्रापर्टी होती है उसको कोई भी व्यक्ति 15 रुपये के स्टैम्प पेपर पर रिलीज करके तैयार करवा सकता है। स्पीकर साहब, मैंने हर विधान सभा सत्र में यह बात रखी है। हरियाणा का आम आदमी इस से बहुत ज्यादा दुखी है, उनके द्वारा बार–बार यह बात उठायी जाती है इसलिए मेरी मांग यह है कि सरकार इंडियन स्टैम्प ऐक्ट में अमैंडमैंट करने जो सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रोपर्टी है जैसे मान लीजिए आप अपने जीवनकाल में कोई जायदाद बनाते हैं तो आपको यह अधिकार होना चाहिए एनसैंसट्रल प्रोपर्टी की तरह से अपने खून पसीने से बनायी हुई जायदाद को भी अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बेटे या बेटियों को देना चाहें तो 15 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ही उसको भी देने की इजाजत होनी चाहिए क्योंकि इससे सरकार के खजाने पर भी कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो अभी तक प्रदेश के

जो लोग अपनी जायदादों को अपने बच्चों के नाम नहीं करवा पा रहे हैं। इससे उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमारी सरकार ने लोगों को दूसरी तरह की बहुत सी राहतें प्रदान की हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से पंजाब के अंदर और हमारे हरियाणा में भी जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं उनसे अगर कोई किसान कर्जा लेना चाहता है और अपनी जमीन गिरवी रखता हे तो उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है लेकिन वही किसान अगर नेशनेलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स से कर्जा लेने के लिए अपनी दरख्वास्त लगाता है तो उसके०पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। इस बारे में मेरा सरकार से यह निवेदन हे कि किसानों को यह राहत देनी चाहिए कि जब कोओपरेटिव बैंक्स से किसान को कर्जा लेने के लिए कोई स्टेम्प ड्यूटी नहीं है तो नेशनेलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स से भी किसान को कर्जा लेने के लिए स्टैम्प ड् यूटी नही होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर परिसीमन के बाद जो नये–नये विधान समा क्षेत्र बने हैं हमारे माननीय विधायक उन नये परिसीमन क्षेत्रों के मुताबिक ही उन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हें तथा जो इलाके उनके क्षेत्रों से परिसीमन के बाद निकल गए हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार हरियाणा के अंदर जो भी नये विधान सभा क्षेत्र परिसीमन के अंदाज से नये बने हैं उनके लिए जितने तरक्की के काम हो सकें उतने करने चाहिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। सरकार चाहे तो इसके लिए कोई कमेटी बना दे या माननीय विधायकों को तरक्की के कामों के लिए ठीक

तरह से राहत दे। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में इरीगेशन के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की गयी है। मैं आपकी मार्फत इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला फरीदाबाद, जिला पलवल, जिला गुड़गांव और जिला मेवात के लोगों को पर्याप्त मात्रा में खेती का पानी उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार को यमुना के०पर एक बैराज बनाना चाहिए। अगर इस तरह का बैराज बन जाता है तो इन चार जिलों के लोगों को बारिश के समय में फसलों के लिए पानी मिलेगा और जब वह पानी नहरों और नालों में चलेगा तो धरती के अंदर जो खारा पानी हे वह भी मीठा हो जाएगा इसलिए इन चार के चार जिलों का बहुत भला हो सकता है। स्पीकर साहब, बजट में दूध उत्पादन की बात भी कही गयी है। वित्त मंत्री जी ने दूध के उत्पादन में हरियाणा को नम्बर एक बनाने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वही हरियाणा है जिसके बारे में देश के अंदर जाना जाता है कि ' देशा में देश हरियाणा जहां दूध दहीं का खाणा।'' अगर हम पूरे देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करते हैं तो हरियाणा के शहरों में हम अच्छी क्वालिटी का दूध क्यों नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। आज हरियाणा के छोटे शहरों में नकली दूध सप्लाई किया जाता हे। सरकार को इसके०पर भी विचार करना चाहिए। जो डेयरी मिल को दूध दिया जाता है वह उनको नहीं दिया जाना चाहिए या फिर उनसे वह वापस ले लिया जाना चाहिए ताकि शहरों में हर आदमी को अच्छी किस्म का दूध मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में सीवरेज के बारे में भी

जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि यमुना ऐक्शन प्लान के तहत हरियाणा में जितने भी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगे हैं उनका अगर वे खुद निरीक्षण करें तो वह मात्र कहने को ही सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट हैं लेकिन असल में उनमें पानी का कोई ट्रीटमैंट नहीं होता है। उनका जो गंद है वह निकालकर खुले में जो तालाब बनाए होते हैं उनमें ही डाल दिया जाता है। वह पानी वहां पड़े–पड़े सूखता रहता है और उससे बहुत दुर्गन्ध आती है जिससे आस–पड़ोस के गांव में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत नुकसान होता है। आज तो दुनिया में सीवरेज ट्रीटमैंट की इतनी अच्छी–अच्छी तकनीक हैं तो क्यों नहीं विदेशों से वह तकनीक यहां लाकर लगाई जाती हैं जिससे पानी का ट्रीटमैंट अत्याधुनिक तरीके से किया जा सके। जो पुराने ट्रीटमैंट प्लांट लगे हुए हैं उनको भी बदलकर या हटाकर नयी तकनीक के सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाए जाएं ताकि पानी इतना साफ हो कि वह पानी खेतों में सिंचाई के लिए काम में लाया जा सके और शहरों में जो गंदगी बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जा सके।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप इस बारे में लिखकर भिजवा देना।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मैं पांच मिनट का समय और लूंगा। मेरे कुछ सुझाव हैं। कर्मचारियों को एल०टी०सी० की सुविधा जो आपने दी है यह एक सराहनीय काम है। मैं

निवेदन करता हूं कि यदि हमारे कोई कर्मचारी भाई एल०टी०सी० पर विदेशों में जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने कार्यालयों से एन०ओ०सी लेनी पड़ती है, वे दरख्वास्त लगाते हैं। उनको महीनों तक एन०ओ०सी० लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह उदारता दिखानी चाहिए कि अगर हमारे कोई कर्मचारी अपनी एल०टी०सी० की सुविधा का लाभ उठाते हुए विदेशों में जाना चाहें तो उन्हें अपने विभागों से नो आब्जैक्शन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यह जो नरेगा की स्कीम है यह भी बहुत अच्छी है लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोग इस नरेगा की स्कीम के तहत काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे प्रदेश के गांवों में विकास कराने के लिए वे इस नरेगा स्कीम के बारे में भारत सरकार से बात करें कि हरियाणा में मशीनों की मार्फत काम करके लोगों का भला होता है तो उसके लिए नरेगा की स्कीम से हरियाणा सरकार को पैसा मिलना चाहिए। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां मेवात और अहीरवाल के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों को नसे। स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका लाभ लेने के लिए इसमें हमें अमैंडमैंट करानी चाहिए। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में व्याह–शादियों में जो डी०जे० बजते हैं यह काफी बेहूदगी और बदतमीजी व्याह–शादियों के नाम से होती है। इससे लोग परेशान होते हैं। इस डी०जे० पर अंकुश लगाने के लिए भी कानून बनना चाहिए। इस तरह से डी०जे० बजाने की लोगों को इजाजत नहीं होनी

चाहिएं इससे पढ़ने वाले बच्चें को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को और ज्यादा पावर्ज देनी चाहिए। हर काम हरियाणा की विधान सभा नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, अभी इसके लिए पंचायतों को पॉवर्ज दे दी हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः वे तो पूरी नहीं हैं, हमारी सरकार को पंचायतों को और पॉवर्ज देनी चाहिए जिससे कि वे गांवों में बैठकर खुद फैसले करें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कैंसर और टी०बी० की बीमारी बढ़ रही है।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, क्या आपने इस बारे में अपनी ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में सजैस्ट किया है? उसमें आप ये सुझाव दे देना।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, वह तो मैं जब समय आएगा तब अलग से दे ही दूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कैंसर और टी०बी० की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन्होंने जैसे रोहतक में पंडित भगवत दयाल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट और जो मैडीकल कालेज है उसमें हर तरीके से धन दिया है लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश के कैंसर और टी०बी० से

ग्रस्त मरीज दिल्ली में धक्के खाते फिरते हैं मैं चाहता हूं कि कैंसर रिसर्च इंस्टीच्यूड की कोई न कोई ब्रांच हरियाणा प्रदेश में अवश्य खुलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि दीन बंधु सर छोटू राम के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया। उसका नाम यदि आप पढ़ें, वित्त मंत्री जी को इस बारे में पता होगा।

श्री अध्यक्षः यह बात आ चुकी है और उसमें जरूरी अमैंडमैंट की जा रही है। श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, उसमें नाम के बीच में हाइफन है। मेरा निवेदन है कि दीनबंधु एक ही शब्द में लाने के लिए यदि अमैंडमैंट लाने की जरूरत हो तो अमैंडमैंट लायें अगर बिना अमैंडमैंट के काम चल सकता है तो उसे इनको करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए इतना समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी दो बातें और हैं। हरियाणा प्रदेश में जो इतनी ज्यादा शिक्षा संस्थायें बनाई जा रही हैं। यह एक बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब समय आ गया है कि हम इन स्कूलों और संस्थाओं में अपने हरियाणा के बच्चों को विदेशी भाषाओं की जानकारी भी दें और अत्याधुनिक डिप्लोमा कोर्सिज चलाएं। अध्यक्ष महोदय मैं जर्मनी गया था। जो मैंने वहां देखा उसके हिसाब से हमारे यहां इतने काम की गुंजाइश है कि कहा नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, जर्मन लैंग्वेज ऐसी है जिसे हर कोई नहीं बोल सकता। हमारे यहां अंग्रेजी सीखने की होड़ है

लेकिन जर्मन लैंग्वेज हर कोई नहीं बोल सकता। इसी तरह चीन में भी और फांस में भी जर्मन लैंग्वेज है। अध्यक्ष महोदय, आप भी विदेशों में होकर आए हैं। अगर हम हरियाणा के सभी शिक्षण संस्थानों में विदेशी भाषाओं में डिप्लोमा कोर्सिज और डिग्री कोर्सिज करायेंगे तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छे रोजगार मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जो शहर०ंचाई पर बसे हुए हैं जिनमें रोहतक, सोनीपत, हमारा पलवल शहर, जीन्द, दूसरे बड़े शहर और जिले हैं जो पुराने समय में०ंचाई पर बस गये थे उनमें सीवर और पानी के पाईप फट जाते हैं। पानी उन पुराने मकानों में बैठने लगता है और मकान फटने शुरू हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे कोई ऐसी स्कीम शहरों के लिए जारी करें जिसके तहत०ंचाई पर बसे हुए शहरों में जो लोग बसे हैं उनको रियायती दरों पर नई जमीन आबंटित की जा सके। जो हरियाणा इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बनाया गया है वह उस जमीन को टेक ओवर करे और वहां पुराने शहरों को खाली कराकर उनका डिवैल्पमैंट किया जाए और वहां नये आधुनिक शहर बसाए जाए। जो०ंचाई पर बसे हुए दुखी लोग हैं इससे उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी ओं

श्री अध्यक्षः ठीक है दलाल साहब, thank you very much.

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आखरी सुझाव है। सरकार ने काफी राहत गरीब लोगों को दी है लेकिन

अब समय आ गया है कि हरियाणा के गांवों में जो गरीब व्यक्ति हैं चाहे हरिजन या बैकवर्ड या दूसरे हमारे भाई हैं उनके लिए जरूरी है कि 'सभी घेरों में लैट्रीन बनाई जाए क्योंकि गांवों को निर्मल बनाने के लिए गांवों से गन्दगी को समाप्त करना होगा।

श्री अध्यक्षः ठीक है दलाल साहब, आप जो सुझाव दे रहे हैं ये सुझाव पहले भी आ चुके हैं। आप बार–बार रिपीट न करें। अब आप बैठ जाइये thank you very much.

श्री कर्ण सिंह दलालः सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

प्रो० छत्तरपाल सिंह (विघ्न): स्पीकर सर, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी द्वारा रखे बजट पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं 'आपका धन्यवाद करता हूं। चुनी हुई सरकार अपने प्रान्त के रिसोर्सिज से किस प्रकार से पैसे इकट्ठे कर सकती है, किस प्रकार की प्रायोरिटीज प्रान्त की है कहां परं कौन सा पैसा सरकार खर्च कर सकती है।

श्री अध्यक्षः छत्तरपाल जी, आप दस मिनट में कन्कल्यूड कीजिए।

प्रो० छत्तरपाल सिंहः स्पीकर सर, हमारे प्रदेश की रिक्यायरमैंट क्या हैं और क्या प्रायोरिटीज हैं उसकी रूपरेखा हमारी कोई भी चुनी हुई सरकार तय करती है। स्पीकर सर, आज पूरे हरियाणा प्रान्त में एक सन्तोष का विषय है। एक मैनेजर

जिसको पहले हमारी जनता ने सुनकर भेजा था उसका उदाहरण दोबारा से रिपीट न हो, इस बात के लिए हरियाणा की जनता आज समझती है।

बैठक का समय बढाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for 30 minutes ?

Volces: Yes Sir.

Mr. Speaker: The time of the Sitting of the House is extended for 30 minutes.

वर्ष 2009–10 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

प्रो० छत्तरपाल सिंहः स्पीकर सर, जब आप आधा घण्य समय बढा रहे हैं फिर तो मुझे बोलने के लिए पूरा समय मिल जायेगा। स्पीकर सर, वह उदाहरण रिपीट न हो यह हरियाणा की जनता आज सोचती है। आज वित्त मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने हरियाणा का बजट मैनेज किया है।

श्री अध्यक्षः बजट मैनेज नहीं किया बल्कि प्रजैण्ट किया है।

14.00 बजे

प्रो० छत्तरपाल सिंहः स्पीकर सर, पहले हमारी रिक्वायरमैंट क्या है, क्या रिसोर्सिज हैं इस सब की मैनेजमैंट करने

के बाद ही बजट पेश किया जाता है। मैं इस बात के लिए उन की तारीफ करता हूं कि उनका मैनेजमैंट बहुत अच्छा है। पांचवां बजट वित्त मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने सदन में रखा है। अभी अपोजीशन के भाइयों की तरफ से ये बजट भाषण आये थे कि ये तो सिर्फ घोषणाएं हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का बजट में प्रावधान नहीं है। स्पीकर सर, जो पिक्के चुनाव हुए उस समय पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने बुढ़ापा पैंशन को 200 रुपये से 300 रुपये करने की घोषणा ही की थी वह कोई बजट मैनेजमैंट नहीं था। आज मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की हैं वे सारी बजट प्रावधान में निहित रहेंगी। हमारी सरकार उन घोषणाओं को पूर्ण रूप से इम्पलीमैंट करेगी। यदि इनकी सरकार को यह आभास रहा होता कि आने वाली टर्म में ये इसको रिपीट कर रहे हैं तो ये इस पैंशन को 200 रुपये से 300 रुपये करने वाले नहीं थे। इनको पता था कि भुगतेगा कोई और इसलिए ये घोषणाएं करके चले गए थे। आज मुख्यमंत्री महोदय ने in the interest of social justice जो फैसले किए हैं वह काबिले तारीफ हैं। आज चाहे मैम्बर पंचायत हैं, चाहे सरपचिज हैं चाहे हैंडीकैप्ड हैं या बेरोजगार लोग हैं या विडोज हैं उनके लिए रिक्वायरमैंट है कि उनको फाइनैंशियल असिसटैंस मिले। एक तरफ हरियाणा सरकार ने जब 6वें पे कमीशन का प्रावधान किया उस वक्त बुजुर्गो के, हैंडीकैप्ड के, बेरोजगारों के जहन के अंदर यह सवाल था कि हरियाणा सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी या नहीं। जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय ने धोषणाएं की उसके बाद हर गांव के अंदर

चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री तो ये हैं जिनके पास कोई मांग नहीं थी, कोई रोला नहीं था, कोई प्रैशर नहीं था। फिर भी जो ठीक समझ में आया उसको लागू करके उन्हींने उसकी घोषणा की। यह बात नीति और नीयत में फर्क की है, व्यक्तित्व में फर्क की है और संस्कारों के फर्क की है। मुख्यमंत्री जी फ्रीडम फाइटर परिवार से जुड़े हुए हैं, संस्कारी परिवार से जुड़े हुए हैं, सच्चाई के साथ राजनीति करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी की आइडोलोजी से जुड़े हुए हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। राजनैतिक पार्टी ओर राजनैतिक मतदाता के बीच विश्वास मजबूत हो यह हमारी पार्टी का हमेशा ध्येय रहा है और यह बात हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने साबित करके दिखायी है। जो घोषणाएं नहीं की गई थी, हरियाणा की जनता को वोटों के लिए जो सब्जबाग हमने नहीं दिखाए थे और जो लालच हमने लोगों को नहीं दिखाए थे उससे भी आगे बढ़कर सरकार द्वारा क्लम उठाए गए हैं जिनमें 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए गए, कोपरेटिव बैंकों के ब्याज माफ किए गए फार्मर्ज के कर्जे भारत सरकार ने माफ किए। अव ये सारी घोषणाएं इस बात को सावित करती हैं कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह जी की सरकार ने ये सारी घोषणाएं लोगों के वोट अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपसी विश्वास को मजबूत करने के लिए की हैं। जनता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक नेताओं से उम्मीद रखती हैं कि ये हमारे सबसे बड़े खैर खवा हैं, ये हमारे सबसे बड़े वैलविशर हैं जो हमें किसी

भी गलत तरीके से बचाएंगें और एक अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। सरकारी रिसोर्सिज का फायदा उन्हीं लोगों को देंगे जो उसके पात्र होंगे। यह बजट इस बात का बहुत बड़ा परिचायक है। यहां बहुत अच्छे–अच्छे सुझाव आए हैं जोकि वैल्यूएबल भी हैं। यह निश्चित तौर पर सही है कि अच्छे समाज, अच्छे प्रांत और अच्छे देश के लिए अच्छी एजुकेशन की जरूरत है और अच्छी हैल्थ की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, यह किस प्रकार से सुनिश्चित हो सक्ता है इसको इस बजट में प्रायरिटी पर लिया गया है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और इस बात को इस बजट में सुनिश्चित किया गया है। इस प्रांत में जो लैंड होल्लिग्ज हैं उनकी वैल्यू किस प्रकार से सुनिश्चित की जा सकी है, उसकी जो प्रोडैक्शन है उसको कैसे वढ़ाया जा सक्ता है, उसका जो इन्फ्रास्टक्चर है उसको कैसे बैटर बनाया जा सकता है, इस बात पर हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। किसान की आर्थिक हालत बैटर होती है तो पूरा देश खुशहाली की तरफ बढ़ता है। सरकार के वर्तमान बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि देहात में, शहर में जहां हमें अच्छी हैल्थ की आवश्यक्ता है, अच्छी शिक्षा की आवश्यकता रहती है वहीं हमारे पास स्पोर्टस के साधन भी अच्छे होने चाहिएं ताकि हम हाइजैनिक कंडीशन में रह सकें। जो सी०सी० रोड्स और पेवमैंट ऑफ स्ट्रीटस के काम किए गए हैं वे बहुत सराहनीय हैं। अध्यक्ष महोदय, तालाबों का अक्स प्रावधान रखा गया है ताकि पशु साफ पानी पी सकें और गंदे पानी का डिस्पोजल अच्छे तरीके से किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, गांव

की हालत अच्छी हो ताकि किसान अपना रहन–सहन अच्छा कर सकें। इसका प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्यूंसी ओर स्टेट से रिलेटिड मेरे कुछ सुझाव हैं। यहां नरेगा से मुखतलक कई चर्चाएं हुई हैं। यह ठीक है कि नरेगा स्कीम के तहत हमारे पास बहुत पैसा है और इसका परपज यह है कि हम उन लोगों को रोजगार दे सकें जो शिक्षित नहीं हैं, लेबर क्लास से जुड़े हुए हैं और जिनके पास आजीविका के साधन नहीं हैं ताकि वे मजदूरी कर सकें। यदि हम मशीनों की तरफ जाते हैं तो इस स्कीम का परपज डिफिट होता है। स्पीकर सर, यदि मशीनों के०पर निर्भर करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस बारे में जो गाईडलाइंज हमारे सामने आई हुई हैं उनको फोलो करते हुए जो हमारे गांव के प्रोजैक्ट हैं उनको पूरा करने में डिफीक्लटीज आती हैं। हमारे किसान के पास रहेडू गड्डी है,०ंट रेहडा है। इसके अतिरिक्त हमारी कुछ बिरादरिया गधे–घोड़ों का भी काम करती हैं। आज जब हम आक और पंचायत डिवैल्पमैंट आफिस में इस बारे में चर्चा करते हैं तो वहां पर वे अधिकारी कैन्कूलेशन तक नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो इंजीनियरिंग विभाग है उसको इन गाईडलाईज के मुताबिक मोटीवेट करना चाहिए क्योंकि इन गाईडलाइंज में विद्यमान है कि किस प्रकार से रेहडा, रहेडू गड्डी और गधे–घोड़ों का इस्तेमाल गांव के प्रोजैक्ट्स को सिरे लगाने में किया जा सकता है। उसमें वाल्यूम ऑफ मिट्टी किननी होगी, उसके अंदर लेबर क्तिनी इन्वोल्व होगी इस तरह की कैल्कूलेशन ब्लॉक लैवल के

अधिकारियों के पास नहीं हैं जिसकी वजह से वे इन प्रोजैक्ट्स को सिरे लगाने में डिफीक्लीटीज महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं स्पीकर सर, आपके माध्यम से इस ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस तरफ वे पूरी तव्वजो भी देंगे। स्पीकर सर, हमारे प्रदेश में जो तालाब हैं जिनके बारे में क्त मान साहव भी जिक्र कर रहे थे कि तालाबों के ठेके मछली पालन के लिए दे दिए जाते हैं और उनमें इस प्रकार के सीड डाल दिए जाते हैं जिनसे पानी खराब हो जाता है और जिसके कारण पशुओं को भी नुकसान होता है। यह बात आज सोचने की है क्योंकि हम उसी पशु का दूध भी इस्तेमाल करते हैं। गंदा पानी हमारे पशु पीते हैं जिसका असर दूध पर भी पड़ता है। स्पीकर सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पशु जिस प्रकार को खान–पान करता है उसके गुण उसके दूध में भी विधमान होते हैं। जिस प्रकार से पैस्टीसाईड्स या दूसरी दवाईयां डालकर हम खाद्यान्न या सब्जियां पैदा करते' हैं उनका असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है उसी प्रकार से बदबूदार पानी पीने से पशुओं के दूध परं भी असर पडता है इसलिए आज इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि गांव में जो तालाब हैं उनमें स्वच्छ पानी पशुओं के लिए किस प्रकार से रह सके। इसके अतिरिक्त जो गंदा पानी है वह ड्रेनेज के भू निकाला जाये और उसका इस्तेमाल खेतों में खाद के रूप में किया जाए। इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि निर्मल बस्ती योजना के तहत, एच०आर०डी०एफ० और दूसरी स्कीम के तहत जो गलियां बनाई जाती है उनके साथ–साथ

नालियों का समुचित प्रावधान होना चाहिए ताकि गलियों में गंदा पानी खड़ा न हो सके।

अध्यक्ष महोदय, किसान की खेती को बेहतर करने के लिए मैंने पहले भी अपने जिले के मुतल्लक बहुत सी बातें यहां उठाई हैं। मैं आज भी कहना चाहूंगा कि पहले भिवानी को एक सिवानी फीडर से पानी मिलता था। उसको रिस्टोर करने की आवश्यकता है। ताजेवाला हैड से हांसी ब्रांच के लिए जो पानी लेते हैं इसरो हांसी हल्के में, बवानी खेड़ा हल्के में, सिवानी के कुछ हिस्सों में और मेरे हल्का धिराय के कुछ हिस्सों में जो यमुना सिस्टम से फीड होता है उसको उससे बहुत फायदा मिल सकता है। सिंचाई मंत्री जी इस बात को एप्रीशियट करेंगे कि जो भाखडा के सिस्टम से हमने भिवानी को पानी देना शुरू किया है वह सिवानी फीडर को अबनडन करके ही दिया है। सिंचाई विभाग ने क्त परसों ही अब यह स्कीम शायद चेंज कर दी है। अब वे 16 दिन के बजाये 21, दिन बाद 8 दिन पानी देने वाले हैं। मैंने पहले भी प्वायंट आऊट किया था कि खन्नौरी हैड से जो बी०एम०एल० से नरवाना ब्रांच डाकल फाल पर जाती है उसकी कैपेसिटी 1700 क्यूसिक के करीब है। आप जब उसमें 1700 क्यूसिक पानी नहीं चला पा रहे तो 16 दिन तक पानी हिसार जिले में किस प्रकार पहुचा पायेंगे? सिकनी फीडर को आलटरनेट डेज पर बालसमंद सब–ब्रांच से पानी दिया हुआ है वह कैसे पहुंचा पायेंगे? इस बारे में मंत्री जी को सीरियसली सोचने की आवश्यकता है ताकि

भाखड़ा में पानी की अवेलेबलिटी को देखते हुए हमें महीने में 1 छ दिन पानी मिल सके और यमुना के सिस्टम से उन इलाकों में पूरा पानी जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त सिंचाई से संबंधित कुछ दिक्कते मेरे हल्के में और हें जिनके बारे में बताना चाहूंगा। मैंने पहले भी मोठ माईनर की एक्सटैंशन की बात की थी इसलिए उसको एक्सपीडाईट करवाया जाये ताकि डाटा, सिसाय, गऊशाला के एरियाज में फायदा हो सके। इसके अतिरिक्त बालसमंद सब–ब्रांच की बुर्जी नं० 2700 से ले करके कुर्सी नं० 8500 तक खरकडी खुलाषा जो माईनर है उसके अंडर एक स्कीम अंडर प्रोसैस है उसको भी मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जल्दी बनवायें। लाठवा और न्यू लाठवा माईनर की एक स्कीम भी प्रोसैस में है उसको भी मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जल्दी पूरी करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त में आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पावटा डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल फरीदपुर गांव में पड़ती है और फरीदपुर मेरा अपना गांव है। पिछली सरकारों ने हमारी नहर में गड़बड़ी करके हमारे इलाके को दिक्कत में डाल दिया था। स्पीकर सर, जो फरीदपुर टेल बनाई गई थी वह 8– 10 साल के अन्दर ही सारी की सारी टूट चुकी है, रिस चुकी है। स्पीकर सर, इस टेल की जो अलाईनमैंट थी वह भी बहुत ज्यादा गलत थी इसलिए उसको आज दोबारा से रिमॉडल करने की जरूरत है और इसके साथ–साथ इसकी सीपेज को भी रोकने की सख्त जरूरत है। वर्तमान समय में जो अधिकारी हैं वे यह कहते हैं कि अगर हम इस केस को मूव करते हैं तो पिल्ले अधिकारी मुसीबत में फंस

जायेंगे जिन्होंने यह गलती कर रखी है। उनको बचाने के लिए ही केस मूव नहीं हो रहा है। स्पीकर सर, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि गलती करने वाले अधिकारियों को बचाने की कीमत फार्मर्ज को चुकानी पड़ रही है और वह निरन्तर पीड़ित हो रहे हैं। स्पीकर सर, इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर 9 इंच के खालों की बात भी इसीलिए आई है क्योंकि जो इरीगेशन डिपार्टमैंट का इंजीनियरिंग विंग है वह लाईनिंग में जानबूझकर कहीं न कहीं खामियां छोड़ देता है। स्पीकर सर, इससे हमारे फार्मर्ज को बड़ी भारी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक विशेष बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गांव मसय्यड का रोहित भाकर नाम का एक लड़का अर्जुन अवार्डी है। यह अवार्ड उसे वर्ष 2005 में मिला था। स्पीकर सर, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने उसके नाम पर गांव मसय्यड को माडल विलेज बनाने की रिक्वैस्ट सरकार को भेजी थी लेकिन हमारी उस रिक्वैस्ट को आज तक मॉडल विलेज की फाईनल लिस्ट में शुमार नहीं किया गया है। इस गांव को माडल विलेज बनाने का केस अभी अण्डर प्रोसैस है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस गांव को जल्दी से जल्दी माडल विलेज डिक्लेयर करवाया जाये। स्पीकर सर, इसी प्रकार से एजुकेशन, एनीमल हसबैंडरी और स्पोर्टस से संबंधित अपने सुझाव मैं मंत्री जी को भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप भिजवा देना We will incorporate it in the proceedings.

Prof. Chhattar Pal Slngh: Thank you, Speaker Sit स्पीकर सर, इसके साथ ही में इस बजट को पास करने की सिफारिश करता हूं।Thank you, very much.

श्री साहिदा खान (तावडू): स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर वोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, बजट का अध्ययन करने पर मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हुआ कि इससे गरीव आदमी को कोई फायदा हुआ होगा। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं कृषि की बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं स्वयं भी किसान हूं। स्पीकर सर, सरकार द्वारा वर्ष 2अम 1० को भइसान–मजदूर वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। स्पीकर सर, जब यह तय हो जाता है कि क्सि।न की फसल इस रेट में ली जायेगी तौ उसे सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर सईद लिया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नही होता जिस प्रकार से बाजरे का ही उदाहरण लिया जाये। स्पीकर सर, बाजरे की जो बेकायदगी हुई उसके बारे में आपने भी इलैक्ट्रानिक मीडिया में सुना और अखबारों में पढ़ा होगा। इसके विरोध में किसानों द्वारा रोष प्रदर्शन भी किये गये और अधिकारियों को इस बारे में लाईन हाजिर भी किया गया। स्पीकर सर, जिस दिन हमारे बाजरे की खरीद एजेंसी द्वारा नहीं की गयी उस दिन अचानक बारिश हो गई। जब मैं मण्डी में गया तो मैंने एक किसान को देखा जो कि

अपने 3–4 मन बाजरे को बेचने के लिए मण्डी में आया हुआ था। बारिश आने पर जब उसका वह बाजरा वह गया तो उसकी आखों में आसू आ गये और वह वहीं पर बैठ गया। जब हमें डस घटना का पता चला तो हम उसे फौरन हास्पिटल में लेकर गये। स्पीकर सर, यह एक सत्य बात मैं आपको बता रहा हूं। हमने इस बारे में डी०एम०, रिवाड़ी से बात की तो डी०एम० ने कहा कि उसके पास समय नहीं है। फिर हमने एस०डी०एम० से सम्पर्क साधा तो एस०डी०एम० ने भी हमारी बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद हमने प्रदर्शन किया उसके बाद भी कसंर्ड एजेंसी ने बाजरे की खरीद 3–4 दिन बाद शुरू की। प्रदेश की सभी मण्डियों में किसानों का बाजरा एजेंसियों द्वारा अच्छी कीमत पर उस समय तक नहीं खरीदा गया जब तक कि किसानों द्वारा अपना बाजरा बेच नहीं दिया गया और आढ़तियों द्वारा खरीदकर अपने गोदामों में नहीं भर लिया गया। आढ़तियों द्वारा स्टॉक कर लिये जाने के बाद बाजरा 840 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान जब खाद लेने जाता है तो लाईन में लगने के बाद भी उसको दो दिनों बाद तक भी खाद नहीं मिलती तो फिर मजबूरन उसे 50–100 रुपये एडवांस में देकर ब्लैक में खाद लेनी पड़ती है। स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से हमेशा किसान का शोषण होता रहता है।

श्री अध्यक्षः साहिदा जी, जो आपकी यह किसानों से पैसा लेकर ब्लैक में खाद देने की बात है क्या आपने इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित रूप में दी है?

श्री साहिदा खानः स्पीकर सर, किसानों से ज्यादा पैसा लेकर ब्लैक में खाद देने की चर्चा तो पूरे प्रदेश में है।

श्री अध्यक्षः साहिदा जी, यह आम बात नहीं है, it is a serious matter. अगर इस प्रकार की कोई बात आपके नोटिस में आती है तो उसकी शिकायत आपको लिखकर करनी चाहिए।

श्री साहिदा खानः स्पीकर सर, इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसान जब कर्जा लेने जाता है तो उसको सही तरीके से कर्जा भी नहीं मिलता और उसको तरह–तरह से परेशाान किया जाता है। जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी और सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा बड़े गर्व से यह कहा जा रहा था कि किसान एक एकड़ जमीन गिरवी रखकर एक ट्रैक्टर के लिए लोन लेगा। स्पीकर सर, सिंचाई की बात भी पिछले 2–3 सैशनों से चली आ रही है और कहा जा रहा है कि मेवात में एक मेवात कैनाल बनाई जायेगी मंत्री जी बार–बार कह रहे थे कि हम इसका कुछ कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसकी अभी तक पैमाइश भी नहीं हुई है कि किस–किस जमीन पर यह नहर बनेगी?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि मेवात

कैनाल बनाने का सर्वे चल रहा है। हमारी कोशिश यह है कि अगले 3 महीने में यह सर्वे पूरा करके इसको बनाया जाये। पिछली सरकार ने तो इस बारे में कुछ भी काम नहीं करवाया था जबकि हमने तो मेवात कैनाल बनाने के लिए बजट में प्रावधान भी किया है।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, हमारे मेवात के और भी साथी बैठे हैं सबको पता हे कि गुडगांव कैनाल कें नाम से वहां पर जो नहर है उसमें पानी ही बहुत कम आता है और यदि पानी आता भी है तो वह भी गंदा ही आता है। यहां तक कि मेवात में लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे एरिया में दो जगह ऐसी हैं जहां. पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। इनमें से एक तो आरेज कहते हैं और दूसरी जगह को भयाना कहते हें। जो सोहना से नूह तक क्त एरिया है उसको आरेज कहते हैं और उससे आगे वाले एरिया को भयाना कब्जे हैं। आरेज और भयाना जो नाम हैं इन्हें हम अपनी भाषा में बोलते हैं। वहां पर हमने हजार–हजार फुट तक पानी निकालकर देख लिया लेकिन वहां पर कहीं पर भी पानी नहीं है। लोग पीने के लिए तो पानी तालाबों से ले लेंगे लेकिन अगर नहर में पानी ही नहीं आयेगा तो तालाब कैसे मरेंगे? अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि आदमी पीने का पानी तो किसी भी तरह से जैसे कैनी से या बाल्टी से ला सकता है लेकिन जब वश पर पानी ही नहीं होगा तो लोग कहां से पानी लायेंगे? आपको भी पता है

कि पानी की वहां पर बहुत दिक्कत है पिछली सरकार में तो वहां पर नहरों से जोहड़ भरे गये थे। अध्यक्ष महोदय, इतना काम इस सरकार ने जरूर किया है कि जो रैनीवैल प्रोजैक्ट था उसको अब राजीव गांधी पेयजल योजना के नाम से बदल दिया गया है। 9 जुलाई को गवर्नर हाउस में एम०डीज्वी० की मीटिंग हुई थी उसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी भी थे। उसमें सिंचाई विभाग के कमिश्नर ने कहा कि हम 1 सितम्बर, को रैनीवैल प्रोजैक्ट का पानी दे देंगे। उस समय मैंने उनको कहा कि आप यह कैसे दे सकते हो क्योंकि अभी तक तो इसकी लाईन की खुदाई भी नहीं हुई है? आप तो अगले साल तक भी पानी नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, आज तक उस प्रोजैक्ट का भी कोई अता–पता नहीं है कि उसमें क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, कोटला झील की भी उस मीटिंग में चर्चा हुई थी। लगातार यह कहा जाता रहा है कि हम इसको यमुना के पानी से बरसात के दिनों में भरेंगे। मेवात का एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जिसको कोटला झील कहा जाता है। हमारे मेवात के दूसरे माननीय साथियों को भी इस बात का पता है कि वह 15–20 किलोमीटर का एरिया है, वह झील हमेशा ही बरसात में पानी से भरती रही है। लेकिन अब बरसात कम होने के कारण वह नहीं भरी जाती। यदि उसमें सिंचाई और पीने का पानी यमुना से लाया जाये तो मैं समझता हूं इससे मेवात के एरियाज में काफी सुधार हो सक्ता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। आजकल बिजली के बारे में बहुत बड़ी चर्चा है कि आज प्रदेश में बहुत थर्मल प्लांट लग रहे हैं और बिजली के

इतने प्रोजैक्ट होंगे, इतनी बिजली पैदा होगी कि हम दूसरे प्रदेशों में भी बेचेंगे। आज के दिन सरकार का बिजली देने का शिडयूल सिर्फ पांच घण्टे का है। किसानों को आज केवल पांच घण्टे ही बिजली मिलती है। जो छोटे शहर और कस्वे हैं उनमें भी इसी हिसाब से बिजली मिलती है और बड़े बड़े बिजली के कट्स लगते हैं। मेरे कहने का मतलब यह हे कि बिजली का उत्पादन यदि दुगना–तिगुना भी किया जाए तो भी सिर्फ 10 से 15 घण्टे से ज्यादा बिजली लोगों को नहीं मिल सकती है। आज तो फीडरों पर भी कट लगते हैं। सरकार ने जो अधिकारी वहां पर बिठा रखे हैं उनमें सबसे अधिक दिफ्ल तो यह है कि वहा, पर एस०डीभ्योज० ही नहीं हैं। जेर्थ्य० या जूनियर लोग ही वहां बिठा रखे हैं जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाते हैं। जब कोई ट्रांसफार्मर बदलना होता है तो वे लोग लगातार 15– 15, 20–20 दिन और महीने भर तक ट्रांसफारमर्ज को नहीं बदलते हैं। जब तक दो–तीन हजार रुपये रिश्वत के रूप में उन्हें नहीं मिल जाते तब तक वे ट्रांसफारमर को नहीं बदलते। स्पीकर सर, इस प्रकार की कई–कई बेकायदगियाँ हो रही हैं। अब मैं मेवात के अन्दर कानून–व्यवस्था की हालत के बारे में मैं बात करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः साहिदा जी, प्लीज आप अब कन्क्रलूड करें। आपने पांच मिनट के लिए लिखा था लेकिन आपको बोलते हुए

आठ मिनट हो गए हैं इसलिए अब आप दो मिनट में कंकलूड करें।

श्री साहिदा खानः स्पीकर सर, मेवात में जो पुलिस वाला मामला है मैं उस पर अपनी बात कहना चाहता हूं वहां की पुलिस ने मेवात को इतना बदनाम कर दिया है कि जब हम लोग बाहर जाते हे तो हमें बुरी नजर से देखा जाता है (विघन) बोर्ड तो हटा दिये हैं लेकिन पीछे किसी चौकी इन्वार्ज ने फायर किया और उसके सामने डॉक्टर. की दुकान के क्लीनिक में दो आदमी बैठे थे उनको गोली के छर्रे लगे। उन दो आदमियों को पुलिस की गोली छर्रे लगने के बावजूद उन्हीं आदमियों पर उल्टा केस दर्ज कर दिया गया। इसी तरह से नगावड गांव में पुलिस की रेड डाली गई थी। स्पीकर सैर, मैं यह ऐडमिट करता हूं कि यह गांव कोई बहुत बढ़िया गांव नहीं है। पुलिस को यहां पर कोई अडोसी–पडोसी तो मिला नहीं लेकिन एक लड़की मिल गई। नवीन सहगल नाम का वहां जो डी०एस०पी० है उसने फायर किया जिसके कारण उस लड़की की जाम में गोली का छर्रा लग गया। स्पीकर साहब, उल्टे उसी लड़की पर केस दर्ज कर दिया गया और आज वह लड़की भौंडसी जेल में है। दूसरे हमारा एक अहलाल पुर गांव हे उसमें एक व्यक्ति को पुलिस वाले कहने लगे कि उसने चोरी का ट्रक ले लिया है। हो सक्ता है कि उसने चोरी की हो। मैं मानता हूं कि वह व्यक्ति बदमाश था लेकिन उसके ट्रक का नश्वर दूसरा था। वहां पर सी०आई०ए० का इन्सपैक्टर गांव में गया और

उस व्यक्ति से उसने पैसे मांगे लेकिन उस व्यक्ति ने पैसे देने से इन्कार कर दिया।

श्री अध्यक्षः साहिदा जी, आप क्या बात कह रहे हैं कि वह आदमी बदमाश था। गांव भी ठीक नहीं था फिर भी केस दर्ज हो गया यह सारा क्या मामला है?

श्री साहिदा खानः स्पीकर सर, मैं असलियत बता रहा हूं कि कानून–व्यवस्था की क्या स्थिति है। इस बारे में वहां पर महा–पंचायत भी हुई थी और आपने भी इसके बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। मेवात में इस बारे में कितनी ही पंचायतें हुई हैं। उसने वहां पर पुलिस को बुला लिया और वह आदमी किसी दूसरे के घर में घुस गया। पुलिस वालों ने 4–5 डिस्ट्रिक्ट से वहां पर पुलिस फोर्स लेकर फायर शुरू कर दिया। किसी के घर में शादी का सामान रखा हुआ था वह सामान भी पुलिस ने तोड–फोड़ दिया और मकान भी तोड़ दिये। जिन लोगों का नुकसान हुआ, उन लोगों की आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। स्पीकर सर, ऐसी जबरदस्ती कब तक चलेगी?

श्री अध्यक्षः साहिदा जी, ठीक है। आपको और जो क्य भी कहना है वह आप लिख कर भिजवा दीजिए। ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब तक 26 मैम्बर्ज गवर्नर ऐड्रैस पर बोल चुके हैं और 25–26 मैम्बर साहेबान बजट पर बोले हैं। बोलने के लिए जिन ऑनरेबल मैम्बर्ज की पर्चियां मेरे पास आई हैं उनमें श्री महेन्द्र प्रताप सिंह

जी, श्री राम कुमार गौतम जी, श्री नरेश यादव जी, मैडम अनीता यादव जी, पण्डित राधेश्याम शर्मा जी, डॉ० शिवशंकर भारद्वाज जी, श्री नरेश मलिक जी, श्री नरेश बादली जी, श्री सुखबीर सिंह फरमाणा जी, श्री अमीर चन्द जी मक्कड, डॉ० सुशील इन्दौरा जी, श्री एस०एल० बतरा जी को मैं कल बोलने का टाईम दूंगा ताकि सभी पांच–पांच सात–सात मिनट बोल सकें। मेजर नृपेन्द्र सिंह जी ने भी बोलना है लेकिन अभी तक उनकी पर्ची मेरे पास नहीं आई है। मेजर साहब को भी कल बुलवाएंगे। (विघन)

विधान कार्य

(1) दि पंजाब शिडयूल्ड रोडस एण्ड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2009 and will move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, **I** beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move -

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled

Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is -

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं यह प्रस्ताव करूं कि यह बिल पास किया जाए, मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए बताना

चाहूंगा कि पूरे राज्य भर में नगरपालिका का विस्तार हुआ और उसके बावजूद भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के court on its own motion के नोटिसिज आ गए थे कि 100 मीटर शैडयूल्ड रोड्ज पर और 30 मीटर जो स्टेट रोड्ज पर कंस्ट्रक्शन कर ली थी, लोगों ने घर बना लिये थे, छोटे–छोटे मकान, छोटी–छोटी दुकानों के माध्यम से व्यवसाय कर लिये थे उनको हटाया जाये। इसके कारण उन लोगों के सिर पर तलवार लटक रही थी और उन लोगों में एक चिन्ता का विषय बनी हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने इसे बड़ी ही गम्भीरता से लिया कई जगह तो मुख्यमंत्री जी के खुद के नोटिस में आया है, हमारी माननीय सदस्या सुमिता सिंह जी, चौधरी साहब और बहुत से दूसरे सदस्य भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में मिले थे। इनके अलावा और भी दूसरे लोग माननीय मुख्यमत्री जी से मिले थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में मंत्रिमंडल की बैठक में यह मुद्दा लाए थे और इस बारे में निर्णय लिया गया है कि हम एक बार में ही उन सबको रैगुलराईज करेंगे। हमने इन सब का सर्वे कर लिया है। मैं केवल आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि 53782 ऐसे परिवार हैं जिनको इस अमैंडमैंट से लाभ पहुंचेगा। इस वजह से उनके सिर पर जो उनकी उम्रभर के लिए रोजी–रोटी छिन जाने की तलवार लटक रही थी, वह हमेशा के लिए उनके सिर से हट जाएगी। With these words, Sir,

I beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that time of the sitting of the House be extended for another 10 minutes?

Voices: Yes, Yes.

Mr. Speaker: The time of the sitting of the House is extended for another 10 Minutes.

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(2) दि हरियाणा लैजिस्टेटिव असैम्बली स्पीर्क्ज एण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड एलाउसिज (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):

Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2009.

Sir, 1 also beg to move—

That The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए छठा पे कमीशन पूरे प्रदेश में और

सारे देश में लागू किया है तो हमारे सभी साथियों की भी इच्छा है और मेरी भी यह इच्छा है कि जिस हिसाव से... ...

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आप तो रिचौएस्ट मैंबर में आते हैं क्या आपकी भी लार टपक गयी है?

श्री नरेश मलिकः अध्यक्ष महोदय, ये सारे मैम्बर्ज मुझसे कहलवा रहे हैं इसलिए मैंने यह बात कही है।

श्री अध्यक्षः चलो ठीक है, आपकी फीलिंग कन्वे हो गयी है आप बैंठें। अब तो मूसलाधार बारिश होने लग रही है।

श्री नरेश मलिकः स्पीकर साहब, मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि मंत्रियों और सारे विधायकों की सैलेरीज और एलाउंसिज बढ़ा दिये जाने चाहिएं। इसके अलावा जो एक्स एम०एल०एज० हैं उनकी पैंशन भी बहुत कम है इसलिए एक्स एम०एल०एज० की पैंशन भी वहा दी जानी चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आपकी यह फरमाइश इंडीविजुअल है या आपकी पार्टी की तरफ से यह फरमाइश है?

श्री नरेश मलिकः सर, मैं तो सबकी तरफ से फरमाइश कर रहा हूं।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो बात कही है और एक सुझाव डॉक्टर

इंदौरा जी ने पीछे बैठे हुए दिया था। इन सबकी जो राय है उससे हम मुख्यमंत्री जी को, सदन के नेता को अवगत करवा देंगे। मुख्यमंत्री जी इस बारे में वित्त मंत्री जी से मंत्रणा कर लेंगे। हम जरूर कोशिश करेंगे कि इनकी यह बात सिरे चढ़ सके।

डॉ० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद): स्पीकर सर, जिस तरह से अब मंहगाई बड़ी है और जिस तरह से सरकार कह रही है कि हमने प्रदेश के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, माननीय सदस्य भी इसी प्रदेश के हिस्से हैं इसलिए उनकी जरूरत का अगर सरकार ध्यान रखती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए।

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(3) दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी शराइन (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will introduce the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minlster (ShriA.C. Chaudhary): Sir, **I** beg to introduce the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is -

That the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause be clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, सभी साथियों के सुझाव आएं हैं इसलिए हमने आपसे अनुरोध किया था कि कल 18.2.09 को दूसरी सीटिग में 20 फरवरी, 2009 का एजेंडा भी ले लिया जाए।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, is it the sense of the House that the agenda fixed for 20th February, 2009 be taken up on 18th February, 2009 in the second sitting of the House?

Voices: Yes, yes.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, there will be two sittings on 18th February, 2009. The first sitting will commence from 9.30 A.M. to 1.30 A.M. and the second sitting will commence from 2.00 P.M. till the conclusion of the business entered on the list of business fixed for the second sitting. There will be no Business Hour in the second sitting.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 18th February, 2009.

***14.36 Hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 18th February, 2009.)